हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 2007

खण्ड–1, अंक–4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 14 मार्च, 2007

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4)24
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)33
इण्डियन नैशनल लोकदल के सदस्यों के आचरण तथा व्यवहार की निन्दा करना ।	(4)40
ओलावृष्टि तथा भारी वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान सम्बन्धी मामला उठाना ।	(4)41
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान	(4)44
वर्ष 2006–07 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना ।	(4)76
एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।	(4)76
वर्ष 2006–2007 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।	(4)77

मूल्य : 100

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 14 मार्च, 2007

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डा. रघुबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker :- Hon'ble Members now Question Hour.

Providing 50% Reservation in Government Jobs for Ruralities

***579. Sh. Dharampal Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give 50% reservation to ruralities in Govt. service/ jobs :

(b) if so, whether there is any proposal to make it compulsory to these employees to serve for at least first half of their service period in rural areas ? and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to give some incentive to those Govt. employees who will be posted/ transferred in rural areas ?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

(a) No Sir. However, in Education Department 50% 'horizontal reservation' has been provided in direct recruitment in all the school teaching categories of posts i.e. Schools Lecturers, Masters, Classical & Vernacular Teachers and JBT Teachers to the rural youth who have passed their matriculation examination from a rural area school of Haryana.

(b) & (c) No, Sir,

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय अध्यक्ष जी, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति शहरों में होती है या शहर के करीब होती है उनको सिटी एलाउंस दिया जाता है यानी उनको यह प्रलोभन दिया जाता है। इसी कारण मुलाजिम यह कोशिश करते हैं कि उनकी पोस्टिंग शहर में हो। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनके लिए शहर में पोस्टिंग होना जरूरी है लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं जिनके लिए पोस्टिंग गांवों में की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह से सिटी एलाउंस शहरों में पोस्टिंग के लिए दिया जाता है तो क्या उसी प्रकार या उससे भी ज्यादा मात्रा में जिनकी गांवों में पोस्टिंग होगी, उनको भी कोई इन्सैंटिव या और कोई प्रलोभन देने का विचार सरकार के सामने विचाराधीन है ताकि लोगों का रूझान देहात की तरफ हो ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, सरकार इस बात को लेकर सजग है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा की सरकार का ग्रामीण अंचल से विशेष लगाव भी है, जुड़ाव भी है। माननीय सदस्य खुद भी एक काबिल वकील हैं इसलिए वे इस बारे में जानते हैं कि जो 50 परसैंट रिजर्वेशन हमने अध्यापकों के लिए की है उसको भी अदालत में चुनौती दी गयी है और माननीय उच्च न्यायालय ने हमें सिलैक्शन करके रिजल्ट अनाउंस न करने की अभी भी पाबंदी लगा रखी है इसकी वैधता का अदालत जो भी फैसला करेगी उसको हम मानेंगे। स्पीकर सर, जहां तक ग्रामीण अंचल में काम करने वाले व्यक्तियों का एक विशेष कॉडर बनाने की बात है मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह सर्विस कॉडर का सवाल है। हरियाणा में अर्बन और रूरल दो अलग अलग सर्विस कॉडर नहीं है केवल एक ही कॉडर है। लेकिन हमने जो अपनी ट्रांसफर पोलिसी 12 अप्रैल, 2006 को बनायी है उसमें ग्रामीण अंचल में कम्पलसरी पोस्टिंग का प्रावधान रखा गया है। मैं आपकी अनुमति से इनकी जानकारी के लिए इस बारे में पढ़कर सुनाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब भी पहली नियुक्ति होगी तो विद्यालय शिक्षा विभाग की विभागीय स्थानांतरण नीति दिनांक 12-4-2006 में निम्नलिखित प्रावधान है कि -

3. अ. सेवा नियमों के अनुसार सीधी भर्ती-नियमित तदर्थ आधार पर प्रथम नियुक्ति में उम्मीदवारों को प्रथम पांच वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा।

ख. सेवा नियमों के अनुसार प्रत्येक पदोन्नित पर प्राध्यापकों को तीन साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा। यद्यपि 50 परसैंट आरक्षण वाले ग्रामीण युवाओं के लिए पहले आधे वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने का विभाग का प्रस्ताव अभी नहीं है। ग्रामीण नियुक्ति के लिए प्रोत्साहन-वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए अभी कोई विशेष प्रोत्साहन का मामला विचाराधीन नहीं है। जैसा मैंने बताया कि हमने 50 प्रतिशत ग्रामीण रिजर्वेशन का पहली बार प्रावधान रखा है। आज तक किसी सरकार ने इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखा था। यह मामला अभी अदालत में चला गया है परन्तु हम कटिबद्ध हैं कि ग्रामीण अंचल से ज्यादा से ज्यादा युवा आगे आएं और ग्रामीण इलाकों की सेवा करें।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, आम तौर से यह देखा जाता है कि देहात में जितने गवर्नमैंट स्कूल है उनमें स्टूडैंट्स कम होते हैं और टीचर्स ज्यादा होते हैं और जो प्राइवेट लोग स्कूल खोल देते हैं उन स्कूलों में ज्यादा अटरैक्शन होता है। ग्रामीण अंचल में स्कूलों में कोई बिल्डिंग नहीं है, बच्चे दरखतों के नीचे पढ़ते हैं। बच्चों पर कंट्रोल करने वाला कोई होना चाहिए। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि कम से कम हर गांव में स्कूल का हैड मास्टर, गांव का पटवारी या गांव का ग्राम सेवक जिनका स्कूल चलाने में मेनफक्शन है उनकी रिहायश का वहां प्रबन्ध हो जिससे वे स्वयं भी सुविधा से रह सकें और लोगों को भी ज्यादा सुविधा दे सकें और बच्चों की पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान दे सकें।

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चंद मुलाना) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अभी जो प्रश्न किया उसमें एक तो यह कहा कि देहात में अध्यापक ज्यादा हैं और बच्चे कम हैं, यह बात ठीक नहीं है। हमारे देहात में बच्चे भी हैं और अध्यापक भी हैं। जहां जहां अध्यापकों की कमी थी वह हमने गैस्ट टीचर्ज लगाकर पूरी कर दी है। यह भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार की पहली मिसाल है। सारे देश में गैस्ट टीचर्ज का कहीं प्रावधान नहीं है। जहां तक रिहायश की सुविधा देने का सवाल है यह अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है कि शहरों में अध्यापक काफी हैं और गांवों में भी अध्यापक काफी हैं जबकि वास्तविकता यह है कि सरकार के भरसक प्रयास करने के बावजूद भी और गैस्ट टीचर्ज अप्वांयट करने के बावजूद भी हालांकि यह एक आरजी व्यवस्था है, स्कूलों में टीचर्स की अभी भी कमी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप काफी सीनियर आदमी हैं आप केवल क्वैशचन पूछें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि पूरे प्रयास करने के बावजूद भी टीचर्ज की कमी है और जो टीचर्स काम कर रहे हैं वे देहात में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि शहर में उनको हाउस रैंट व ट्यूशन आदि की भी सुविधा है और रिहायश में भी इंसैंटिव मौजूद हैं। इस समस्या का समाधान तभी होगा जब उनको रूरल अलाउंस दिया जाएगा। इसलिए इस पर फिर से गहराई से विचार करके उनको रूरल अलाउंस दिया जाए।

श्री फूल चंद मुलाना : माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर साहब ने बड़ी ही तफसील से बताया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि फर्स्ट अप्वायंटमैंट के समय उन पर पांच साल के लिए देहात के स्कूलों में रहने की बंदिश होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा आपको मालूम है कि हम लोग ही मुख्यमंत्री महोदय पर बार-बार दवाब डालते हैं कि इस अध्यापक को शहर में लगा दो। लेकिन सरकार इस बार बजिद है कि उन नियमों में ढील नहीं दी जाएगी। अब हमने स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को भी 12 हजार टीचर्ज की भर्ती की डिमांड भेजी है। लगभग 12 हजार अध्यापकों की भर्ती होने के बाद अध्यापकों की संख्या पूरी हो जाएगी। जहां तक रूरल अलाउंस की बात है उसका कोई प्रावधान नहीं है। हां, कोई और इंसैंटिव इस बारे में देने के लिए विचार किया जा सकता है।

श्री रामकुमार गौतम : स्पीकर सर, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इलाके पर मेहरबानी की है कि हिसार जिले में मेरे हल्के के दो स्कूलों को अपग्रेड किया है ये स्कूल एक तो थास गांव का और दूसरा नारनौंद का स्कूल है जो लड़कियों के स्कूल हैं इनको अपग्रेड करके प्लस टू के स्कूल किए हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि ये स्कूल तो अपग्रेड कर दिए लेकिन वहां पर न तो प्रिंसीपल और न ही स्टाफ आज तक लगाया गया है इस कारण वहां पर क्लासिज आज तक शुरू नहीं की जा सकी हैं।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, प्रिंसीपल तो इनकी सिफारिश पर ही लगाया था। क्या पता वह वापिस किसी और जगह पर बदली करवा गया हो। सभी स्कूलों के इन्चार्ज को सरकार ने यह छूट दे रखी है कि उनके स्कूल में अगर क्लास में पूरे बच्चे हैं और टीचर की वैकेंसी खाली है तो वहां पर वह इन्चार्ज गैस्ट टीचर लगा सकता है।

श्री रामकुमार गौतम : स्पीकर सर, मुलाना साहब ने मेरे कहने पर लड़कों के स्कूल में श्री आर०के० लोहान को प्रिंसीपल लगाया था जो बहुत ही काबिल प्रिंसीपल है और अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ये जो लड़कियों के स्कूल अपग्रेड किए हैं वहां पर आज तक प्रिंसीपल और टीचिंग स्टाफ नहीं लगाया गया है।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, वहां पर भी जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा कर देंगे।

श्रीमती अनिता यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार परमानैन्ट टीचर लगा लेगी तो जो गैस्ट टीचर्ज लगे हुए हैं जो बेरोजगार अध्यापक लगे हुए हैं क्या सरकार उनके लिए भी कोई प्रावधान करेगी।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, जो गैस्ट टीचर्ज लगे हुए हैं उन्होंने भी तो परमानैन्ट भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ है। हम तो कहते हैं कि वे सारे सिलैक्ट हो जायें। लेकिन आप जानते हैं कि गैस्ट तो गैस्ट ही होता है वह आखिर कितने दिन तक रूकेगा यह आपको पता है।

श्री सुखवीर सिंह जौनपुरिया : स्पीकर सर, सदन में रूरल एरिया की बात हो रही है। इसके बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि जब से सरकार ने गैस्ट टीचर लगाये हैं स्कूलों में पढ़ाई होनी शुरू हो गई है और आप जानते हैं कि जिनके पास पैसा होता है उनके बच्चे तो प्राईवेट स्कूलों में ही पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में तो उनके बच्चे ही पढ़ते हैं जिनके पास पैसे की कमी है। लेकिन माननीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने गैस्ट टीचर्स की व्यवस्था करके मेवात एरिया के 35,000 बच्चों के पढ़ाने का काम किया है जो आज तक पढ़ाई से वंचित थे।

प्रो० दिनेश कौशिक : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो टीचर्ज के लिए भर्ती का प्रोग्राम बनाया है उसमें यह शर्त लगाई है कि जो टीचर रूरल एरिया में लगाये जायेंगे उनको वहां पर पांच साल तक सर्विस करनी जरूरी है। क्या सरकार दूसरे विभागों के अधिकारियों के बारे में भी कोई ऐसी पोलिसी बनाने जा रही है क्योंकि हमारे रूरल एरिया में कोई भी अधिकारी नहीं रूकना चाहते, चाहे वे एस.डी.ओ.हो,बी०डी०ओ० हो या दूसरे अधिकारी, सभी शहरों की तरफ भागते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि उनका हैडक्वार्टर वहीं रूरल एरिया में हो।

श्री अध्यक्ष : आप भी तो कौशिक साहब अमेरिका जा रहे हो।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ग्रामीण अंचल के उन अधिकारियों की निश्चितता के बारे में मन्शा जाहिर की है इस बात को लेकर सरकार भी चिन्तित है और माननीय सदस्य स्पैस्फिक कोई केस बतायेंगे तो सरकार उसके बारे में जरूर दुरूस्त कदम उठायेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या 587

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री नरेश यादव इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Action taken against Doctors/Officials of P.H.C. Nangal Chaudhary

***593. Sh. Radhey Shyam Sharma Amar :** Will the Minister for Health be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the medicines of the Primary Health Centre, Nangal Chaudhary, Distt. Mahendergarh had been thrown into the river and gutter by the Doctors/Officials; and

(b) if so, what action has been taken or proposed to be taken against the said Doctors/Officials ?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहन करतार देवी) :

(क) हां श्रीमान जी।

(ख) एक औषधाकारक, एक बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष), एक चिकित्सा अधिकारी व एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध कर्तव्यहीनता के आरोप में अनुशासनिक कार्यवाही शुरु कर दी गई है।

स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि 12.9.2006 को माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में मैंने सदन का ध्यान दिलाया था कि इस बारे में जांच कराई जायेगी और दोषियों को सजा दी जायेगी। उसी आश्वासन को मद्देनजर रखते हुए उस मामले की पूरी जांच कराई गई है। उसमें एक फार्मेसिस्ट, एक एम०पी०एच०डब्ल्यू (मेल), एक एस०एम०ओ० और एक दूसरे डाक्टर जो वहां पर काम करता था इस काम में थे लैक ऑफ सुपरविजन के दोषी साबित किए गये हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, क्या यह सवाल आपने पहले भी पूछा था ?

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सैशन में यह सवाल पूछा था। जिन कर्मचारियों ने दवाईयां नदी तथा गटर में फैंक दी उनके खिलाफ दोष भी साबित हो गया है लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उसका परिणाम यह निकला कि नारनौल में जो एक्टिंग सी०एम०ओ० है वह सरकार को सूचना दिए बगैर वहां पर डेली वेजिज पर भर्ती कर रहा है और नारनौल होस्पिटल में इनैलो और बीजेपी के आदमियों को चीफ गैस्ट बुलाकर उद्घाटन करवाये जाते हैं। मेरी मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि जिन लोगों ने दवाईयों को गटर में फैंक दिया था उनके खिलाफ क्या अभी तक कोई कार्यवाही हुई है या नहीं ? यदि कोई कार्यवाही हुई है तो उसकी नोटिंग हमें यहां सदन में दिखाई जाये। (विघ्न)

बहन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमने कार्यवाही शुरू कर दी है। दो कर्मचारियों को अब तक सस्पैंड किया गया है और दो के खिलाफ कर्तव्यहीनता के आरोप में अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, 6 महीने से ऊपर का समय हो गया है लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ प्रोपर कार्यवाही नहीं हुई। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अनिता जी, प्लीज आप बैठें। मंत्री जी ने पूरा जवाब दे दिया है।

तारांकित प्रश्न संख्या-675

(इस समय माननीय सदस्य श्री राकेश कम्बोज सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।

तारांकित प्रश्न संख्या-598

(इस समय माननीय सदस्य डा० सुशील इंदौरा सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Regularization of Un-authorised Colonies in the State

***605 Sh. Mohender Partap Singh :** Will the Chief Minister be pleased to State : —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the unauthorized colonies in the State ; and

(b) if so, the details of colonies of Mewla Maharajpur area for which the resolution for regularization have been received by the Government from Faridabad, Municipal Corporation may be given?

शहरी विकास, राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) :

(क) हाँ, श्रीमान् जी,

(ख) नगर निगम फरीदाबाद ने मेवला महाराजपुर क्षेत्र की निम्नलिखित 22 कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव भेजा था : -

सरस्वती कॉलोनी, सूर्य बिहार-II, सूर्य बिहार-III, सरस्वती कॉलोनी-II, सरस्वती कॉलोनी-III,सूर्य बिहार-I (सेहतपुर की राजस्व सम्पदा), राव सुल्तान सिंह कॉलोनी, शिव कॉलोनी, पॉवर हाउस कॉलोनी (पल्ला की राजस्थ सम्पदा), शिव दुर्गा बिहार (लक्कड़पुर की राजस्व सम्पदा), ओम एनक्लेव, दीपाली एनक्लेव, पंचशील कालौनी (इस्माईलपुर की राजस्व सम्पदा), बासेल्वा कालौनी, भूर कॉलौनी, न्यू सईद वाड़ा, पटवारी कालौनी, पूर्ण एनक्लेव (फरीदाबाद की राजस्व सम्पदा),भारत कालौनी, इन्द्रा कम्पलैक्स (बासेल्वा की राजस्व सम्पदा), यादव कालौनी (सराय ख्वाजा की राजस्व सम्पदा), अग्वानपुर एक्सटैंशन (अग्वानपुर की राजस्व सम्पदा)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो अनएथोराईज्ड कालोनीज हैं इनको रैगुलर करने का सरकार का क्या क्राईटेरिया है और जो कालोनियां मेरे क्षेत्र में हैं जिनका यहां जिक्र किया गया है उनको कब तक रैगुलर किया जायेगा ?

श्रीमती सावित्री जिंदल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि उन अनएथोराईज्ड कालोनियों को रैगुलर किया जायेगा जिनमें 30.11.2004 तक 50 प्रतिशत या इससे अधिक प्लॉटों पर मकान बने हुए होंगे और सड़कें पूरी तरह से यातायात के लिए आने-जाने योग्य होंगी।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि

एक वर्ष पहले जिन कालोनियों को रैगुलर करने के लिए म्यूनिसीपल कारपोरेशन ने प्रपोजल भेजा था वे सभी कालोनियां मंत्री जी ने जो मापदण्ड बतायें हैं उनको पूरा करती हैं। उन कालोनियों में 80 से 90 प्रतिशत तक मकान बने हुए हैं और सड़कें भी पूरी तरह से चौड़ी हैं इस तरह वे सभी मापदण्ड पूरा रखती हैं। उन कालोनियों में मेरे क्षेत्र के अलावा बल्लभगढ और एन०आई०टी० की कालोनियां भी हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी डेढ़ साल पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग में उन कालोनियों को रैगुलर करने के बारे में आश्वास्त किया था और कारपोरेशन ने उनको रैगुलर करने के लिए एक साल पहले प्रपोजल भी सरकार को भेज रखा है लेकिन अभी तक भी उनको रैगुलर नहीं किया गया है। उनमें 20 कालोनीज़ बल्लभगढ की हैं, 22 एन०आई०टी० की हैं और इतनी ही हमारे क्षेत्र की हैं। हम मानते हैं कि ये कालोनियां पिछली सरकारों की देन हैं लेकिन अब वहां आम जनता को परेशानी हो रही है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब वे कालोनियां सभी मापदण्ड पूरा करती हैं तो उनको कब तक रैगुलर करवाकर उनमें डिवैल्पमैंट के काम करवाये जायेंगे।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। माननीया मंत्री महोदया ने माननीय सदस्य के सवाल का जवाब दे दिया है। 17 दिसम्बर, 2004 को जिस दिन चुनाव आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट लगाया गया उसी दिन 1054 कालोनीज को रेग्यूलराईज करने की आनन-फानन में चिट्ठी इश्यू कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, आप समझ सकते हैं कि एक घंटे में 1054 कालोनीज को न तो रेग्यूलराईज किया जा सकता है और न ही कोई सुविधा दी जा सकती है। जो भाई आज बहिर्गमन करके चले गये हैं यह सब उनकी मानसिकता का सूचक है। जब माननीय मुख्य मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कार्यभार सम्भाला उन्होंने बाकायदा सारी बात की समीक्षा की और यह निर्णय किया कि इन सारी 1054 कालोनीज में जहाँ 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है हम इन सबको वाकई जमीनी स्तर पर सुविधाएं देकर रेग्यूलराईज करेंगे। इस काम पर तकरीबन 318 करोड़ रुपये से अधिक खर्च आयेगा और इस काम में इस समय यह सरकार,मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी तत्परता से लगे हुए हैं। स्पीकर सर, जहाँ तक फरीदाबाद का सवाल है जो माननीय सदस्य ने पूछा है फरीदाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन ने जो प्रस्ताव भेजा था माननीय मंत्री महोदया जी उस प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल के सामने लेकर आई थी और मंत्रिमण्डल में माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हमने यह निर्णय किया था चूंकि यह प्रस्ताव इनकम्पलीट है। इसमें पूरा डाटा उपलब्ध नहीं है कि कितने मकान बने हैं, गलियाँ कितनी चौड़ी हैं, ओपन स्पेस कितने परसैंट है और ग्रीन स्पेस कितना है और दूसरी सुविधाएं देने का प्रावधान है या नहीं। इसलिए मंत्रिमण्डल ने यह ऑर्डर किया कि it was decided that the department could conduct a physical survey and send a fresh proposal. मंत्री जी ने एक स्पैशल कमेटी का गठन किया है जो उन सारी बस्तियों के अन्दर जिनका जिक्र माननीय सदस्य जी ने किया है जाकर फिजिकल सर्वे इस समय कर रही है। वह कमेटी पूरा मैप ड्रा करके लायेगी। मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें अभी 3 से 4 महीने और लग सकते हैं। हालाँकि यह 2004 के बाद का मामला है फिर भी मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी की यह मंशा है कि हम इस पर भी गम्भीरता से विचार करके इसका भी हल निकालें। यह प्रपोजल आ जाये इसके बाद हम इस पर कार्यवाही शुरू कर देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या-615

(इस समय माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा गया)।

Tax on Private School's Buses

***611 Sh. Dinesh Kaushik :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to abolish or decrease the tax of Rs. 60/- being charged per student per month in private School's buses ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : हाँ, श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्य और आपकी अनुमति से सदन को यह बताना चाहूँगा कि 60 रुपये प्रति सीट जो है 9 महीने के लिए बसों से टैक्स चार्ज किया जाता था। माननीय सदस्य श्री दिनेश कौशिक, माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले थे और भी बहुत सारे साथियों ने ऐसी इच्छा जाहिर की थी कि 60 रुपये प्रति सीट 9 महीने तक जब आप स्कूल बसों से जिनकी संख्या 4405 है, टैक्स चार्ज करेंगे तो इसका बोझ जो है वो अभिभावकों और बच्चों के ऊपर पड़ेगा। इस सारी बात का चिन्तन करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने विशेष बैठक बुलाई और उसमें मुख्य मंत्री जी ने यह निर्णय लिया है जो मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। स्पीकर सर, जहाँ पर स्कूल, बच्चों से 100 रुपये या 100 रुपये से कम चार्ज करेंगे क्योंकि आखिर तो स्कूल बसें बच्चों के लिए हैं तो 60 के 60 रुपये टैक्स माफ कर दिया जायेगा। जहाँ पर स्कूल 100 रुपये से अधिक और 200 रुपये से कम चार्ज करेंगे उनका भी 60 रुपये से घटा कर केवल 20 रुपये प्रति मास हमने इसको कर दिया है। जहाँ पर 200 रुपये से अधिक चार्ज करेंगे वहाँ पर टैक्स 60 रुपये से घटाकर 40 रुपये प्रति मास किया है और 4754 एजूकेशन इन्स्टीच्यूशनज की बसिज को कुल 571 लाख रुपये का लाभ होगा जिसका मुख्य मंत्री जी ने भी जिक्र किया है। सर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि यह राहत स्कूलों को नहीं बल्कि अभिभावकों को है। बसों के जो किराये थे वो निश्चित ही कई गुणा बढ़ गये थे यह राहत प्रदान करने के लिए अध्यक्ष महोदय, एक बार मैं फिर माननीय मुख्य मंत्री जी का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ।

श्री दिनेश कौशिक : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि यह राहत स्कूलों को नहीं बल्कि अभिभावकों को है, गांवों के लोगों को है क्योंकि जो स्कूल शहरों में बने हुए हैं उन स्कूलों की बसें बच्चों को लेने के लिए गांवों में जाती हैं और बसों का जो किराया बढ़ाया गया था निश्चित रुपये से वह कई गुणा बढ़ाया गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि यह समस्या शहरों की नहीं थी यह समस्या गांवों के अभिभावकों की थी इस समस्या के समाधान के लिए मैं दोबारा माननीय मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-632

(इस समय माननीय सदस्य श्री ज्ञान चंद सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा गया)।

तारांकित प्रश्न संख्या-640

(इस समय माननीय सदस्य श्री ईश्वर सिंह पलाका सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा गया)।

तारांकित प्रश्न संख्या-652

(इस समय माननीय सदस्य श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा गया)।

Upgradation of Badkhalsa Hospital

***636. Sh. Ramesh Kaushik :** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for upgradation of Badkhalsa Hospital and opening of new hospital of 30 beds at G.T. Road, Murthal ?

स्वास्थ्य मंत्री बहिन करतार देवी : जी नहीं, श्रीमान।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि बढ़खालसा में पहले से ही 30 बिस्तर का सी०एच०सी० चल रहा है और वहां पर केवल 70-80 पेशैंटस ही प्रतिदिन आते हैं इसलिए इसको अपग्रेड करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। जहां तक इन्होंने मुरथल की बात कही है, पिछली सरकार के वक्त से यह अस्पताल प्राईवेट बिल्डिंग में चल रहा है। इस अस्पताल के लिए पत्थर भी रखा गया था लेकिन पंचायत ने जो साईट दी थी वह गांव से भी तीन किलोमीटर दूर है और इन्होंने यह अस्पताल जी०टी०रोड पर बनाने के लिए कहा है। अध्यक्ष महोदय, जी०टी० रोड यहां से करीब पांच किलोमीटर दूर है। मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करना चाहूंगी वे ग्राम पंचायत से अनुरोध करके कोई स्यूटेबल साईट दिलवा दें तो सरकार वहां पर पी०एच०सी० की नई बिल्डिंग बनाने को तैयार है।

श्री रमेश कौशिक : स्पीकर सर, 10 एकड़ जमीन हम जी०टी० रोड मुरथल चौक पर पंचायत से दिलवा देंगे। पानीपत से लेकर दिल्ली तक कोई ऐसा होस्पीटल नहीं है कि अगर कहीं पर एक्सीडैंट हो जाए तो घायलों को चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा सके। अगर कोई घायल होता है तो उसको दिल्ली ले जाना पड़ता है जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। स्पीकर सर, पंचायत से हम दस एकड़ जमीन उपलब्ध करवा देंगे वे वहां पर होस्पीटल बनवा दें ताकि घायल होने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, वहां पर ऐसा होस्पीटल बनवाया जाए जिसमें एक्सीडैंटल केसों को डील किया जा सके। माननीय मन्त्री महोदया ने वहां पर होस्पीटल बनवाने का आश्वासन दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को यह बताना चाहूंगी कि यह जनहित की बात है और माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार इस मामले में कृतसंकल्प है कि जनहित जिस भी प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है उस समस्या का समाधान करना है और उस प्रश्न को भी हल करना है। स्पीकर सर, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि माननीय साथी जमीन दिलवा दें उस जमीन पर सरकार बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार है।

Appointment of Badminton Coach at Bhiwani

***649. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to appoint a Badminton Coach at Bhiwani; and

(b) if so, up to what time such a Coach is likely to be appointed ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) :

(क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) लागू नहीं होता।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि भिवानी में एक बहुत ही अच्छा स्टेडियम है और बहुत से बच्चों ने वहां पर खेलों में नैशनल लैवल पर और इन्टरनैशल लैवल पर प्रदेश का नाम रोशन किया है और बैडमिंटन के नैशनल लैवल के कई टूर्नामैंटस भी भिवानी में हुए हैं। सरकार से मेरा आग्रह है और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध है कि खेलों के भविष्य के लिए और देश के बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छे और सक्षम बैडमिंटन कोच की नियुक्ति वहां पर करने की कृपा करें। वहां पर पहले विजय कपूर जी बैडमिंटन कोच रहे हैं जो अब पंचकूला में नियुक्त हैं, उनके समय में हमारे बच्चों ने खेलों में विशेषकर बैडमिंटन के खेल में बड़ी तरक्की की थी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि बैडमिंटन कोच वहां पर नियुक्त करने की कृपा करें ताकि बच्चों को खेलने और सीखने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकें।

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, भिवानी में श्रीमती मन्जू घई दिनांक 11.08.2005 से बैडमिंटन कोच नियुक्त रहीं हैं, वे वहां पर स्पोर्ट अथोरिटी की ओर से पोस्टिड हैं। भिवानी में अभी और कोच की आवश्यकता नहीं है। जहां तक इन्होंने भिवानी में जिक्र किया कि वहां पर बच्चों में टेलैन्ट है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि सरकार ने वहां पर 26 कोचिज लगाए हुए हैं, अगर ये चाहें तो मैं इनको विभिन्न खेलों में जो हमारे कोच लगे हुए हैं उनकी डिटेल भी दे देता हूं। इस समय वहां पर ऐथलिटिक्स के 5, बास्केट बॉल के 2, बॉक्सिंग का एक, क्रिकेट के दो, जिमनास्टिक के दो, हैंडबॉल का एक, हॉकी का एक, जूडो का एक, कबड्डी के चार, वॉलीबाल के दो, रैस्लिंग के चार, योगा का एक और बैडमिंटन का एक कोच वहां पर कार्य कर रहे हैं।

10.00 बजे **डॉ० शिव शंकर भारद्वाज :** अध्यक्ष महोदय, वह महिला कोच अक्सर गैरहाजिर रहती है और वहां पर कोई भी कोच नहीं होता है। आप इस बारे में जांच करवाएं ताकि आपको असलियत का पता चले। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर कोई परमानैंट कोच लगाया जाए ताकि जो बच्चे वहां पर आते हैं उनको प्रोपर कोचिंग मिल सके।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी जी जो कह रहे हैं इस बारे में हम जांच करवा लेंगे और पता करेंगे कि वह महिला कोच क्यों गैरहाजिर रहती है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वहां पर बच्चों को सही ढंग से कोचिंग मिले।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन में स्टेडियम और खिलाड़ियों को फैसिलिटी देने की बात हो रही है तो मैं भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि करनाल में एक स्वीमिंग पूल है और वहां के बच्चे देश में और प्रदेश में हरियाणा का नाम रोशन करके आए हैं। लेकिन सरकार ने उस स्वीमिंग पूल को प्राईवेट ठेकेदार को ठेके पर दे दिया है और यह कहा कि इस पूल की मैनटेनैंस नहीं हो पा रही थी। अब वह प्राईवेट ठेकेदार मार्च के महीने में जब तपती धूप होती है उस वक्त हमारे बच्चों को स्वीमिंग करने का समय देता है जिससे हमारे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को वहां पर प्रैक्टिस करने में बहुत मुश्किल आती है। वह ठेकेदार सुबह और शाम के टाईम में प्राईवेट बच्चों को पैसे लेकर स्वीमिंग करवाता है। क्या इस बारे में मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ताकि हमारे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने का सही समय मिल सके।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वीमिंग कोच का सम्बन्ध है तो हमने करनाल में कोच लगाया हुआ है और जहां तक इन्होंने स्वीमिंग पूल को ठेके पर देने वाली बात कही है तो हम इस बारे में पता कर लेंगे कि वह स्वीमिंग पूल क्यों ठेके पर दिया है। अगर ये चाहती हैं कि वह स्वीमिंग पूल प्राईवेट ठेके पर न दिया जाए तो हमें इस बारे में लिखकर दे दें।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न कोच के बारे में नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि वहां पर स्वीमिंग पूल प्राईवेट ठेकेदार को ठेके पर दिया हुआ है और वह हमारे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को दोपहर के वक्त ही प्रैक्टिस का समय देता है और दूसरे जो बच्चे स्वीमिंग शौक के लिए करते हैं उनसे 500 या 1000 रुपए लेकर सुबह और शाम के टाईम पर स्वीमिंग का समय देता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि उस प्राईवेट ठेके को खत्म करके सरकार को उस स्वीमिंग पूल को अपने कब्जे में लेना चाहिए ताकि हमारे खिलाड़ी वहां पर सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकें और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का जो खदसा है हम उस बारे में जांच करवा लेंगे। अगर वह ठेकेदार उस स्वीमिंग पूल को सही तरीके से नहीं चला रहा है तो हम उसका ठेका रद्द कर देंगे और उन खिलाड़ियों को सही और उचित समय प्रैक्टिस करने को देंगे।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, यह जो हरियाणा प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए हर ब्लाक में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और जब ये बन कर तैयार हो जाएंगे तो क्या वहां पर भी कोचिज़ को लगाया जाएगा। क्या ऐसा मंत्री जी आपने कोई प्रावधान किया है।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने बहुत ही सही सवाल किया है। पिछली सरकार के वक्त में हरियाणा में शिक्षा और खेलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था।

[श्री फूल चन्द मुलाना]
आज इस सरकार के राज में शिक्षा का बहुमुखी विकास हो रहा है। आज शिक्षा का नाम देश में नम्बर एक पर है। इसी तरह से हमारी सरकार के आने से पहले देहातों में खेलों का कोई प्रावधान नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने निर्णय लिया है कि हम हरियाणा प्रदेश में हर ब्लाक स्तर पर स्टेडियम बनवाएंगे और इसके लिए 40 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। पूरे हरियाणा में 139 स्टेडियम ब्लाक लैवल पर बनाए जाने का आदेश दिया गया है। जब ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएंगे तब हम वहां पर कोचिज़ की ड्यूटी भी लगाएंगे ताकि हमारे देहातों के बच्चे वहां पर ट्रैनिंग ले सकें। हम वहां पर हर गेम से रिलेटिड कोचिज़ की ड्यूटी लगाएंगे।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो बैडमिन्टन कोच का सवाल भिवानी के मुतालिक उठा है तो क्या कोई डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर भिवानी के अलावा और भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर हैं जहां पर बैडमिन्टन का कोच नहीं है या बैडमिन्टन की सुविधा नहीं है और यदि नहीं है तो क्या फर्दर वहां पर बैडमिन्टन कोच लगाने का सरकार का विचार है ?

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने दूसरे सवाल के उत्तर में बताया कि हर स्थान पर अलग अलग खेलों की प्रतिभा हैं जहां पर भी बैडमिन्टन के खिलाड़ी होंगे वहां पर हर जिले में हम बैडमिन्टन के कोच लगाने का प्रावधान भी करेंगे।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में वर्तमान स्थिति पूछी है मंत्री जी उसके बारे में बताएं।

श्री अध्यक्ष : यह मामला तो बहुत वाईड है इसलिए आप सैपरेट क्वैश्चन पूछें।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : स्पीकर सर, यह तो कंसर्ड मामला ही है इतनी बात तो मंत्री जी के पास टिप्स पर होगी।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष जी, बैडमिन्टन के लिए जैसा मैंने बताया कि एक कोच भिवानी में है, एक कोच फरीदाबाद में है और एक कोच करनाल में है। इसके अलावा जहां जहां से हमारे पास इसके लिए मांग आएगी वहां-वहां पर हम बैडमिन्टन का कोच प्रोवाइड करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रोफैसर साहब, आपको कहां पर कोच चाहिए ?

प्रो० छत्तरपाल सिंह : स्पीकर सर, मुझे हिसार में कोच चाहिए।

चौ० राकेश कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में लॉन टैनिस के कितने कोच हैं ?

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष जी, जहां तक करनाल जिले का ताल्लुक है करनाल में एथेलिटिक्स का एक कोच है, बास्केटबाल का एक कोच है साईकलिंग का भी एक कोच है, फेंसिंग का भी एक कोच है, फुटबाल के दो कोच हैं, हॉकी का भी एक कोच है, कबड्डी का भी एक कोच है, स्केटिंग का भी एक कोच है, योगा का भी एक कोच है, स्वीमिंग का भी एक कोच है और रेसलिंग का भी एक कोच है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष जी, अगर विधायक जी को लोन टैनिस का कोच चाहिए तो उसके लिए मैं तैयार हूं ये मेरे पास सुबह आ जाया करें।

Opening of New Colleges in the State

***668. Sh. S.S. Surjewala :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of Colleges of all categories have been opened by the present Govt.; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open new Colleges in the State during the Financial year 2007-2008 ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : श्रीमान् जी, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

(क) खोले गए महाविद्यालय :

वर्तमान सरकार द्वारा प्रियदर्शिनी इन्दिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय, जीन्द तथा राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय, साहा (अम्बाला) तथा शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय, मटक माजरी इन्द्री (करनाल) (प्रभार में लिया गया) खोले गए हैं।

(ख) खोले जाने वाले महाविद्यालय :

सरकार ने वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य में राजकीय महिला महाविद्यालय, तोशाम (भिवानी), राजकीय महाविद्यालय, जुलाना (जीन्द) तथा राजकीय महाविद्यालय, बिरोहड़ (झज्जर) खोलने का निर्णय लिया है। राजकीय महिला महाविद्यालय, पंचकुला में भी वर्ष 2007-08 के दौरान शिक्षण कार्य आरम्भ हो जायेगा। सरकार ने आगामी पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान छछरौली (यमुनानगर) तथा छारा (झज्जर) में भी नये राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, क्षेत्र की आवश्यकता तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर सरकार नये महाविद्यालय खोलने पर विचार करेगी।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, कैथल में दो साल से 12 एकड़ जमीन पंचायत ने कालेज बनाने के लिए दी हुई है। वहां पर जो मेन रोड है उस पर यह जमीन शहर के ही नजदीक है। मुख्यमंत्री जी ने भी पब्लिक मीटिंग में इस बारे में आश्वासन दिया था कि इस साल में नया कालेज वहां पर शुरू कर देंगे। लेकिन मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है उसमें कैथल का नाम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस साल कैथल में नया कालेज शुरू करवा देंगे ?

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को प्राथमिकता दी जाती है। कैथल में कालेज बनाना मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है और उसके लिए मामला अंडर प्रौसेस भी है। अगर वहां की जमीन के कागजात पूरे हो गये हैं तो मुख्यमंत्री जी की घोषणा को पूरा किया जाएगा।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ऐजुकेशन डिपार्टमैंट के नाम वहां की पंचायत ने जमीन कर दी है।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष जी, फिर हम उसको बनवाएंगे। मैं माननीय साथी को आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो हम वहां पर उस कालेज की बिल्डिंग बनवा देंगे लेकिन यदि ये कहीं और किसी आल्टरनेटिव जगह का प्रबन्ध कर दें तो हम क्लासिज भी वहां शुरू करवा देंगे।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री तो नहीं हूं पर मैं मंत्री जी को आश्वासन देता हूं कि जिस वक्त भी ये कहेंगे हम वहां टैम्परेरी क्लासिज चलाने के लिए पर्याप्त बिल्डिंग दे देंगे।

श्री फूल चंद मुलाना : ठीक है, हम क्लासिज शुरू कर देंगे।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी काफी काबिल व कमीटेड व्यक्तित्व हैं। मैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि जब से इस सरकार का गठन हुआ है, पहले सैशन में ही मैंने एक मांग की थी कि हमारे यहां पर गांव सीकरी में जो कि शहर से काफी दूर है और उसके इर्द गिर्द तीस गांव आते हैं। वहां के लोगों की पुरानी मांग थी कि वहां बच्चियों के लिए गर्ल्स कालेज का प्रावधान किया जाए। क्या मंत्री जी मुझे आज आश्वस्त करेंगे कि वहां गर्ल्स कालेज खोला जाएगा। वहां गांव के लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं और फंड से अमाउंट भी देने के लिए तैयार हैं ?

Shri Phool Chand Mullana : The Government is committed to impart education to every section of the society. But opening of new Girls College would depend on the need of the area and the availability of the funds.

Shri A.C. Chaudhary : Sir, it is the need of the area. It being the Girls Education Year also and simultaneously funds are quite available. The villages are ready to make the part payment and are also ready to give the land for the purpose. Would the Hon'ble Minister give the assurance in this regard.

Shri Phool Chand Mullana : Sir, we will examine this matter.

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या कलायत जैसे बैकवर्ड एरिया के लिए कालेज खोलना विचाराधीन है क्योंकि कलायत के बैकवर्ड होने की वजह से वहां लिटरेसी रेट कम है। एक वहां पर कपिल मुनि महिला कॉलेज के नाम से कालेज चलाया जा रहा है। हमारे पास 9 एकड़ लैंड है, बिल्डिंग तैयार है। जब से यह सरकार बनी है तब से हम कलायत में एक कालेज खोलने की मांग करते आ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रहा है क्या कलायत में सरकार की कालेज खोलने की सोच है ?

श्री फूल चंद मुलाना : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने यह बताया कि एक कालेज वहां है। यह कालेज एडिड है या नॉन एडिड है यह मुझे नहीं पता है।

श्रीमती गीता भुक्कल : नॉन एडिड है।

श्री फूल चंद मुलाना : नॉन एडिड है और अगर बैकवर्ड एरिया है तो हम इसको भी ऐग्जामिन करेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, कलायत बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर्ड है।

श्री दूड़ा राम : अध्यक्ष जी, मेरे हल्के फतेहाबाद में एम०ए० की क्लासिज लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। क्योंकि यह एरिया हिसार से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है।

श्री फूल चंद मुलाना : अध्यक्ष जी, जो भी संस्था पोस्ट ग्रेजुएट क्लासिज शुरू करना चाहती है उनकी तरफ से एक मांग आती है वह मांग जब आएगी तब पूरा विचार किया जाएगा।

श्री दूड़ा राम : अध्यक्ष महोदय, हमने मांग भेज रखी है।

श्री फूल चंद मुलाना : अगर आपने मांग भेज रखी है तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, हमारा बवानी खेड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। यहां के बच्चे हांसी और भिवानी पढ़ने जाते है। बच्चियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्या बवानी खेड़ा में कालेज खोलने का कोई प्रावधान सरकार कर रही है ? इसके लिए हम एक करोड़ रुपया लोगों से इकट्ठा करके दान के तौर पर दे देंगे और आपका धन्यवाद भी करेंगे।

श्री फूल चंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वैसे तो भिवानी जिले में पहले से ही कई कालेज हैं। जिस जगह की ये चर्चा कर रहे हैं वह भिवानी से ज्यादा दूर नहीं है। हमारा क्राइटेरिया है कि 20-25 किलोमीटर की दूरी पर कालेज होना चाहिए। फिर भी ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग बना कर दे देंगे तो हम विचार करके कालेज खुलवा देंगे।

प्रो० छतर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हांसी में जो गवर्नमेंट कालेज है वहां पर विद्यार्थियों की संख्या के मुकाबले में बिल्डिंग बहुत कम हैं। इसके बारे में काफी रिक्वैस्ट भी आई हुई है। मैं पिछले दिनों वहां पर एक एनुअल फंक्शन में गया था तब वहां के प्रिंसीपल और स्टाफ ने मुझ से इस बारे में अर्ज जाहिर की थी। क्या वहां पर टीचिंग के लिए फरदर ब्लॉक देने का प्रावधान करेंगे ?

श्री फूलचन्द मुलाना : माननीय स्पीकर साहब, हांसी के कालेज के प्रिंसीपल की अगर इस बारे में कोई मांग आई है तो वहां पर एडीशनल बिल्डिंग की जहां तक बात है तो अगर विभाग के पास बिल्डिंग के लिए फण्ड उपलब्ध होगा तो उस बारे में अवश्य विचार करवायेंगे।

श्री अमीरचन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रो० साहब ने वैसे तो हांसी के कालेज के बारे में सवाल कर दिया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या हांसी में लड़कियों का कालेज खोलने की सरकार की कोई स्कीम है। इसके अलावा गवर्नमेंट कालेज में लड़कों के खेलने के लिए मैदान नहीं हैं क्या सरकार का वहां पर स्पोर्टस स्टेडियम बनाने के लिए जमीन लेने का प्लान है क्योंकि हुड्डा साहब खेलों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं क्या हांसी के कालेज के खेल के मैदान का प्रावधान सरकार करवायेगी ?

श्री अध्यक्ष : मक्कड़ साहब, आप इस बारे में अलग से प्रश्न लिखित रूप में दे देना।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि 20 किलोमीटर की दूरी पर कालेज खोलने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। भिवानी से बहल सब तहसील 60 किलोमीटर है और लोहारू से 50 किलोमीटर है। वहां की पंचायत कालेज के लिए जमीन देने के लिए तैयार है इस बारे में सरकार को रिक्वैस्ट भेजी हुई है, क्या मंत्री जी वहां पर कालेज खोलने का आश्वासन देंगे। दूसरा लोहारू कालेज में 500 के करीब लड़कियां पढ़ती हैं और उनका अलग से विंग भी है लेकिन वह जगह किसी सेठ ने किराए पर दी हुई है और अब वह सेठ उस जगह को खाली करवाना चाहता है। क्या सरकार लड़कियों की विंग के लिए कोई अलग से बिल्डिंग बनवाने का प्रावधान करेगी।

श्री फूलचन्द मुलाना : माननीय स्पीकर साहब, जहां तक बहल की बात माननीय सदस्य ने कही है कि इस बारे में मांग भेजी हुई है, तो सरकार उस मांग पर विचार अवश्य करेगी। जहां तक लड़कियों के लिए अलग विंग बनाने के लिए जगह के बारे में बात की है उसके लिए बिल्डिंग का प्रावधान जरूर करेंगे।

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 25-30 किलोमीटर के अन्दर कालेज खोलने का सरकार का विचार है। बरवाला की आबादी लगभग 50 हजार की है और हिसार, नरवाना और जीन्द से 30 किलोमीटर दूर है और इतनी दूरी में कोई कालेज नहीं है। बरवाला में एक प्राईवेट संस्था ने बिल्डिंग बनाई हुई है अगर सरकार चाहे तो उस बिल्डिंग में सरकारी कालेज खोल सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बरवाला में सरकारी कालेज खोला जायेगा।

श्री फूलचन्द मुलाना : माननीय स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस बारे में हम एग्जामिन करेंगे और वहां पर कालेज जरूर खोलेंगे।

Food Grain Supplied to B.P.L. Families

Sh. Tejendera Pal Singh Mann : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the details of amount paid as subsidies of the food grain supplied to B.P.L. families per month in the State and also togetherwith the details of amount contributed by the Govt. of India ?

उप मुख्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन) : गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सीधी नकद सब्सिडी नहीं दी जा रही है। परन्तु इन परिवारों को कम दामों पर गेहूं और चावल का वितरण किया जा रहा है। सब्सिडी की राशि मास दर मास खाद्यान्नों के उठान पर निर्भर करती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों द्वारा मास अप्रैल, 2006 से मास जनवरी, 2007 तक मास दर मास प्राप्त की गई सब्सिडी, जिसे भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है, का ब्यौरा सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों द्वारा प्रति मास प्राप्त की गई सब्सिडी का विवरण

मास	वस्तु	श्रेणी	खाद्यान्न का उठान (क्विंटलों में)	सरकारी कीमत (प्रति क्विंटल रुपयों में)	उपभोक्ता मूल्य (प्रति क्विंटल रुपयों में)	खाद्यान्न के उठान की स्थिति अनुसार जो सब्सिडी बनती है (लाख रुपयों में)	भारत सरकार का अंशदान (लाख रुपयों में)	राज्य सरकार का अंशदान (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल, 06	गेहूं	बी.पी.एल.	129955	1204	484	935.68	935.68	0
	गेहूं	ए.ए.वाई.	78502	1195	210	773.24	733.99	39.25
	चावल	बी.पी.एल.	48388	1672	640	499.36	499.36	0
मासिक सब्सिडी						**2208.28**	**2169.03**	**39.25**
मई, 06	गेहूं	बी.पी.एल.	130168	1204	484	937.21	937.21	0
	गेहूं	ए.ए.वाई.	80981	1195	210	797.66	757.17	40.49
	चावल	बी.पी.एल.	44593	1672	640	460.20	460.20	0
मासिक सब्सिडी						**2195.07**	**2154.58**	**40.49**
जून, 06	गेहूं	बी.पी.एल.	129412	1204	484	931.77	931.77	0
	गेहूं	ए.ए.वाई.	80573	1195	210	793.64	753.36	40.29
	चावल	बी.पी.एल.	47448	1672	640	489.66	489.66	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मासिक सब्सिडी						**2215.07**	**2174.79**	**40.29**
जुलाई, 06	गेहूं	बी.पी.एल.	126737	1204	484	912.51	912.51	0
	गेहूं	ए.ए.वाई.	79257	1195	210	780.68	741.05	39.63
	चावल	बी.पी.एल.	48333	1672	640	498.80	498.80	0
मासिक सब्सिडी						**2191.99**	**2152.36**	**39.63**
अगस्त, 06	गेहूं	बी.पी.एल.	129446	1204	484	932.01	932.01	0
	गेहूं	ए.ए.वाई.	81303	1195	210	800.84	760.18	40.65
	चावल	बी.पी.एल.	49647	1672	640	512.36	512.36	0
मासिक सब्सिडी						**2245.21**	**2204.55**	**40.65**

टिप्पणी बी.पी.एल. : गरीबी रेखा से नीचे

ए.ए.वाई. : अन्त्योदय अन्न योजना

मास	वस्तु	श्रेणी	खाद्यान्न का उठान (क्विंटलों में)	सरकारी कीमत (प्रति क्विंटल रुपयों में)	उपभोक्ता मूल्य (प्रति क्विंटल रुपयों में)	खाद्यान्न के उठान की स्थिति अनुसार जो सब्सिडी बनती है (लाख रुपयों में)	भारत सरकार का अंशदान (लाख रुपयों में)	राज्य सरकार का अंशदान (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सितम्बर, 06	गेहूं	बी.पी.एल.	118659	1204	484	854.34	854.34	0
	गेहूं	ए.ए.वाई.	84076	1195	210	828.15	786.11	42.04
	चावल	बी.पी.एल.	48035	1672	640	495.72	495.72	0
मासिक सब्सिडी						**2178.21**	**2136.17**	**42.04**
अक्तूबर, 06	गेहूं	बी.पी.एल.	116195	1204	484	836.60	836.60	0
	गेहूं	ए.ए.वाई.	85186	1195	210	839.08	796.49	42.59
	चावल	बी.पी.एल.	50492	1672	640	521.08	521.08	0
मासिक	**सब्सिडी**					**2196.76**	**2154.17**	**42.59**
नवम्बर, 06	गेहूं	बी.पी.एल.	114974	1204	484	827.81	827.81	0
	गेहूं	ए.ए.वाई.	91682	1195	210	903.07	857.23	45.84
	चावल	बी.पी.एल.	50482	1672	640	520.97	520.97	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मासिक सब्सिडी						**2251.85**	**2206.01**	**45.84**
दिसम्बर, 06	गेहूं	बी.पी.एल.	113559	1204	484	817.62	817.62	0
	गेहूं	ए.ए.वाई.	95485	1195	210	940.53	892.78	47.74
	चावल	बी.पी.एल.	51000	1672	640	526.32	526.32	0
मासिक सब्सिडी						**2284.47**	**2236.72**	**47.74**
जनवरी, 07	गेहूं	बी.पी.एल.	113490	1204	484	817.13	817.13	0
	गेहूं	ए.ए.वाई.	95610	1195	210	943.73	895.82	47.91
	चावल	बी.पी.एल.	51040	1672	640	526.73	526.73	0
मासिक सब्सिडी						**2287.59**	**2239.68**	**47.91**

टिप्पणी बी.पी.एल. : गरीबी रेखा से नीचे
ए.ए.वाई. : अन्त्योदय अन्न योजना

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह : स्पीकर सर, मंत्री महोदय ने जो यह बी०पी०एल० की लिस्ट बताई है इसके लिए सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि बी०पी०एल० फैमलीज के लिए सरकार जो भी सहायता देती है उसमें टोटल कन्ट्रीब्यूशन भारत सरकार का होता है। कई स्टेट गवर्नमेंट्स, पोलिटिकल पार्टीज ने पिछले दिनों इन फैमलीज को सस्ता आटा, दाल, चावल देने के लिए योजना लोगों के सामने रखी है। हम पर भी बहुत सा लोगों का प्रैशर रहता है। हमें मालूम है कि जो बी०पी०एल० कार्ड होल्डर हैं उनमें सरकार के मापदण्डों के अनुसार शहरों में रहने वाले लोग ज्यादा होते हैं इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से दरखास्त करूंगा चूंकि सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी है। इसलिए बजट में कोई ऐसी प्रणाली बनाई जाये कि जो बी०पी०एल० कार्ड होल्डर हैं, जो शहरों में स्लमज में रहने वाले लोग हैं उनको सस्ते दाम पर सरकार रिम्ब्रसमैंट करके सस्ता आटा और दाल देने का प्रावधान करे। इसके अतिरिक्त मैं उप मुख्यमंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि जो अन्त्योदया अन्न योजना है वह किन वर्गों के लिए है।

श्री चन्द्र मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय पहले से घोषणा कर चुके हैं कि बी०पी०एल० का सर्वे दोबारा करवाया जायेगा। जिन परिवारों का इस पर हक था और वे इससे वंचित रह गये हैं उनको इसके अंतर्गत लिया जायेगा। यदि मेरे माननीय साथी के यहां कोई स्पैसीफिक शिकायत इस तरह की है तो वे बता दें उसका दोबारा सर्वे करवा लिया जायेगा।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा सर्वे करवाने का बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि पिछली सरकार के समय में जो सर्वे हुआ था उसमें उन लोगों को बी०पी०एल० का फायदा दे दिया जो इसके हकदार नहीं थे और उनको इसका फायदा नहीं दिया गया जो वास्तव में हकदार थे। लेकिन एक बात मैं मंत्री जी को जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में सारी सुविधाएं बी०पी०एल० के आधार पर ही दी जायेंगी जिसके कारण गांवों में गरीब आदमियों में सामाजिक अलगाव की भावना पैदा होगी। क्योंकि बहुत से गरीब आदमी अब भी बी०पी०एल० की लिस्ट में इसलिए शामिल नहीं हो पायेंगे कि जो सैंट्रल गवर्नमैंट का बी०पी०एल० का दायरा है उसमें वे कवर नहीं होते। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार एक ऐसा वर्ग बनायेगी जो अफ्लूयैंसी और बी०पी०एल० के बीच बनाया जाये जिसको आटे-दाल की सुविधाएं सरकार के माध्यम से सस्ते रेटों पर दी जायें। क्योंकि हमारी वित्तीय स्थिति आज के दिन बहुत अच्छी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ऐसा कोष बनाया जाये जिससे गांव के हर राशन कार्ड होल्डर को और शहरों में रहने वाले सलम एरियाज के लोगों को सस्ते रेट पर आटा और दाल दी जा सके।

श्री चन्द्र मोहन : अध्यक्ष महोदय, बी०पी०एल० फैमली का क्या क्राईटेरिया है यह मामला सैंट्रल गवर्नमैंट से संबंधित है, स्टेट गवर्नमैंट से संबंधित नहीं है। हम इसके क्राईटेरिया को नहीं बदल सकते। हमारा डी०आर०डी०ऐ० और अर्बन डिवैल्पमैंट विभाग इसका सर्वे करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही कहा हुआ है कि इसका दोबारा से सर्वे करवाया जायेगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक बार-बार बी०पी०एल० के बारे में सवाल कर रहे हैं। मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो सर्वे अब हमारी सरकार ने बी०पी०एल० का किया है उसकी तीन महीने में लिस्ट आ जायेगी

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

इसलिए सभी साथी तीन महीने तक इंतजार करें। हम सभी साथियों की जिम्मेवारी है कि जिस परिवार का हक बनता है उसका नाम बी०पी०एल० की लिस्ट में आये। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले हुआ था कि जिन लोगों का हक नहीं था वे लोग इसका फायदा ले गये और जिनका हक बनता था वे रह गये। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि जो लोग हकदार हैं वे किसी भी कारण से रहने नहीं चाहिएं और मेरी सभी विधायकों से भी प्रार्थना है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि उनके हल्के में कोई बी०पी०एल० का हकदार परिवार रह न जाये। उसके बाद जिस बात का जिक्र माननीय साथी कर रहे थे उस पर विचार किया जायेगा।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय से सस्ते रेट पर गेहूं और दूसरे खाद्यान्न पदार्थों को मुहैया करवाने की बात की है। मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जनवरी, 2007 तक जो बिलो पावरटी लाईन के परिवार हैं उनके लिए एक महीने का कोटा 25 किलो गेहूं पर कार्ड का है और 4.84 रुपये प्रति किलो के भाव से दिया जा रहा है। जहां तक मेरे साथी ने अन्त्योदय अन्न योजना का जिक्र किया है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस स्कीम के तहत 35 किलो गेहूं पर कार्ड, पर मंथ, 2 रुपये 10 पैसे प्रति किलो के भाव पर दिए जाते हैं।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जो लोकल लैवल पर हर शहर में और गांव में सरकारी राशन के डिपोज अलाट किए जाते हैं उनका क्या क्राईटेरिया है। अगर एक डिपो के लिए 5-6 एप्लीकेशन आती हैं तो उनमें से किसी एक को डिपो दे दिया जाता है। मैं यह जानना चाहती हूं कि उन पांच या छः एप्लीकेंट्स में से किसी एक को किस आधार पर डिपो अलॉट किया जाता है।

श्री चन्द्र मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि डिपो अलाट करने के लिए शहरों और गांवों में एक-एक कमेटी का गठन किया हुआ है। जहां तक शहरी क्षेत्रों में डिपो अलाट करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसमें म्यूनिसिपल काउंसलर, पूर्व म्यूनिसिपल काउंसलर, उपमण्डल अधिकारी तथा मनोनीत स्थानीय महिला प्रतिनिधि मैंबर होते हैं। उस कमेटी की रिकमैंडेशन पर ही संबंधित शहर का डिपो अलाट किया जाता है। जहाँ तक गाँव का सवाल है वहाँ पर सरपंच, अनुसूचित जाति का पंच और यदि सरपंच अनुसूचित जाति से है तो उसके स्थान पर दूसरी जाति का पंच और क्षेत्र के पटवारी की रिकमैंडेशन हम मानते हैं।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि पिछले 2 साल के अन्दर करनाल में जो डिपोज दिये गये हैं क्या वे सभी इन कमेटियों की रिकमैंडेशन के आधार पर दिये गये हैं। मेरी जानकारी में ऐसी कोई कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है और क्या सभी मैम्बर्स ने वो मीटिंग अटैंड भी की है या नहीं। मेरे रेजीडैंस के पास ही डी०एफ०एस०ओ० का दफ्तर है। मुझे कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि वहाँ पर आपस में कोई सैटिंग हो जाती है उसके बाद वो हमारे पास भेज देते हैं कि लोकल एम०एल०ए० की रिकमैंडेशन करवा लो और हमें मजबूरी में करनी पड़ती है क्योंकि हम उनके रिप्रैजैंटेटिव हैं और वो हमारे वोटर हैं। बाकी जगहों का मुझे नहीं मालूम इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप करनाल का जरूर चैक करवाईये।

श्री चन्द्रमोहन : अध्यक्ष महोदय, अगर इनकी जानकारी में कोई इस तरह की कम्पलेंट है तो ये लिखकर भिजवा दें हम इन्क्वायरी करवा लेंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि दो साल के अन्दर-अन्दर जितने डिपोज करनाल में अलाट किये गये हैं आप अपने लैवल पर ही उनकी इन्क्वायरी करवा लीजिए।

श्री चन्द्रमोहन : ठीक है सर, हम इन्क्वायरी करवा लेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप-मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इन डिपोज में जो शिकायत आती हैं कि गरीबों को और जरूरतमंदों को सही तरीके से सामान नहीं मिलता क्या ये कोई ऐसी नीति बनाने पर विचार करेंगे कि जिसमें जो प्रदेश के अन्दर बेरोजगार हैं जो स्नातक हैं या जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको ही ये डिपोज अलाट किए जाएं। जिस तरीके से मुख्य मंत्री जी ने बिजली विभाग में एक्स सर्विसमैन को बिल बनाने का काम दिया है वह बहुत अच्छा काम है क्योंकि गरीबों का हक गरीब के घर तक पहुँच जायेगा और वह महंगाई की मार से बच सकेगा। तो क्या उप-मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि प्रदेश में जो पढ़े लिखे बेरोजगार या एक्स सर्विसमैन है उनको ये डिपो दिये जायें।

श्री चन्द्रमोहन : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमने पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की है। ग्राम पंचायतों की अलग किस्म की ड्यूटी लगाई है। पंचायत समिति और जिला परिषद के मैम्बर्स को भी इस कार्य में हमने साथ लिया है। जहाँ तक एक्स सर्विसमैन और दूसरे बेरोजगार स्नातक की बात की है तो इस बारे में हम विचार कर लेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को और माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल को यह बताना चाहता हूँ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और हमारे डिपोज की जो लाईसैंसिंग प्रणाली है इन दोनों को लेकर मुख्य मंत्री जी बड़े चिंतित थे इसलिए उन्होंने बैठक बुलाई। इसके बाद उप मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री महोदय ने और हमने इन दोनों प्रणालियों के बारे में डिटेल नीति 21 सितम्बर 2005 को सरकूलेट की है। मिट्टी के तेल के डिपोज के आबंटन और वो ठीक से बगैर किसी लीकेज के सही जगह पर पहुँच जाये उसके बारे में भी जो नीति बनाई और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीति बनाई उसमें एडिक्वेट सेफगार्ड्स रखे गये हैं। मैं इन दोनों नीतियों की एक-एक कॉपी माननीय सदस्य को भी पहुंचा दूंगा।

Establish HUDA Sector in Narnaund Constituency

***683 Sh. Ram Kumar Gautam :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to develop any sector of HUDA in Narnaund Constituency ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्री मान्।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस पर हमने चिन्तन किया है और हमने यह निर्णय किया है कि हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि माँग को देखते हुए वहाँ हुडा का एक छोटा सैक्टर अवश्य बनाया जाये और इसका सर्वे हम शुरु करवा लेंगे और माँग के मुताबिक इसको बनवा भी देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, नारनौंद में हुडा का सैक्टर बनवा देंगे।

श्री राम कुमार गौतम : सर, वैसे तो आपने मना किया था लेकिन फिर ना-ना करते प्यार हमीं से कर बैठे आपने हाँ कह दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker : Now, the questions hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Roads/Amount Sanctioned by the Haryana State Agricultural Marketing Board

***590. Dr. Sita Ram :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the district-wise details of roads and amount sanctioned by the Haryana State Agricultural Marketing Board since the financial year 2005 till date ?

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) : श्रीमान् जी, सूची हाऊस के पटल पर रखी जाती है।

सूची

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिनांक 01-04-2005 से 28-02-2007 तक जिलावार सम्पर्क सड़कों तथा स्वीकृत राशि का विवरण।

अम्बाला	क्र. सं.	सड़क का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की तारीख	लम्बाई किलोमीटरों में	अनुमानित लागत रुपये लाखों में
1	2	3	4	5	6
अम्बाला	1.	मानकपुर से को-ओपरेटिव सोसायटी गांव लोहगढ़	17.04.2006	1.36	20.57
	2.	मदनपुर से धूलकोट (पावर हाउस)	12.05.2006	0.78	10.99
	3.	गरनाला से जनेतपुर	21.07.2006	1.53	31.65
	4.	गेलखुर्द से लायलपुर बस्ती	09.10.2006	3.00	48.97
	5.	धुडियाला से दुखेड़ी	15.06.2006	1.19	17.86
	6.	टोबा से पिलखनी	15.06.2006	1.46	19.15
	7.	टेपला से बिहटा	15.06.2006	1.97	26.80
	8.	गोकुलगढ़ से खेड़ा	15.06.2006	1.32	19.20
	9.	खारुखेड़ से शामलहेड़ी	15.06.2006	1.95	26.04
	10.	गगनखेड़ी से महूवा खेड़ी	15.06.2006	2.50	33.03
	11.	बराड़ा से होली	15.06.2006	2.30	28.37

1	2	3	4	5	6
	12.	सुबरी से राजो खेड़ी तंदवाली सड़क	04.07.2006	1.50	19.76
	13.	थम्बड़ से सलीमपुर	11.07.2006	2.90	35.33
	14.	अम्बाला जगाधरी रोड़ से साहा कालिज साहा	13.07.2006	1.40	13.82
	15.	शिबला से बुड़ियाँ	11.07.2006	0.97	13.97
	16.	उपलाना से महुवाखेड़ी	04.12.2006	1.92	25.59
	17.	लंगर छानी से चुड़ियाली	04.12.2006	2.84	34.85
	18.	सौंटा से ईस्माईलाबाद वाया मीरपुर	31.05.2006	2.32	31.67
	19.	वोट काछवा से शाहपुर	17.08.2006	1.90	22.69
	20.	कक्कड़ माजरा से थरवा	12.05.2006	2.98	44.63
	21.	नारायणगढ़ माजरा से केसरी	30.01.2007	2.29	30.50
		कुल		**40.38**	**555.40**
भिवानी	1.	कादमा से नौरंगाबाद जटां वाया गौशला कादमा	04.09.2006	3.73	41.08
	2.	धनाणा से मंढाणा	06.09.2006	6.40	75.76
	3.	खरकड़ी से सुई	23.11.2006	5.50	67.36
		कुल		**15.63**	**184.20**
फरीदाबाद	1.	झरसंथली से समयपुर	8.05.2006	2.40	32.28
		कुल		**2.40**	**32.28**
फतेहाबाद	1.	बूली बागड़िया से सदलपुर	08.02.2007	3.52	47.13
		कुल		**3.52**	**47.13**
झज्जर	1.	छारा से खरहर	21.12.2006	5.80	65.72
	2.	छारा से खेड़ी आसरा	09.01.2007	4.45	48.80
	3.	छुड़ाणी से खरमल	22.11.2006	3.00	39.84
	4.	गंगड़वा से बुपनिया	09.01.2007	4.00	48.43
	5.	लुकशर से मंडेला (दिल्ली बार्डर)	09.01.2007	1.25	14.41
	6.	खुंगई से खेरका	09.01.2007	4.25	47.75
	7.	गोयलया कलां से बुपनिया	09.01.2007	3.70	42.55
	8.	नंगला से जाहिदपुर	08.02.2007	3.90	43.98
	9.	कुटानी से दुमन	08.02.2007	3.60	41.95

1	2	3	4	5	6
[सरदार एच०एस० चट्ठा]					
	10.	लुकशर से गुभाणा	23.02.2007	1.00	12.76
	11.	असौदा से रोहद	01.05.2006	6.40	78.23
	12.	असौदा से दकोरा	02.05.2006	5.95	66.01
	13.	दकोरा से जसौरखेड़ी	18.05.2006	4.00	65.64
	14.	जसौरखेड़ी से भैसरू	27.06.2006	5.00	59.48
	15.	लहरावण से कड़ौली	18.07.2006	2.90	36.91
	16.	मंडौटी से जसौर	21.07.2006	9.00	123.65
	17.	सौलधा से सीदीपुर	09.01.2007	2.90	35.30
	18.	महराणा से गिरावड	22.11.2006	3.50	43.66
	19.	महराणा से छोछी	22.11.2006	3.80	47.72
	20.	छुबलधन से पहाड़ीपुर	27.11.2006	6.65	66.84
	21.	धौड़ से दुजाना	21.12.2006	4.05	51.64
	22.	अहरी से अमदलपुर (रिवाड़ी रोड तक)	16.06.2006	2.40	27.75
	23.	रायपुर से गिजरोद	07.07.2006	1.70	20.75
	24.	कासनी से ढकला	11.07.2006	3.40	41.69
	25.	पटौदा से कारोला	17.07.2006	4.60	57.53
	26.	मुंडसा से बाबा खुशीदास आश्रम	18.07.2006	2.00	20.16
	27.	डावला से रणखंडा	18.07.2006	2.30	27.90
	28.	पटौदा से गिरावड	25.07.2006	3.65	43.04
	29.	डावला से तलाव	25.07.2006	3.60	45.12
	30.	सरौला से जैतपुर	25.07.2006	4.15	45.11
	31.	सुरेटी से माछरौली	27.7.2006	6.30	81.15
	32.	सिलाणी (पाना जालिम) बाबड़ा	27.07.2006	4.55	62.14
	33.	सिरौला से अहरी (शेष कार्य)	22.11.2006	2.20	25.34
	34.	माछरौली से भाटेडा	22.11.2006	3.35	44.42
	35.	उटलौड़ा से झज्जर-सिलाणी गांव तक	27.11.2006	4.35	57.24
	36.	सिलाणी गेट एम०सी० आफिस झज्जर से सोलदा वाय बाबड़ा	21.12.2006	7.40	98.99
	37.	मारोत से भिंडावास	16.01.2007	3.80	51.50

1	2	3	4	5	6
	38.	स्यौला से बहरामपुर	17.01.2007	4.05	47.06
	39.	हिमायुपुर से झांसवा	18.01.2006	5.00	48.69
	40.	अकहेड़ी मदनपुर से रूडीयावास	18.01.2006	4.80	45.28
	41.	अकहेड़ी मदनपुर से नौगांव	18.01.2006	5.40	52.35
	42.	जमालपुर से मुरावास	18.01.2006	1.60	34.26
	43.	लिलाहेड़ी से कोयलपुर वाया मुंडाहेडा	18.01.2006	6.00	47.36
	44.	बिरोर से मुंडाहेड़ा	03.03.2006	3.85	38.03
	45.	कलीयावास से भागवी	15.06.2006	1.20	11.24
	46.	अकहेड़ी मदनपुर से झांसवा	27.06.2006	6.00	70.67
	47.	अकहेड़ीमदनपुर से बाबा भया समाध (शेष कार्य)	25.07.2006	1.30	8.23
	48.	ससरोली से झामरी	27.11.2006	5.80	65.62
		कुल		**193.85**	**2299.79**
जींद	1.	जीलगढ़ से शाहपुर	27.03.2006	3.65	44.21
	2.	भूसलाना से गोली	01.03.2006	4.20	57.32
	3.	डुमरखां खुर्द से तरखा	06.01.2006	3.50	36.90
		कुल		**11.35**	**138.43**
कैथल	1	रत्ताखेड़ा से बबकपुर (शेष कार्य)	16-11-2006	2.06	50.86
	2	कैलरम से गुलियाना वाया बालू	16-1-2007	15.00	232.70
	3	सोंगडी से संडील	27-6-2006	4.95	85.76
	4	पाई से सौंगल	19-7-2006	5.60	84.86
		कुल		**27.61**	**454.18**
करनाल	1	बांसा से जुंडला	25-10-2005	4.95	56.24
	2	बालू से सिंगड़ा	15-5-2006	2.86	39.89
	3	सनवल से हैबतपुर	29-11-2006	2.10	28.56
	4	नड़ाना (गोबिन्दगढ़ गांव से गांव शामगढ़ वाया चोपड़ी)	21-12-2006	6.04	88.95
	5	साम्बी से घोलपुरा	9-1-2007	4.40	55.39
		कुल		**20.35**	**269.03**

1	2	3	4	5	6
[सरदार एच०एस० चट्ठा]					
कुरुक्षेत्र	1	दाउमाजरा से स्टेट हाईवे (शेष कार्य)	7-12-2005	0.40	3.04
	2	किशनगढ़ से गोडियां	13-3-2007	1.41	18.19
	3	मोहनपुर से कड़ा साहब	26-7-2006	1.30	16.56
	4	ईसाक से सनसर	26-7-2006	3.25	41.23
	5	डेरा सुरेन्द्र चड्ढा से मैन हाईवे	26-7-2006	1.50	18.73
		कुल		**7.86**	**97.75**
मेवात	1	खोड़ी से टाकिया	8-5-2006	2.25	22.66
	2	सिंगलहेड़ी से खेरला पुन्हाना	8-5-2006	2.50	24.43
	3	जेतलका से मोतीकुई	9-5-2006	0.44	4.44
	4	सिरोली से झंडा	9-5-2006	2.34	26.89
	5	नीमखेड़ा से बडेड	9-5-2006	2.19	22.24
	6	ज्मालगढ़ से टीकरी	9-5-2006	1.30	15.13
	7	लोहिंगाकला से अंचवाड़ी	15-5-2006	3.08	30.21
	8	दोहा से दिल्ली अलवर रोड	15-5-2006	2.10	21.01
	9	सहिरी से पिपौली	23-5-2006	2.36	28.55
	10	बंडौली से टिकरी	9-8-2006	1.94	19.61
		कुल		**20.50**	**215.17**
पानीपत	1	जी०टी० रोड सिवाह से गोहाना रोड से डब्ल्यू०जे०सी० बाई पास का निर्माण	18-1-2006	4.94	176.25
		कुल		**4.94**	**176.25**
रिवाड़ी	1	जांट से दौलताबाद	17-4-2006	5.50	71.20
	2	नंदरामपुर बास से भटसाना	13-10-2006	3.18	44.61
	3	बावा से गाड़ा	30-1-2007	4.12	39.80
	4	भाल्हा से भगोत	30-1-2007	4.15	41.70
	5	लूला अहिर से जारौदा	20-4-2006	2.63	30.04
	6	जारौदा से लुखी	2-5-2006	4.50	52.36
	7	मुमताजपुर से खुरशीद नगर	8-5-2006	2.30	29.88
	8	जखौला से बहरमपुर	9-1-2007	3.10	35.62

1	2	3	4	5	6
	9	कोसली से नांगल पठाणी	16-1-2007	4.75	53.93
	10	भाकली से पी०डब्ल्यू० रोड जंकशन सी०एस०डी० कनटीन कौसली	17-1-2007	1.65	17.62
	11	भारंगी से लुखी	17-1-2007	2.90	35.13
	12	खुरशीद नगर से गोरिया	30-1-2007	1.95	22.29
		कुल		**40.73**	**474.18**
रोहतक	1	धार्मिक स्थान दादा दाय पाल से गांव अठैल	3-1-2007	0.65	20.63
	2	गिजी से नया बांस	9-1-2007	2.60	31.59
	3	गिजी से समचाणा	9-1-2007	4.45	47.79
	4	जी०जी०एस० स्कूल चुलियाणा से कारोर	9-1-2007	3.73	40.30
	5	अटैल से समचाणा	16-1-2007	4.48	50.63
	6	हसनगढ़ से जसोरखेड़ी	16-1-2007	5.15	57.22
	7	नौनद से बलियाणा	30-1-2007	3.70	45.24
	8	हसनगढ़ से निलोठी	8-2-2007	3.30	36.84
	9	गढ़ी से निगाणा	23-3-2006	4.60	45.62
	10	काहनौर से सिवाणा	27-3-2006	8.30	82.30
	11	सैंपल से बसाणा	17-4-2006	4.62	45.29
	12	ककराणा से बलम	12-5-2006	2.43	28.48
	13	अनावल से जिंदरान	1-6-2006	1.80	20.35
	14	सांगाहेड़ा से पिलाणा	2-6-2006	2.84	27.04
	15	निगाणा से धिलाणा	17-7-2006	4.40	43.61
	16	सांगाहेडा से सिवाणा	25-7-2006	3.70	35.91
	17	काहनौर से सांगाहेडा	14-11-2006	6.10	66.00
	18	जिंदराण से गुंडाण	29-11-2006	4.30	46.55
	19	चीड़ी से नांदल	25-7-2005	4.35	44.58
	20	खिड़वाली से चीड़ी	25-7-2005	6.45	54.68
	21	चमारिया से मकरौली कलां	25-7-2005	2.90	24.17
	22	चमारिया से ब्राहमणवास	25-7-2005	2.20	18.25

1	2	3	4	5	6
[सरदार एच०एस० चट्ठा]					
	23	मकरौली कलां से लाडोत	3-10-2005	1.73	15.93
	24	चमारिया से मकरौली कलां एन०एच० 71-ए तक	3-10-2005	1.63	13.59
	25	बोहर बोपाना से मंकरौली खुर्द	3-10-2005	4.30	35.69
	26	नांदल से हथवाला	3-10-2005	5.05	42.54
	27	सांघी से घिलौड कलां	3-10-2005	2.79	23.44
	28	नांदल से चांदी	3-10-2005	4.60	38.58
	29	बोहर से बलियाणा	19-10-2005	3.83	32.63
	30	कानी से दामड	19-10-2005	5.53	43.91
	31	मुंसी वाला से सांघी चीड़ी रोड	30-1-2006	1.40	12.29
	32	रूड़की से आसन	30-1-2006	4.80	33.94
	33	जसिया से दामड	30-1-2006	5.85	59.43
	34	गुसकाणी से भगवतीपुर	30-1-2006	5.40	44.88
	35	जसिया से खिड़वाली	30-1-2006	5.65	49.23
	36	बखेता से सिसांणा	30-1-2006	3.45	30.03
	37	सांघी से ब्राहमणवास	30-1-2006	6.00	54.75
	38	पोलंगी से मुंगान	30-1-2006	3.25	28.26
	39	लाडोल से बोहर	30-1-2006	5.12	44.55
	40	गोरड से फरमाणा	30-1-2006	4.80	42.29
	41	रूड़की से पाकसमा रोहतक सोनीपत रोड़ तक	30-1-2006	3.70	42.00
	42	भालौट से बलियाणा	30-1-2006	2.31	23.78
	43	पोलंगी से गोरड	30-1-2006	5.74	57.72
	44	घडोठी मोड से टिटौली से जींद रोड़	3-3-2006	1.83	16.20
	45	चीड़ी से चांदी	24-4-2006	3.70	48.20
	46	घडोटी पी०डब्ल्यू० रोड से कनाल रेस्ट हाउस चांदी	24-4-2006	2.87	35.01
	47	चीड़ी से घनाणा	1-5-2006	3.86	54.29
	48	बसन्तपुर से मकडौली कलां	1-6-2006	2.80	31.54
	49	नसीरपुर से सिसरौली	19-6-2006	2.32	24.71

1	2 3	4	5	6
	50 सांघी से कथूरा	23-11-2006	5.00	61.29
	51 भालौट से पाकसमा	23-11-2006	4.78	63.25
	52 धौला कुंआ टिटौली से खिड़वाली सिसरौली रोड	27-11-2006	2.67	32.55
	53 रूड़की आसन रोड़ से चांदवाला भाबड़ा रूड़की गांव	8-2-2007	0.50	5.66
	54 खरैन्टी से बैंसी	18-5-2006	5.80	80.23
	55 बैंसी से गिरावड़	18-5-2006	6.70	83.73
	56 कैनाल ब्रिज से रोहतक जींद रोड	29-11-2006	1.80	20.65
	57 मुरादपुर टेकना से बहु अकबरपुर	3-1-2007	2.20	25.87
	58 खरक जाटान से लाखन माजरा	16-1-2007	3.78	71.32
	59 भैणी चंदरपाल से खेड़ी महम	17-1-2007	2.28	24.86
	60 सींसर से साई	23-2-2007	4.04	43.09
	कुल		230.91	2405.06
सोनीपत	1 जागसी गंगाना रोड़ से जागसी सरफाबाद रोड़	1-5-2006	1.15	11.72
	2 जागसी से अहमदपुर माजरा	1-5-2006	3.06	34.01
	3 तयोडी से मोई	8-5-2006	2.80	36.47
	4 कैलाणा से सीलावाली	12-5-2006	3.40	47.14
	5 बड़ी से शाहपुर तेगा	9-1-2007	3.19	43.51
	6 राठधाणा से भालगढ़	28-2-2006	3.12	23.15
	7 फिरोजपुर बांगड़ से जठौला	20-4-2006	0.97	11.68
	8 कतलुपुर से हरेवाली गौशाला	19-6-2006	0.43	6.44
	9 बिदलाण से सालीमसर माजरा	18-9-2006	5.29	84.35
	10 चिमोली सिसाना-खरखौदा रोड़ खांडा ड्रेन के साथ	13-10-2006	1.74	24.75
	11 सिसाणा से समचाणा	9-1-2007	7.90	105.42
	12 गढ़ी सिसाणा से मोरखेड़ी	6-1-2007	3.95	57.01
	13 सलारपुर माजरा से भोला	20-4-2006	1.73	19.42
	कुल		38.73	505.07

Construction of Tourist Complex at Ateli Mandi

*586. **Sh. Naresh Yadav :** Will the State Minister for Forests be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a Tourist Complex at Ateli Mandi or Narnaul; if so, the time by which the above said proposal is likely to be started ?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : जी नहीं, श्रीमान्।

Opening Veterinary Hospital in Narnaul Constituency

*594. **Sh. Radhey Shyam Sharma :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open new Veterinary Hospital in Narnaul Constituency ?

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) : जी हां, श्रीमान्।

Atrocities on Down-Trodden

*599. **Dr. Sushil Indora :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether the number of incidents of atrocities on down-trodden increased during the tenure of present Govt.

(b) wether it is a fact that the people belonging to the down-trodden community have changed their religion or have been displaced as a result of the said atrocities ; and

(c) the steps taken by the Govt. to provide the security to the down-trodden community in the State ?

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : (क), (ख) व (ग) वांछित सूचना सदन के पटल में रखी जाती है।

सूचना

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(ग) राज्य में शान्ति एवं स्थिरता का वातावरण है और सभी समुदाय के लोग पूर्ण भाईचारे व एकता के साथ रह रहे है। जब भी कोई झगड़ा या सामाजिक विषमता उत्पन्न होती है तो दलित वर्ग के लोगों को तुरन्त जरूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त दोषी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही की जाती है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Industrial Units of Dudhola, Pirthla and Dhatir Villages

59. Shri Karan Singh Dalal : will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names and addresses of industrial units operating in the revenue estates of Dudhola, Pirthla, and Dhatir Villages of Palwal Tehsil which are extracting groundwater for their industrial process; and

(b) the number of units in part (a) above have been permitted for extracting groundwater alongwith the quantity of water thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) ऐसी इकाईयों के नाम व पते निम्न प्रकार से है :--

नाम	पता
मैसर्स एम०पी० टैक्स प्रिन्ट	ग्राम धुधोला
मैसर्स जे०डी० सन्स स्टील्स	ग्राम पिरथला
मैसर्स एम०बी०डी० पेपर मिल्स	ग्राम धतीर
मैसर्स वीर ह्यूज	ग्राम धतीर
मैसर्स हाई पोलीमर लिमिटेड	ग्राम धुधोला
मैसर्स गुप्ता एक्सिम	ग्राम पिरथला

(ख) भूमिगत-जल निकालने के लिए अनुज्ञा केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण द्वारा दी जाती है। ये इकाईयां नगर निगम सीमा से बाहर स्थित हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास भूमिगत-जल निकालने की मात्रा की अनुज्ञा के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा उद्योगों के रिकार्ड से एकत्रित की गयी सूचना के अनुसार भूमिगत-जल निकालने की मात्रा निम्न प्रकार से है। वैसे कोई प्रमाणित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है :--

इकाई का नाम	मात्रा किलोमीटर/प्रतिदिन में
मैसर्स एन०पी० टैक्स प्रिन्ट, ग्राम धुधोला	110
मैसर्स जे०डी० सन्स स्टील्स, ग्राम पिरथला	20
मैसर्स एम०बी०डी० पेपर मिल्स, ग्राम धतीर	890
मैसर्स वीर ह्यूज, ग्राम धतीर	20
मैसर्स हाई पोलीमर लिमिटेड, ग्राम धुधोला	225
मैसर्स गुप्ता एक्सिम, ग्राम पिरथला	625

Details of Developers of Special Economic Zones

60. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minster for Industries be pleased to state—

(a) the details of the Developers of Special Economic Zones granted formal approval and in Principal approval for establishing in Haryana State till date alongwith their site and the required land ; and

(b) the details of villages required to be shifted in the areas of the SEZ's in (a) above ?

उद्योग मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा) :

(क) अब तक भारत सरकार द्वारा हरियाणा राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिये 19 औपचारिक तथा 30 सैद्धान्तिक विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अनुमति प्रदान की गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में आने वाले गावों तथा वांछित भूमि का विवरण अनुंलग्नक-1 पर संलग्न किया गया है।

(ख) उपरोक्त (क) में किसी भी अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी भी विकासक से गांवों को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुलग्नक-1

विशेष आर्थिक क्षेत्र जिनको हरियाणा राज्य में औपचारिक/सेधान्तिक अनुमति प्रदान की गई के विकासकों, उनके स्थान, वांछित भूमि और गांवों सहित विवरण :—

औपचारिक अनुमति :

क्र० सं०	विकासक का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र एकड़ में	विशेष आर्थिक क्षेत्र की श्रेणी	पूंजी निवेश (करोड़ो में)	गांव
1	2	3	4	5	6
1.	मै० हरियाणा टैक्नोलोजी पार्क, फरीदाबाद में	8.25	आई०टी० एण्ड आई०टी०ई०एस०	317	एम सी एरीया, देहली मथुरा रोड़ फरीदाबाद
2.	मै० उपपल डवलपर प्रा० लि० गुड़गांव में	269	बहु सेवाऐं	1547	राठीवास, भोड़ाकलां एण्ड भुड़का
3.	मै० ओरिण्ट क्रॉफटस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० गुड़गांव में।	283.643	टैक्सटाईल	2000	बांस हरिया झुण्डसारी एण्ड भांगरोलीया
4.	मै० लक्जर साईबर सिटी प्रा० लि० गांव शिकोहपुर में	67.02	आई०टी० एण्ड आई० टी०ई०एस०	1500	शिखापुर
5.	मै० डा० फ्रेश हैल्थकेयर प्रा० लि० गुड़गांव में	57.893	आई०टी० एण्ड आई० टी०ई०एस०	760	धामरौज, सोहना रोड़

1	2	3	4	5	6
6.	मै० डी०एल०एफ० सिलोखरा गुड़गांव में	30 (12.14एच०)	आई०टी० एण्ड आई० टी०ई०एस०	345	सिलोखरा, सैक्टर 30, गुड़गांव
7.	मै० डी०एल०एफ० साईबर सिटी गुड़गांव में	26 (12.54 एच०)	आई०टी० एण्ड आई० टी०ई०एस०	563	सैक्टर 24-25, गांव नाथपुर
8.	मै० सनवाईज प्रोपर्टीज प्रा० लि० गुड़गांव में	25.01 (10.12 एच०)	आई०टी० एण्ड आई० टी०ई०एस०	450	आर डी सिटी, ग
9.	मै० पाईनीर अर्बन लैण्ड एण्ड इन्फ्रा लि० गुड़गांव में	100 (40.48 एच०)	आई०टी० एण्ड आई० टी०ई०एस०	2310	गांव घाटा, नजदीक पालम
10.	मै० आंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फरास्ट्रक्चर लि० जिला सोनीपत।	250 (100 एच०)	यान्त्रिक वस्तुऐं टी०ई०एस०	582.30	भीगन एवंशाहिबपुर, नजदीक मुरथल
11.	मै० एस्सोटेक रीयेल्टी प्रा० लि० जिला गुड़गांव में	27.75 (10.62 एच०)	आई०टी० एण्ड आई० टी०ई०एस०	275.69	भौंडसी तहसील गुड़गांव
12.	मै० ग्लोबल हैल्थ प्रा० लि० गुड़गांव में	43 (17,43 एच०)	बायो टैक्नोलोजी, सैक्टर सपैसिफिक	650	सैक्टर 38, गुड़गांव
13.	मै० मैट्रो वैली बिजनिस पार्क प्रा० लि० गुड़गांव	25.70 (10 एच०)	आई०टी० एण्ड आई० टी०ई०एस०	375	ग्वाल पहारी, फरीदाबाद-गुड़गांव रोड
14.	मै० आंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फरास्ट्रक्चर लि० बादशाहपुर गुड़गांव।	27 (10.93 एच०)	आई०टी० एण्ड आई० टी०ई०एस०	582.30	बादशाहपुर
15.	मै० एसकैंट एस्टेट प्रा० लि० गुड़गांव	38 (15.2 एच०)	आई०टी० एण्ड आई० टी०ई०एस०	800	सैक्टर-66, सोहना रोड
16.	मै० आरीजी इन्वैस्टमैंट होलडिंग-III लि० गुड़गांव	100 (40 एच०)	इलैक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर आई०टी० एण्ड आई०टी०ई० एस०	1600	घाटा, भैरमपुर, गुजर सोहना
17.	मै० पार्श्वनाथ डवलैपर प्रा० लि० गुड़गांव में।	114 (46.13 एच०)	आई०टी० एण्ड आई० टी०ई०एस०	599	मोहम्दपुर गुजर सोहना
18.	मै० सनसीटी प्रोजैक्ट प्रा० लि० गुड़गांव में	102 (41,278 एच०)	आई०टी० एण्ड आई० टी०ई०एस०	81.60	झुण्ड सराय
19.	मै० बेनटैक्स प्रोजैक्टस प्रा० लि० गुड़गांव	421 (168 एच०)	मल्टी सर्विस	1623	रोजका गुजर, तहसील सोहना
20.	मै० गुड़गांव कवैशन सिटी प्रा० लि० धनवापुर गुड़गांव में	600 (240 एच०)	सर्विस एस० सी० जेड०	3965	धनवानपुर, अलावादी
21.	मै० एस०आर०एम० प्रा० लि० मेवात नूंह में।	2500 2500	बहुउत्पाद	500	1, इंद्री, अटटा 2. धासेरा, खारोन, रीटाओरा, बरना, हिरमतला

1	2	3	4	5	6
	[श्री लछमन दास अरोड़ा]				
22.	एच०एस०आई०डी०सी० तथा मै० रिलायंस लि का संयुक्त उपक्रम झज्जर तथा गुडगांव में।	25000 (10000एक०)	बहुउत्पाद	25.200	गुडगांव ज़िला: मुबारकपुर, झंझरौला, सुलतानपुर, इब्राहिमपुर कालीयावास मकडौला, वघुरा चन्द, सड्डराना, धड़ी, हासरु, गरौली कलां, धनकोट, ब्रसई, खेडकी माजरा, धनकोट, नरसिंगपुर, मोहम्मदपुर झारसा, खांडसा, धरौली खुर्द, सिही, हैयतपुर, बजीरपुर, खेखरी दौला। झज्जर जिला : बादली, दरियापुर, लगारपुर, दवेरखाना, लौहत, बादसा, मुण्डाखेरा, इसमैलपुर, मोहमदपुर माजरा, फतेहपुर, खेलपुर, याकुबपुर, सौंधी, निमाना, पलहपा, लाडपुर, फैजापुर, मुनीमपुर कुकडौला, ममनौला, बिरादरी, शिवोजीपुरा, खादरी टो।
23.	मै० डी०एल०एफ० यूनिवर्सल लि० गुडगांव में	20000 (8097 एक०)	बहुउत्पाद	26000	पटोदी, नरहेरा, मोरा, कलां, बिनौला, खुम्मनवास, कौकालवास, घोषगढ, जौरी समपकी तथा अटौली, देहली जयपुर रोड।
24.	मै० डी०एल०एफ० यूनिवर्सल लि० अम्बाला में।	2500 (1012एक०)	बहुउत्पाद	1950	मंडहोर, पिंजौखरा तथा ख कतौली, नारायणगढ रोड, नजदीक बलदेव नगर

1	2	3	4	5	6
25.	मै यूनिटेक कामर्शियल डवैलपर्स लि कुण्डली सोनीपत में।	10000 10000 (40000 एच०)	बहुउत्पाद	22000	मंदरी, मंडौरा, अचासपुर, छतौरा, अट्टरपुर, अकबरपुर, बरेटा, जथेरी, बाजीपुर, साबु, 1, सफीयाबाद पाना पापसन, सफीयाबाद, खेरी मनजाश, खेरीमाना जाट, मालाह माजरा, नाहरा, इललापुर, नाहरी, दिरखी, मुनीरपुर, कटलपुर, झींझौली।
26.	मै० डी०एस०सी० कंसट्रैशन लि० पलवल में	12500 (5000एच०)	बहुउत्पाद	9816	झज्जु नगर, अटोहन, लुधारी, नग्गल, बराहमन, लाडिका, खेखड़ा, फिरोजपुर, बाटा, सिलौथी, मुस्थाबाद, अटवा, रहीमपुर, टीकरी, गुतर, रसूलपर, बिलोचपुर, काशीपुर, फिरोजनपुर, मिस्सा, सुल्तानपुर ऑफ पलवल तहसील विकासक ने सूचित किया है कि वह एस०सी० जैड का क्षेत्र बदलना चाहते हैं।
27.	मै० रहेजा हरियाणा एस०ई० जैड डवलैपर प्रा०लि० धारूहेड़ा।	5000 (2000एच०)	बहुउत्पाद	2602	देहली जयपुर रोड
28.	मै० इम्मार एम०जी०एफ० लैण्ड प्रा० लि०, शिकोहपुर, गुडगांव।	250 (100 एच०)	आई०टी०एण्ड आई० टी०ई०एस०	-	शिखोपुर, गुडगांव
29.	मै० इम्मार एम०जी०एफ० लैण्ड प्रा०लि०, हरियाणा गुडगांव।	70 (28एच०)	आई०टी०एण्ड आई० टी०ई०एस०	-	गांव के नाम अभी सूचित नहीं किये।
30.	मै० इम्मार एम०जी०एफ० लैण्ड प्रा०लि०, खेड़की दौला, गुडगांव।	50 (20एच०)	आई०टी०एण्ड आई० टी०ई०एस०	-	खेड़की दौला, गुडगांव
31.	मै० इम्मार एम०जी०एफ० लैण्ड प्रा०लि०, भौंडाकलां, गुडगांव।	10000 (4000एच०)	बहुउत्पाद	-	भौंडा कलां बिलासपुर भरहेरा, सिदरावाली, पैथहरी, लोकरा, कपरीवास, मालपुरा तथा अकलौरा।

1	2	3	4	5	6
	[श्री लछमन दास अरोड़ा]				
32.	मै० इम्मार एम०जी०एफ० लैण्ड प्रा०लि०, जहाजपुर, गुड़गांव।	5000 (2000एच०)	बहुउत्पाद	खेरकी कलां	बसई, धनवापुर, नरहेरा, खेरक माजरा, टीकमपुर, महोमदहेदी, बाबूपुर, दौलताबाद, धर्मपुर, गोपालपुर, चंदू, बुढेरा, चौमा बजगहेरा तथा जहाजपुर
33.	मै० इम्मार एम०जी०एफ० लैण्ड प्रा०लि०, लखनौला, गुड़गांव।	600 (240एच०)	आई०टी०एण्ड आई० टी०ई०एस०	-	लखनौला, गुड़गांव
34.	मै० इम्मार एम०जी०एफ० लैण्ड प्रा०लि०, मच्छीगढ़, भूपानी फरीदाबाद।	250 (1000एच०)	बहुउत्पाद	-	मच्छीगढ़, नवादा टीगान, भुखांपुर, टीगोह, सदपुरा, फरीदपुर, खेरखरीकलां, नचौली, भूपनी, दयालपुर तथा मासकाला
35.	मै० इम्मार एम०जी०एफ० लैण्ड प्रा०लि०, बांस कुशला, गुड़गांव।	200 (100एच०)	आटो एंसेलरी टी०ई०एस०	-	बांसकुशला, गुड़गांव
36.	मै० इम्मार एम०जी०एफ० लैण्ड प्रा०लि०, बांस हरिया गुड़गांव।	300 (120एच०)	आई०टी० एण्ड आई० टी०ई०एस०	-	बांस हरिया, गुड़गांव
37.	मै० इम्मार एम०जी०एफ० लैण्ड प्रा०लि०, नवादा फतेहपुर, गुड़गांव।	100 (40एच०)	जैम एण्ड जवैलरी	-	नवेदा फतेपुर, गुड़गांव
38.	मै० रोज न्यू प्रमोटर्स लि०, गुड़गांव में।	110 (44एच०)	क्षेत्र आई०टी० एण्ड आई०टी०ई०एस० के लिये निर्धारित	431.80	कासन खाना
39.	मै० नताशा हाउसिंग एण्ड अर्बन डवलैपर लि० करनाल।	2500 (1000एच०)	बहुउत्पाद	2600	गांव के नाम अभी सूचित नहीं किये।
40.	मै० सनसीटी प्रोजैक्ट प्रा०लि० अम्बाला	8100 (3237.48)	बहुउत्पाद एस० सी० जेड	16404	गाव के नाम अभी सूचित नहीं किये।
41.	मै० यूनिटैक रियलटी प्रोजेक्ट लि० गुड़गांव में	26	आई०टी० एण्ड आई०टी०ई०एस०	499	गांव टिकवरी, ढुंढाहेरा
42.	मै० ओरियन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० गुड़गांव में	250.70 (130 एच०)	आई०टी० एण्ड आई०टी०ई०एस० बायो-टैक्नोलोजी	2285.50	गांव बंदहवारी, सोहना रोड
43.	मै० आई०एस०टी० लि० गुड़गांव में	28	आई०टी० एण्ड आई०टी०ई०एस०	535	ढुंढाहेरा
44.	मै० विपुल लि० गुड़गांव में	150 (60एच०)	आई०टी० एण्ड आई०टी०ई०एस०	550	फाजीलपुर, भरमपुर

1	2	3	4	5	6
45.	मै० पार्श्वनाथ डवलैपर प्रा० लि० कुण्डली में	250 (100एच०)	खाद्य प्रसंकरण क्षेत्र निर्धारित	176	पबसारा, झकौली, मनौली, कदमपुरा
46.	मै० रहेजा डवैलपर्स लि० गुडगांव में ।	327 (132एच०)	इलैक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर एवं आई	2855	धादा
47.	मै० रौफमैन प्रोजैक्ट लि० कुण्डली में	250 (100एच०)	बहुसेवाऐं	1258	नजदीक मानेसर, जयपुर देहली हाईवे
48.	मै० श्रीओम जी रियल इस्टेट प्रा० लि० फारूखनगर जिला गुड़गांव में	252 (101एच०)	सैक्टर सपेसिफिक ऐपेरल	447	सैदपुर, मोहम्मदपुर, फारूखनगर
49.	मै० श्रीओम जी डवैलपर प्रा० लि० फारूखनगर जिला गुड़गांव में	252 (101एच०)	सैक्टर सपेसिफिक आइटोमोटिव	447	सैदपुर, मोहम्मदपुर, फारूखनगर

F.I.R. in City Police Station Sirsa

68.Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether a F.I.R. No. 46 dated 14th June, 2005 has been registered in City Police Station, Sirsa for grabbing the lands of Dakshin Haryana Vidyut Parasaran Nigam,

(b) if so, the names and addresses of all the persons in the said F.I.R.; and

(c) whether all the above named persons have been arrested ; if not, the reasons thereof ?

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : (क), (ख) व (ग) वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) हां मुकदमा नं० 416 दिनांक 14.6.2005 न कि मुकदमा नं० 46 दिनांक 14.6.2005 धारा 448/148/149/427/506/420/467/395 भा०द०स० एवं 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना शहर सिरसा कार्यकारी अभियन्ता ''ओ०पी०'' एस/यू दक्षिण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, सिरसा की शिकायत पर नामालूम लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया।

(ख) मुकदमा नामालूम लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया।

(ग) अनुसंधान के दौरान स्थानीय पुलिस एवं राज्य अपराध शाखा द्वारा निम्नलिखित लोगों को गिरफ्तार किया गया :-

1. बृजलाल पुत्र श्री रामेश्वर दास अग्रवाल वासी अग्रसेन कालोनी, सिरसा।
2. हरीश कुमार पुत्र मदन लाल अरोड़ा वासी सिरसा।
3. गोविन्द कुमार कान्डा पुत्र मुरलीधर कान्डा वासी हिसारिया बाजार सिरसा।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

4. सुशील कुमार पुत्र राम शरण ब्रह्मण वासी किर्ती नगर सिरसा।

5. विजय कुमार पुत्र पूर्णमल महाजन वासी इन्दपुरी मोहल्ला, सिरसा।

6. अजय कुमार पुत्र भगत राम वासी जनता भवन सिरसा।

7. राम निवास पुत्र लाल चन्द अग्रवाल वासी अशोक विहार दिल्ली।

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ द्वारा गोविन्द कुमार कान्डा पुत्र मुरलीधर कान्डा को दिनांक 25-7-2005 को अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश; सिरसा श्री आर०एस० बागडी ने सुशील कुमार पुत्र राम शरण ब्रहामण, विजय कुमार पुत्र पूर्णमल महाजन, अजय कुमार पुत्र भगत राम व राम निवास पुत्र लाल चन्द अग्रवाल को दिनांक 25-6-2006 को जमानत दी गई है। अनुसंघान के दौरान पाया गया कि गोविन्द कुमार कान्डा पुत्र मुरलीधर कान्डा घटना के समय मौका पर मौजूद नहीं था। मुकदमा का अनुसंधान राज्य अपराध शाखा, हिसार द्वारा अमल में लाया जा रहा है।

इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्यों के आचरण तथा व्यवहार की निन्दा करना

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर विपक्ष के साथी बैठे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कई निर्दलीय विधायक भी बैठे हुए है लेकिन इण्डियन नैशनल लोकदल के साथियों ने जिस प्रकार का व्यवहार सदन में किया है वह प्रजातान्त्रिक परिपाटी और लोकतान्त्रिक मूल्यों का हनन है। जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने यहां पर किया है। वह सोची समझी नियत के साथ सदन की कार्यवाही में विघ्न डालने के लिए किया गया है। स्पीकर सर, करीब डेढ़ घण्टा बोलने का समय माननीय सदस्य श्री औम प्रकाश चौटाला को दिया गया (विघ्न) उसके बाद भी आपने फिर दरियादिली और फ्राखदिली दिखाई। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने भी आपसे अनुरोध किया कि आपकी रूलिंग के बावजूद भी उनको बोलने का मौका दिया जाए। स्पीकर सर, आपने भी बहुत उदारता दिखाई और उनसे कहा कि दोबारा सदन में अपनी बात कहें क्योंकि हरियाणा के लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं। सभी लोग चुन कर आए हैं और वे अपनी बात कहें, अपने क्षेत्र की बात कहें और जो जन समस्याएं हैं उनको यहां पर उजागर करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि महामहिम राज्यपाल जी ने सरकार का जो विजन डाकुमैंट हाउस में पेश किया था उसके बारे में नीतिगत सुझाव और कुछ रचनात्मक सुझाव, प्रान्त को आगे ले जाने वाले कुछ सुझाव देते, अपने-अपने क्षेत्रों में प्रगति के कुछ सुझाव देते जैसे कि दूसरी पार्टियों के विधायकों तथा निर्दलीय विधायकों ने दिये। स्पीकर सर, आपने तो यहां तक फ्राखदिली दिखाई कि उनके नेता के अलावा उनके सारे सदस्यों को भी यह कहा कि वे सारे साथी 8-10 मिनट तक बोल सकते हैं। आपने उनको अलॉटिड समय से चार गुणा से फालतू समय बोलने के लिए दिया लेकिन फिर भी एक सोची समझी नियत के अनुसार उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। ऐसा लगता था कि वे सदन की कार्यवाही में केवल व्यवधान डालने के लिए ही आये थे। न उनका रचनात्मक सुझावों से वास्ता था और न ही महामहिम गवर्नर साहब का जो विजन डाकुमैंट है जो सरकार की नीतियों को लेकर आये हैं उससे कोई वास्ता है। उनका केवल एक ही निशाना है कि चेयर पर एक्सपर्शन कॉस्ट करना चाहिएं और सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देना है। मुझे लगता है कि लोकतन्त्र की परिपाटी का हनन हुआ है। स्पीकर सर, यह बड़ा ही दुखद दिवस

है कि उसके बाद वे सदन से बहिर्गमन कर गए। केवल एक सदस्य को उनके व्यवहार के कारण नेम किया गया था बाकी के सदस्य के सदस्य बोले पर चौधरी औम प्रकाश चौटाला जिन्हें आपने बोलने के लिए समय दिया था वे अपने कागज उठा कर हाउस से बाहर चले गए। सम्भवतः उन्होंने यह निर्णय भी इसलिए कर लिया क्योंकि उनको पता था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी उनकी सब बातों का जवाब देंगे। आज अन्य माननीय सदस्यों ने भी बोलना था। विपक्ष के सारे सदस्य कल बोले और अध्यक्ष महोदय, आपने निर्दलीय विधायकों को भी बोलने का पूरा समय दिया। उनको चाहिए था कि वे लोग यहां पर बैठते और अपने कारनामे सुनते। वे यह भी सुनते कि किस तरह के कंस्ट्रक्टिव काम, किस तरह से ऐसे काम इस सरकार ने किये हैं। जिनसे प्रान्त और प्रान्त के लोग आगे जाएंगे, माननीय मुख्यमन्त्री जी का गवर्नर साहब के एड्रैस पर जवाब सुनते। स्पीकर सर, ऐसा लगता है कि जिस मानसिकता के चलते वे यहां सत्तापक्ष से उठ कर उस तरफ चले गये उनके कुछ लोग अपनी मानसिकता कभी बदल नहीं पाएंगे और वहां पर भी एक ऐसी संख्या में चले गये कि उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा तक नसीब नहीं हुआ। स्पीकर सर, दो साल बीत जाने के बाद भी देश और विदेश की सैर करने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि वे अपनी मानसिकता को त्यागने में अभी असमर्थ हैं। स्पीकर सर, हम तो सदन के सभी सदस्य उस परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे विधायकों को सद्‌बुद्धि दे कि वे कुछ अन्तरमन्थन भी करें, कुछ अपने गिरेबान के अन्दर भी झांकें और कुछ यह भी देखें कि उनके कारनामें क्या थे उनके तो चाहिए था कि अपने कारनामों की मुआफी मांगते और आगे बढ़ कर सदन के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को कहते कि आईये हुड्डा साहब हम सब मिल कर आपकी सरकार के साथ इस प्रान्त को आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करें और हम इसमें भागेदारी देंगे परन्तु वे ऐसा नहीं कर पाए इसके लिए हमें बड़ा खेद है।

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक विपक्ष के साथियों का सवाल है जो अब हाउस के अन्दर उपस्थित नहीं है, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने प्रजातन्त्रिक मूल्यों को दरकिनार किया। मैं चार दफा पार्लियामैंट का मैम्बर रहा, दो दफा इस असैम्बली का सदस्य रहा हूं और विपक्ष में भी बैठा हूं तथा आज सत्ता पक्ष में भी हूं। यह पहला मौका है कि क्वैश्चनेयर में 3-3 और 4-4 प्रश्न जिन साथियों के हों और वे जानबूझ कर सदन से गैरहाजिर हों। जो महत्वपूर्ण सवाल थे और साथी सरकार से जनहित के मुद्दों के बारे में पूछ सकते थे लेकिन जनहित के सवालों को पूछने के लिए भी वे लोग यहां हाउस में नहीं पहुंचे जो कि बड़े खेद की बात है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सदन में संसदीय कार्य मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो बात विपक्ष के साथियों के बारे में कही है मैं उस चलती बात में यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में यह मशहूर है कि ओम प्रकाश चौटाला और उनके सदस्यों को समझाना ऊंट को रेल में बिठाने जैसा है या यूं भी कह सकते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है।

ओलावृष्टि तथा भारी वर्षा के कारण फसलों के हुए नुकसान सम्बन्धी मामला उठाना

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हरियाणा में ओलों से और बारिश की वजह से जो फसल बर्बाद हुई है उसमें तमाम हरियाणा

[**श्री कर्ण सिंह दलाल**]

के किसानों का नुकसान हुआ है और मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में उनके नुकसान की भरपाई करने की घोषणा की है। यह सरकार उनके नुकसान की भरपाई के लिए बजट में भी प्रावधान करने जा रही है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कृषि विभाग किसानों के नुक्सान की भरपाई करने के लिए अलग से उन किसानों को कोई अच्छी किस्म के बीज या अगली फसल जो बोई जानी है उससे सम्बन्धित अच्छी क्वालिटी के बीज देने के बारे में विचार कर रहे हैं। अगर ये ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं तो ये कौन-कौन सी फसलों के बीजों को देने का प्रावधान कर रहे हैं और उन बीजों के क्या क्या नाम हैं ?

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि मैंने आज के एक अंग्रेजी अखबार में पढ़ा है कि ओम प्रकाश चौटाला ने प्रैस में जाकर यह बात कही है कि स्पीकर साहब मैम्बरों को मेरे ऊपर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस बारे में हाउस को नोटिस लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, यह पता नहीं क्या-क्या कहते हैं। अगर उनकी हर बात का नोटिस लेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, यह जो महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सदन में रखा गया है इसमें इस सरकार के दो साल के अचीवमैंट और इनके द्वारा किए गए कारनामों का लेखा जोखा है।

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, अभी गवर्नर एड्रैस पर डिस्कशन शुरू नहीं हुई है यह तो जीरो ऑवर चल रहा है।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं जीरो ऑवर में भी अपनी बात कहना चाहता हूं कि यह जो हरियाणा में ओला पड़ा है, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और हमारे पास इस बारे में टैलीफोन आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 1995 में एक बहुत बड़ी तबाही हरियाणा में हुई थी। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त जिसके पास एक भी टयूब्वैल नहीं था वह आठ-आठ टयूब्वैल के पैसे लेकर चला गया था और असल में जिसके पास टयूब्वैल था उसको कुछ नहीं मिला था। मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि सही ढंग से सर्वे करवाएं और असल में जिसका नुकसान हुआ है उसको ही मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे यहां पर जो सीरी भाई और लेबर्ज हैं जिनकी दशा बहुत खराब है उनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। उनको भी सरकार की तरफ से कोई मुआवजा दिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में गिरदावरी चल रही है। जिसके नाम पर गिरदावरी होगी उसी को पैसा मिलेगा। बाकी जो गौतम ज़ी कह रहे हैं तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह आपस की बात है हम उसको आपस में बैठकर भी हल कर सकते हैं। दूसरे जो कमजोर वर्ग के लोगों के बारे में इन्होंने कहा है तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार कमजोर वर्गों के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि उनको रोजगार मिले। ऐसे प्रयास हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। जहां तक ओलावृष्टि और फलड से हुए नुक्सान की बात है तो यह बात सही है कि काफी फसलों का इनसे नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मैं आज ही

हाउस एडजर्न होने के फौरन बाद महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी जिलों में या दूसरी जगहों पर जा रहा हूं। मैं खुद देखकर आऊंगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चड्डा साहब, इस बारे में कुछ इंफोर्मेशन बता रहे हैं। आप उनको बताने दें।

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चड्डा) : स्पीकर सर, सदस्यों ने आपकी मार्फत यह पूछा है कि ओलों से फसल मरने की वजह से या बारिश की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट किसानों को क्या-क्या सुविधाएं दे रहा है। मैं आपकी मार्फत दलाल साहब को बताना चाहूंगा कि पिछली दफा जब चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट को देखा तो पाया कि पिछले पांच साल में प्रोडक्विविटी एकड़ के हिसाब से नीचे ही नीचे जाती जा रही है। कहीं पर एक एकड़ में डेढ़ क्विंटल या कहीं पर तीन क्विंटल यह पहुंच गयी थी। इसके बाद इन्होंने आदेश दिए और इसीलिए पिछली बार हमने तीन हजार क्विंटल ढैंचे का बीज किसानों को मुफ्त में दिया था। इस बार रेन ज्यादा होने की वजह से भी बहुत ज्यादा फसलों का नुक्सान हुआ है। हमने बैठकर मुआवजा देने के बारे में फैसला किया है। लेकिन रात को ही और ज्यादा ओले पड़ गये हैं इसलिए फिर हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। जब सारी फिगर्ज हमारे पास आ जाएंगी तो हम देखेंगे कि क्या-क्या और सुविधाएं हम किसानों को दे सकते हैं। अभी तक तो हमने ढैंचे का बीज ही किसानों को मुफ्त दिया था। हम सारे हिन्दुस्तान से इसका बीज खरीद रहे हैं। पूरे हिन्दुस्तान में और कोई स्टेट नहीं है जिसने किसानों को मुफ्त ढैंचे का बीज दिया हो।

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, ढैंचे के बीज से किसानों को क्या आमदनी होगी ? इसलिए मेरा कहना यह है कि कोई ऐसा बीज किसानों को दिया जाए जिससे कोई और फसल किसान बो सकें।

सरदार एच०एस० चड्डा : स्पीकर सर, मैंने इनकी बात सुनी है। इन्होंने यही बात कही थी कि ओले पड़ने की वजह से सरकार किसानों को और क्या क्या सुविधाएं दे सकती हैं। जो भी सरकार कर सकती है वह हम जरूर करेंगे। (विघ्न)

श्री नरेश मलिक : स्पीकर सर, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने घोषणा की कि वह स्वयं फील्ड में जाकर फसलों के हुए नुक्सान को देखेंगे। इस बारे में सरकार ने आश्वासन दिया है इसलिए इस नुकसान की भरपायी तो सरकार करेगी ही लेकिन मैं इस बारे में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस किसान की अब फसल नहीं रही है तो वह कैसे अपने ट्रैक्टर वगैरा का ब्याज दे पाएगा ? सरकार ने जो 30 जून तक सहकारी ऋणों पर मूलधन जमा करवाने पर सारे ब्याज की माफी की घोषणा की है, मेरा निवेदन है कि अब तो किसान यह पैसे जमा नहीं कर पाएगा इसलिए सरकार इस अवधि को बढ़ा दें ताकि किसान इसको आगे भी मेनटेन कर पाए। अब फसल न होने की वजह से ट्रैक्टर या दूसरी चीजों के लिए उसने जो लोन ले रखा है उसका वह ब्याज नहीं दे पाएगा। इसलिए सरकार इस बारे में भी किसानों पर दरियादिली दिखाए और इस बारे में ध्यान दें।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : स्पीकर सर, मेरी भी पब्लिक इम्पोर्टैन्स से संबंधित एक बात है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और कंसर्ड मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि जो ओलावृष्टि और बारिश के पानी से फसलों के नुकसान की स्पेशल गिरदावरी दोबारा से करवाने के आदेश दिए

[प्रो० छत्तरपाल सिंह]
हैं वह बहुत अच्छी बात है लेकिन इसमें अकसर एक अनियमितता रह जाती है। पटवारी मनमाने तरीके से गिरदावरी करते हैं। पिछले साल भी इस बारे में काफी शिकायतें आयी थीं। हिसार जिले में मीरका और न्याना गांव की भी इस बारे में शिकायत रही थी। मीरका गांव की शिकायत तो अभी भी पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, पटवारी अपनी मर्जी से गिरदावरी करके गिरदावर को इंफोर्म कर देते हैं और जब मुआवजा मिलता है तो किसान को पता लगता है कि उसकी पूरी फसल की गिरदावरी नहीं हुई है। अगर किसी किसान की चार एकड़ जमीन की गिरदावरी होनी चाहिए थी तो उसकी केवल दो एकड़ जमीन की गिरदावरी ही हो पाती है। अगर किसी का खेत एक एकड़ में था तो उसको 3 एकड़ का मुआवजा मिला है। पटवारी गिरदावर को गिरदावरी करके देता है। उसको सार्वजनिक रूप से गिरदावर को इन्फॉर्म करने के साथ किसान को भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपके खेत का हमने इतना मुआवजा असैस किया है ताकि किसान की संतुष्टि मौके पर ही हो जाए।

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अब हम गांव में मुनादी करवाएंगे ताकि जो भी बात हो वह गांव के लोगों के सामने हो। उसमें यदि कोई शिकायत आएगी तो उसकी बाकायदा गिरदावरी पटवारी करता है और उसको गिरदावर भी चैक करता है, तहसीलदार भी चैक करता है, एस०डी०एम० और डी०सी० भी चैक करता है। आपके पास इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो आप भी हमें बताएं, हम अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, फसलों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है और इसको देखते हुए हमने केन्द्र सरकार से भी यह कहा है कि प्रिक्योरमैंट की प्राइज में भी इजाफा किया जाए यह प्राइज 750 की बजाय ज्यादा किया जाए और इस बारे में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री सुखबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसे पटवारी गलत गिरदावरी कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह बात आ चुकी है। आप रिपीटिशन न करें।

श्री सुखबीर सिंह : जैसे बी०पी०एल० का दोबारा सर्वे हुआ है। बी०पी०एल० कार्ड बनाने में जिन्होंने गलती की है उनको भी सजा दी जाए।

श्री अध्यक्ष : बी०पी०एल० के कार्डों की इस समय बात नहीं हो रही है। आपके नोटिस में इस बारे में कोई तथ्य हों तो आप रिपोर्ट करना।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion on the Governor's Address will resume. Shri Bachan Singh Arya may please speak.

श्री बचन सिंह आर्य (सफीदों) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 9 मार्च, 2007 को जो अभिभाषण यहां दिया उस अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने मुझे जो

समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राज्यपाल महोदय ने जिन उपलब्धियों का अपने अभिभाषण में जिक्र किया है। वह अपने आप में विशेष हैं और सही हैं। बल्कि उससे भी ज्यादा उपलब्धियां सरकार की हैं जो दो साल के अर्से में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने की हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे पानीपत के पास समझौता ऐक्सप्रैस में जो बम हादसा हुआ और उसमें 68 के करीब व्यक्तियों की जाने गईं। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री व अधिकारियों ने एकदम से वहां जाकर के जो राहत व बचाव कार्य किए और उनमें तत्परता दिखाई वह सराहनीय है। इससे जाहिर होता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की नीति व नीयत साफ है। जिस ढंग से उन्होंने भयमुक्त हरियाणा में भयमुक्त सरकार दी है। यह अनुकरणीय है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी तरह की कोई अशांति की बात नहीं है। पूरी तरह से शांति का माहौल है। अब से दो साल पहले अराजकता और अशांति का माहौल पूरे हरियाणा में छाया हुआ था। आज अपने तरीके से, किस प्रकार सद्भावना से किस तरह प्रेम से हरियाणा सरकार ने और माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो भाईचारा कायम किया है वह अपने आप में एक मिसाल है। दो साल पहले बदले की भावना हरियाणा में पनप रही थी लेकिन किस तरह से इस सरकार ने अपने तरीके से सहनशीलता और सूझबूझ से एक प्यार का वातावरण हरियाणा में बनाया है। उसके लिए मैं इस सरकार की प्रशंसा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में एक गलत परिपाटी बन गई थी यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम आज सत्ता पक्ष के साथ हैं। यह एक वास्तविकता है और वास्तव में ही पंजाब में शांति के दूत नाम से उस समय के मुख्यमंत्री **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री आनन्द सिंह दांगी पदासीन हुए)** सरदार बेअन्त सिंह जी थे जिन्होंने पंजाब में शांति स्थापित की थी और उसके लिए वे शहीद हो गये। उसी प्रकार हरियाणा के अन्दर दो साल पहले वही अशांति का माहौल था लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शांति का माहौल कायम किया है। जिसका श्रेय यहां की सरकार और मुख्यमंत्री जी को जाता है। दो साल पहले किस तरीके से बदले की भावना से झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते थे इस बारे में सभी सदस्यों को पता है। किस तरीके से मकानों को गिराया जाता था, किस तरीके से बदले की भावना से लोगों को डराया और धमकाया जाता था। लेकिन इन दो सालों में बदले की भावना से एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, यह अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी के सदस्य इस बात से नाराज होकर आज भी टीका-टिप्पणी करते हैं वे आज सदन में बैठे हुए नहीं हैं। क्योंकि कल जो उनका सदन में जिस तरह का व्यवहार था, तरीका था वह बढ़िया नहीं था। जबकि वे इस बात के लिए कहते रहे कि उन्हे सदन में बोलने का समय नहीं दिया गया। जबकि जितना समय उनकी पार्टी को बोलने के लिए दिया गया उतना समय तो हम दस निर्दलीय सदस्य जो सरकार के साथ हैं हमें भी बोलने के लिए नहीं दिया गया है। जब उनका बोलने का तरीका ठीक नहीं था तो उनको जवाब तो मिलना ही था। अब इस बात के लिए वे चिंतित हैं कि **"जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए।"** जब कांटे बोयेंगे तो फिर फूल कहां से मिलेंगे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसी भी प्रकार से उनके प्रति कोई गलत भावना अपने मन में नहीं रखते। लेकिन उनके लिए तो यही कह सकते हैं कि वे इस तरीके से चल रहे हैं **"जो तो को कांटे बोए, वो को बो तो फूल, तो को फूल के फूल हैं, वा को है त्रिशूल।"** हुड्डा साहब और उनकी सरकार सिद्धान्त की बात करती है, हिसाब की बात करती है, नियम की बात करती है, विकास की बात करती है और उसके बावजूद भी जो 6 साल में अराजकता फैलाते रहे हैं वह अराजकता कैसे पनपने दी जायेगी। शांति के साथ हरियाणा का विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री जी वास्तव में हरियाणा में बहुत कार्य कर रहे हैं। इन दो वर्षों में

[श्री बचन सिंह आर्य]

पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान किया गया है कानून एवं व्यवस्था का बढ़िया शासन दिया गया है, बहुत ही भौतिक व सामाजिक ढांचे का विकास किया गया है। कृषि संबंधी क्षेत्रों की ओर ध्यान केन्द्रित किया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का उचित विकास, रोजगार के अवसर सृजित करना जैसे संकल्प शामिल हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास के लिए बजट में बढ़ोत्तरी जैसे सराहनीय कार्य इस सरकार ने किए हैं। जो दो वर्षों की उपलब्धियां हैं आदरणीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उन सारी बातों का उल्लेख किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में पूरे हरियाणा में यह चर्चा चल रही है कि हरियाणा सरकार ने बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि नहरें बनवाई जा रही हैं और उनके बारे में अखबारों में भी आता रहा है कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी वे काम कर रहे हैं जो कभी भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाकर किया था। सभापति महोदय, भागीरथ की तरह ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा में दादूपुर नलवी और हांसी बुटाना नहर दो नहरें बनवा रहे हैं और विपक्ष के साथी उस पर टिप्पणियां करते हैं। आज से पहले कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने हरियाणा में एक भी नहर नहीं बनवाई। सभापति महोदय, जब ये नहरें बनकर तैयार हो जायेंगी और इनसे रजबाहे निकाल कर किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जायेगा तब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पूरे देश के तो नहीं लेकिन हरियाणा के लिए तो भागीरथ ही होंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी से पहले किसी और ने इस तरह के कार्य प्रदेश में करने के बारे में नहीं सोचा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। सभापति महोदय, अब मैं कानून व्यवस्था के बारे में बात करना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में कानून व्यवस्था का किस तरह से जनाजा निकाला गया था उससे पूरा सदन वाकिफ है। पिछली सरकार के समय में चारों तरफ भय और आंतक का माहौल था। न दुकानदार सेफ था, न व्यापारी सेफ था और न किसान भाई सेफ थे। कभी किसी दुकानदार को बंदूक की नोक पर लूट लिया जाता था, कभी किसी व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती थी। कभी किसी की गाड़ी या मोटरसाईकल बंदूक दिखा कर लूट ली जाती थी। उस समय जब कभी कोई किसान कोपरेटिव बैंक से लोन लेने के लिए जाता था तो यह सुनने को मिलता था कि भाई किसी एक ओर को साथ ले जाना, पता नहीं कहां पर कौन लुटेरा मिल जाये। सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय में पूरे प्रदेश में इस तरह की गुण्डागर्दी फैल गई थी। लेकिन हमारे हुड्डा साहब की सरकार आते ही दो साल में सब कुछ बदल गया है। अन्तर्मन से तो विपक्ष के साथी भी मानते हैं कि अब प्रदेश में अमन और चैन का माहौल है। अब प्रदेश में दुकानदार, व्यापारी और किसान यानि की सभी वर्ग शांति से बिना भय के रहते हैं। सभापति महोदय, छोटी मोटी घटनाएं तो राम राज में भी होती रहती थी लेकिन अब कोई गुण्डा हरियाणा प्रदेश में दिखाई नहीं देता। अब गुण्डे या तो जेलों में बंद हैं या वे हरियाणा छोडकर दूसरे प्रदेशों में चले गये हैं इसके लिए भी मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूं। सभापति महोदय, अब मैं कृषि के बारे में बात करना चाहूंगा कि पिछले दो साल से हरियाणा ने कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। यह अलग बात है कि अचानक कोई आपदा आ जाये जैसे अभी भारी बरसात और ओलावृष्टि के कारण हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा फ़सल बरबाद हो गई। हमारे पार्लियामेंट अफेयर्ज मिनिस्टर ने बताया कि जिन किसानों की फसल बरबाद हुई है। उन्हें पूरा मुआवजा दिया जायेगा जबकि पिछली सरकार के समय में किसानों को एक-एक, दो-दो रुपये मुआवजे के नाम पर दिए जाते थे और उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता था। लेकिन अब पूरा मुआवजा किसानों को दिया जायेगा ताकि उनको कुछ राहत मिल सके और उनके आत्म सम्मान को ठेस न

पहुंचे। सभापति महोदय, गन्ने का भी सर्वाधिक भाव हुड्डा साहब की सरकार ने किसानों को दिया है।(विघ्न)

श्री सभापति : आर्य जी, आपके पास केवल दो मिनट का समय बाकी है। आप प्लीज जल्दी वाईंड अप करें और भी बहुत से सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलना है।

श्री बच्चन सिंह आर्य : सभापति महोदय, मैं कृषि के बारे में जिक्र कर रहा था कि हुड्डा साहब की सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए बहुत से काम किए हैं। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए हुड्डा साहब की सरकार ने पशुधन स्कीम चलाई है और पोपुलर के भी अच्छे भाव हमारी सरकार ने दिए हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी सुविधाएं किसानों को दी गई हैं जिनका जिक्र बहुत से माननीय सदस्यों ने किया है, मैं भी उनसे सहमत हूं। सभापति महोदय, अब मैं मेरे हल्के सफीदों के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय 11 जून को सफीदों में सम्पूर्ण रैली करके आये थे। उस समय हमने जो-जो भी मांगे मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी वे सभी मांगे मुख्यमंत्री जी ने मान ली। चाहे सड़कों की बात थी, चाहे करोड़ों रुपये के नगर पालिका भवन के निर्माण की बात थी, चाहे सफीदों शहर में 9 एकड़ के स्टेडियम बनाने की बात थी, चाहे गवर्नमैंट कालेज की बात थी,चाहे प्रसिद्ध राम लीला ग्राउंड की बात थी यानि की सभी मांगे मान ली गई थी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। सभापति महोदय, 9 एकड़ जमीन में जो स्टेडियम बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी करके आये थे उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा कि वह स्टेडियम बनाना मंजूर तो कर लिया है लेकिन अभी तक उसको बनाने के लिए पैसा नहीं पहुंचा है। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही पैसा भी पहुंच जायेगा और यह स्टेडियम बनना भी शुरु हो जायेगा। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 18 फरवरी को हाँसी-बुटाना लिंक नहर का मुख्यमंत्री जी निमणाबाद गांव में शिलान्यास करके आये हैं। उसके लैफ्ट साईड में एक ड्रेन बनी हुई है जो कि कई गांवों के बरसात के पानी का उतार करती है।

11.00 बजे

इस ड्रेन की कैपेसिटी कम होने के कारण इस बार की अचानक हुई बारिश का पानी इस ड्रेन में आया जो कि फालतू पानी रिसालथा से सालवान और डिडवाड़ा इत्यादि गाँवों में चला गया जिस कारण इन गांवों में होने वाली फसलें बरबाद हो गई। मेरा अनुरोध है कि उस ड्रेन की कैपेस्टी बढ़ा दी जाए ताकि आने वाले समय में किसानों की अगली बुवाई वहाँ पर ठीक तरीके से हो सके। हाँसी बुटाना लिंक नहर के राईट साईड में पहले एक ड्रेन थी अब बीच में से हाँसी बुटाना लिंक नहर आ गई दूसरी तरफ के जो गाँव और किसान हैं उन गांवों का बारिश का पानी अब भी ज्यों का त्यों रुका हुआ है। मेरा अनुरोध है कि वहाँ पर राईट साईड एक ड्रेन बनाकर हाँसी बुटाना नहर में डाल दी जाये ताकि उन गांवों की फसलें खड़े पानी से खराब न हों। आदरणीय मुख्य मंत्री जी मेरे हल्के में कुछ सड़कों की घोषणा करके आये थे और उन सड़कों के बारे में मुझे पता चला है कि उनका प्रस्ताव मंजूरी के लिए सरकार के पास गया हुआ है। निमणाबाद से मलिकपुर, मलिकपुर से रोहड़, रोहड़ से मुआना, तलौडा से पिल्लू खेड़ा, अफ्ताबगढ़ से रोहड़ आदि सड़कों की घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की है मेरा अनुरोध है कि उनको बनवाने का कष्ट किया जाये। एक बहुत बड़े हॉस्पीटल का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे यहाँ करके आये थे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी आज बैठी हुई हैं उस समय बहन जी उपलब्ध नहीं थी। वहाँ करोड़ों रुपये की लागत से ऊपर का स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पीटल तो बहुत बड़ा बना दिया। बहुत सुन्दर भवन बनाया है उसके लिए हम स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा

[श्री सभापति]
कि वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। इसलिए मेरा स्वास्थ्य मंत्री महोदया जी से अनुरोध है कि वहाँ पर डॉक्टर भिजवाने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री सुभाष चौधरी (जगाधरी) : सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर हरियाणा के विकास की जो तस्वीर दर्शाई गई है वह अपने आप में बेमिसाल है। किसान पूरे देश की रीढ़ की हड्डी हैं उसको जो सुविधाएं देने के प्रयास हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा किये जा रहे हैं वे देश में अपनी किस्म की एक पहली मिसाल है। किसानों को देश के अन्दर गन्ने का सबसे ज्यादा मूल्य देना जो कि 138 रुपये प्रति क्विंटल है यह भी अपने-आप में एक मिसाल है। 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों की सरसों सरकार खरीद रही है जो पहले कभी नहीं खरीदी गई। इसके अलावा सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह सुझाव है कि यमुनानगर शूगर मिल के किसानों का शूगर मिल पर करीब 35 करोड़ रुपया बकाया है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रयास भी किया ताकि वो पैसा किसानों को मिले। उन्होंने शूगर मिल वालों को मना भी लिया था लेकिन कुछ लोग मैं कहना चाहूँगा कि वे इनैलो के हैं जिन्होंने हाई कोर्ट के अन्दर इस पैसे के लिए केस डाला हुआ है। उन चन्द लोगों की वजह से गरीब किसानों का वह पैसा शूगर मिल ने हैल्ड किया हुआ है। चेयरमैन साहब मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि कोई भी रास्ता निकालकर वह किसानों का पैसा किसानों को दिलाया जाये ताकि किसानों की और मदद हो सके। वैसे भी आजकल किसानों के ऊपर बुरा वक्त चल रहा है। पहले बारिश आ गई और अब ओले पड़ने से फसल बरबाद हो गई हैं। अगर पैसा किसान को मिलेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा। चेयरमैन सर, मेरे हल्के जगाधरी में एक कस्बा मुस्तफाबाद है मुख्य मंत्री जी की अनाऊंसमैंट के मुताबिक वहां पर एक मण्डी बननी थी। पंचायत ने 24 एकड़ जमीन का रैजोल्यूशन करके भी दे दिया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार उसके ऊपर कार्य शुरु करवाए ताकि वहाँ के ऐरिया के लोगों को जल्दी सुविधा मिले। चूंकि पुरानी मण्डी बहुत छोटी है किसानों को बार-बार दिक्कत होती है। मैं मुख्य मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूँ जिनकी सरकार बनने के बाद किसानों के अन्दर एक रोशनी जगी। 120 और 150 रुपये तक बिकने वाला पोपूलर आज 500 से 550 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकता है। चेयरमैन सर, यह सरकार नेकदिली से चलने वाली सरकार है, ईमानदारी से चलने वाली हुड्डा साहब की सरकार है। चौटाला साहब की सरकार में तो प्लाई उद्योग से महीना इकट्ठा किया जाता था जो कि इस सरकार के बनने के बाद बन्द हुआ और किसान को राहत मिली। पापुलर का 150 रुपये की बजाए 500 रुपये का भाव मिला इसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं। चेयरमैन सर, अगर हम शहरी विकास की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि दो साल में जब से हमारी सरकार बनी नगर निकायों को सरकार ने पूरा अनुदान दिया है ताकि शहरों में तरक्की हो सके, सीवरेज प्रणाली सुधर सके और पीने के पानी की ठीक व्यवस्था हो और गलियां और नालियां बन सके, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मेरी नगर परिषद जगाधरी को विभिन्न माध्यमों से छ: करोड़ रुपये का अनुदान दिया उससे हमारे शहर की तरक्की हुई उसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं तथा उनका धन्यवाद भी करता हूं। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक और छोटी सी चीज की तरफ दिलाना

चाहता हूं। पूरे हरियाणा के अन्दर नगर परिषदों के अन्दर जो यह हो रहा है वह आज के समय में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1976 के म्यूनिसिपल एक्ट के तहत जो रेहड़ी हाथ से खींचते हैं उनको लाईसैंस लेना पड़ता है जो रिक्शा चलाता है उसको भी लाईसैंस लेना पड़ता है। हालांकि यह अमांउट बहुत छोटा है कोई 25 रुपये है, कोई 15 रुपये है और कोई 10 रुपये है। म्यूनिसिपल इन्सपैक्टर रेहड़ी वाले से रेहड़ी छीन कर म्यूनिसिपल कमेटी में ला कर खड़ा कर देते हैं तो वह गरीब अपनी रोजी रोटी कहां से कमाएगा। इस तरह के जो छोटे-छोटे टैक्स गरीब लोगों पर लगा रखे हैं वह हटाने चाहिएं। रेहड़ी या रिक्शा चलाने वाले से ज्यादा गरीब कोई हो नहीं सकता। आपके माध्यम से सरकार से मेरा यह निवेदन है कि इस टैक्स को तुरन्त खत्म किया जाए ताकि आम आदमी को रियायत मिल सके। शिक्षा के अन्दर सरकार ने काफी कार्य किये हैं और कर रही है। मेरे हल्के के अन्दर भी मुख्य मन्त्री जी की घोषणा के तहत एक आई०टी०आई० मुस्तफाबाद में बननी है मैं चाहूंगा कि उस पर भी जल्दी से जल्दी काम शुरू हो। इसी तरह से स्कूल भी अपग्रेड हुए हैं मैं चाहूंगा कि मेरे हल्के के सुढल-सुढैल बड़े गांव हैं वहां के स्कूल भी अपग्रेड करवाए जाएं। क्योंकि वक्त की यह डिमांड है। चेयरमैन सर, एक गांव चमनौली पड़ता है, 1922 में वहां पर प्राईमरी स्कूल बना था और 1922 से लेकर आज तक वह स्कूल अपग्रेड नहीं हो सका है, मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि उस स्कूल को अपग्रेड करें ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े। आपके माध्यम से मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे हल्के के गांव गोहलनी के अन्दर एक वोकेशनल इंस्टीच्यूट की बिल्डिंग पंचायत ने अपने खर्चे पर 35 लाख रुपये खर्च करके तैयार की है, पिछले एक साल से यह बिल्डिंग तैयार पड़ी है आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि कि उस बिल्डिंग को टेक ओवर करके वहां पर वोकेशनल इंस्टीच्यूट को जल्दी से जल्दी चलाया जाए। चेयरमैन सर, स्वास्थ्य के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर तरह तरह की सुविधाएं देने की बात कही गई है मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे जगाधरी शहर के होस्पीटल को 30 से 60 बैड का अस्पताल अपग्रेड किया और इसके साथ ही मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे हल्का में गांव भम्बोल में पी०एच०सी० है उसकी बिल्डिंग बहुत छोटी और बहुत पुरानी है। (विघ्न)

श्री सभापति: चौधरी साहब, अब आप वाईंड अप करें।

श्री सुभाष चौधरी : चेयरमैन सर, जब माननीय मुख्य मन्त्री जी जगाधरी गये थे तो मैंने उनसे इस बारे अनुरोध किया था और उसके लिए मुख्य मन्त्री जी ने हां भी की हुई है। यह बिल्डिंग जल्दी बनाई जाए ताकि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं जल्दी उपलब्ध करवाई जाएं। सिंचाई के मुद्दे पर प्रदेश के किसान को पानी देने के लिए सरकार के जो भरसक प्रयास हैं वे भी अपने आप में बहुत अहमियत रखते हैं। एस०वाई०एल० का निर्माण जल्दी से जल्दी हो, हांसी-बुटाना नहर सरकार जल्दी ही बना रही है, दादुपुर-नलवी के ऊपर बड़े जोर से काम शुरू हुआ है। चेयरमैन सर, सरकार की ये ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्हें लोग हमेशा याद रखेंगे। मैं आपके माध्यम से इरीगेशन मिनिस्टर जी से निवेदन करूंगा कि हमारा ऐरिया यमुना नदी के साथ लगता हुआ ऐरिया है। हमारे कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें मेरा अपना भी गांव है इन तीन-चार गांवों से यमुना का फासला केवल एक डेढ़ ऐकड़ का रह गया है। ज्यादा बारिश के दिनों में इन गांवों में बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। मैं आपके माध्यम से इरीगेशन मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि इनको वहां पर ऐसे प्रबन्ध करने चाहिए ताकि वहां के लोगों की जमीन को बाढ़ से बचाया जा सके।

श्री सभापति : सुभाष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रमेश कौशिक जी आप बोलें।

श्री रमेश कौशिक (राई) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। सभापति महोदय, जब से हरियाणा में हमारी कांग्रेस की सरकार आई है तब से हरियाणा में भ्रष्टाचार और जात-पात की राजनीति का खात्मा हुआ है। यह सब हमारे नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की कोशिशों का परिणाम है। इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही भ्रष्टाचार और जात-पात की राजनीति की कलई खोल कर रख दी है। अब उस तरह की राजनीति हरियाणा प्रदेश में नहीं चलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा की 36 बिरादरी को साथ लेकर हरियाणा में प्रगति के काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के वक्त में जो जमीन एक्वायर की जाती थी तो जमीन के भाव 2 लाख रुपए प्रति एकड़ के दिए जाते थे। लेकिन आज इस सरकार के समय में हरियाणा में वही जमीन करोड़ों रुपयों की हो गई है। यह सब हमारे मुख्यमंत्री जी की नेक नीयत की वजह से हुआ है। आज इनकी वजह से हरियाणा में जमीन का 22 लाख रुपए प्रति एकड़ का भाव हुआ है। पिछली सरकार किसानों के हितैषी होने का दावा किया करती थी लेकिन वे असल में किसानों को लूटा करती थी। आज हमारी सरकार ने उन किसानों के बिजली के बिलों के1600 करोड़ रुपए माफ करके एक बहुत ही सराहनीय काम किया है। इसके अलावा सिरसा में जो रैली की है वहां पर मुख्यमंत्री जी ने अपने दो सालों में किए गए कार्यों के बारे में बताया और जो जो विकास किए हैं उनकी जानकारी जनता को दी। आज हमारी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 138 रुपए प्रति क्विंटल किया है यह बहुत ही सराहनीय काम है। चेयरमैन सर, इसके अलावा हमारे इलाके में पानी की बहुत भारी समस्या थी और पिछली सरकारों के वक्त में हमारे साथ पानी के मामले में भेदभाव किया जा रहा था लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने आते ही उस भेद भाव को खत्म किया है और हरियाणा में पानी का समान बंटवारा किया है। चेयरमैन सर, हमारे यहां पर हांसी-बुटाना नहर के निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके लिए मैं इस सरकार का धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा थी। इसको दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले खानपुर में महिला यूनिवर्सिटी खोली है। इसके साथ मुरथल में सर छोटूराम टैक्नीकल यूनिवर्सिटी को भी खोला गया है और उसके लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चेयरमैन सर, इसके अलावा मैं सदन में कहना चाहूंगा कि राई में अपने ही किस्म की राजीव गांधी एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जा रहा है। पहले जो बच्चे एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाते थे अब वे बाहर नहीं जाएंगे और यहीं पर एजुकेशन लेंगे। इस एजुकेशन सिटी की वजह से हरियाणा का नाम देश में ही नहीं विदेशों में लिया जाएगा। यह सब हमारे पढ़े लिखे और ईमानदार मुख्यमंत्री जी की वजह से ही सम्भव हो पाया है। पहले वाली सरकार का शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं था और अब ये इस बारे में भी अनर्गल ब्यान दे रहे हैं।

चेयरमैन सर, इसके साथ ही मैं इन्डस्ट्रीज के बारे में कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा में सबसे ज्यादा इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं। यह सब हमारे मुख्यमंत्री जी की कोशिशों की वजह से हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी विदेशों में जा जा कर ज्यादा से ज्यादा इण्डस्ट्रीज को हरियाणा में आने का न्यौता दे रहे हैं। किसी प्रदेश का विकास तभी हो सकता है जब उस प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इण्डस्ट्रीज हों। चेयरमैन सर, हमारे हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा मिनिमम वेजिज़ 3510 रुपए है। पिछली बार भी मैंने मांग की थी कि मिनीमम वेजिज कम से कम इतना तो होना ही चाहिए

जिससे मियाँ बीबी के अलावा अगर किसी के दो बच्चे हैं तो उनका सही तरह से पालन पोषण हो सकें। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उसने मिनीमम वेजिज बढ़ाए। चेयरमैन सर, इसके अलावा सुपर हाई वे का निर्माण करना भी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुंडली मानसेर पलवल हाई वे का निर्माण कार्य हमारे हल्के कुंडली से शुरू हो गया है। मैं मुख्यमंत्री महोदय का इसके लिए धन्यवाद करता हूं। आज सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जो न किया हो। सब वर्गों को उन्होंने फायदा पहुंचाया है। चाहे चौकीदार हो, चाहे नम्बरदार हो, चाहे पंच या सरपंच हो या चाहे जिला परिषद के मैम्बर हों सबको उन्होंने राहत दी है। इसके अलावा खेलों के बारे में भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। हर हल्के में एक-एक स्टेडियम का निर्माण सरकार ने करवाया है। इसके अलावा जो खिलाड़ी खेलों में कप जीतकर लाएंगे उनके लिए भी सरकार ने विशेष सुविधा देने का प्रावधान किया है। इसी तरह से रोड्ज का निर्माण भी पूरे हरियाणा में बड़ी भारी स्पीड से चला हुआ है। जिस समय यह सरकार बनी उस समय रोड नाम की कोई चीज हरियाणा में नहीं थी सब रोड्ज टूटी फूटी थीं क्योंकि पिछली सरकार ने इनका बहुत बुरा हाल कर रखा था। लेकिन अब रोड्ज के मामले में हरियाणा बहुत आगे चल रहा है चारो तरफ रोड्ज का जाल फैलाया जा रहा है। इसी तरह से पहले पब्लिक हैल्थ में भी बड़ी भारी दिक्कत थी लेकिन हमारी सरकार ने इस बारे में भी ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने सबसे बड़ा काम यह किया है कि हमारे हरिजन भाईयों को फ्री पानी का कनैक्शन और पानी की टंकी देने का भी इंतजाम किया है। यह सरकार की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट के मामले में भी हमारी सरकार ने काफी काम किया है। पहले हरियाणा में टूटी बसिज होती थी लेकिन अब नयी बसिज हरियाणा में लायी गयी हैं। 600 नयी बसिज को बेड़े में शामिल किया गया है। चेयरमैन सर, सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने यह किया है कि आज हरियाणा में शान्ति का माहौल चारो तरफ है। पहले अपराधी जेलों में बैठकर राज किया करते थे लेकिन अब ये लोग या तो हरियाणा छोड़कर चले गये हैं या उन्होंने अपना काम बदल लिया है। हमारे इन विरोधी भाईयों में हमारी बात सुनने की हिम्मत नहीं है इसलिए आज ये हाउस में नहीं आए हैं ये केवल बाहर बैठकर ही बातें करते हैं वे आकर अपनी बात कहते और हमारी सुनते तो अच्छा लगता। इन लोगों ने तो केवल झूठे मुकदमें बनवाएं और लोगों को तंग किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया। जिन जालिमों को सजा देनी चाहिए थी उनको भी उन्होंने सजा नहीं दी है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। चेयरमैन सर, आपका मुझे समय देने के लिए धन्यवाद।

श्रीमती प्रसन्नी देवी (नौलथा) : चेयरमैन सर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। पिछले दो साल में इस सरकार ने इतने थोड़े समय में जितने कार्य प्रदेश के हर वर्ग के लिए किए वह बहुत बड़ी बात है। इन सब कार्यों का ब्यौरा तो नहीं दिया जा सकता। जिस बात को सोचते हैं वह बात उससे पहले ही पूरी हो जाती है। वह काम पहले ही पूरा हुआ मिलता है। आज कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छूटा है कि जिसकी कोई समस्या हो और उसको वह बताने की जरूरत पड़ी हो। उसके बताने से पहले ही सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस बात को पूरा किया है। पिछले दिनों पानीपत के पास मेरे हल्के के एक गांव के ही नजदीक रेल का बहुत बड़ा हादसा हुआ था। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने उस हादसे के बाद बहुत अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री जी तो खुद भी बधाई के पात्र हैं। उनके सारे अधिकारी थोड़ी ही देर में चण्डीगढ़ से वहां पहुंच गये। इसी तरह से जिले के अधिकारी भी वहां तुरंत पहुंच गये। वहां की पंचायत ने भी वहां पर बहुत अच्छा कार्य किया। इससे पता लगता है कि यह सरकार कितनी

[श्रीमती प्रसन्नी देवी]

जिम्मेवारी से अपना काम कर रही है। इस सरकार का ध्यान हर आदमी की तरफ है। चेयरमैन सर, वैसे तो जैसे मैंने कहा कि हर वर्ग के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। गरीब आदमियों के लिए कोई कमी नहीं रही लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो आदमी थे उनके लिए यह अच्छा हुआ कि बीपीएल कार्डों का सर्वे दोबारा से कराया जा रहा है। पहले जो ये कार्ड बने हुए थे वे सारे गलत बने थे क्योंकि जो इस के अधिकारी थे वे इससे वंचित रह गए हैं। जिनके पास सब कुछ है उनके पास ये कार्ड हैं। इस बारे में मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि जो सर्वे किया जा रहा है वह पूरी ईमानदारी से किया जाए। जैसे सरकार ने गरीब आदमियों और हरिजनों को पानी की सुविधा दी है, कनैक्शन दिए हैं, टंकी दी है सब कुछ दिया है। अगर उसमें पिछड़े वर्गों के लोगों को शामिल कर लिया जाए तो यह बहुत अच्छा कदम होगा। हमारी सरकार ने निचले वर्गों की तरफ वैसे तो बहुत ध्यान दिया है लेकिन उनके स्तर में अभी भी थोड़ा सा फर्क है इससे उनको भी भारी फायदा होगा। चेयरमैन साहब, इंदिरा गांधी जी के समय में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला था। उस वक्त पिछड़े वर्गों के लोगों को व हरिजनों को 100-100 गज के प्लाट दिए गए थे। उसके बाद उनकी कई पीढ़ियां आ गई। उनके पास बहुत थोड़ी सी जगह होती है। परिवार का उसमें रहना मुश्किल हो जाता है मैंने पहले भी हर सैशन में इस बात के लिए गवर्नमैंट से प्रार्थना की है। आज भी प्रार्थना कर रही हूं। मुख्यमंत्री जी उदार हैं। जैसे और कामों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है ऐसे ही मैं समझती हूं कि इस काम में भी पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी। जिन गांवों में पंचायत की जमीन है उन गांवों में तो पंचायत से इस काम के लिए जमीन ली जा सकती है। थोड़े से ही गांव ऐसे होंगे जहां जमीन ऐक्वायर करनी पड़ेगी। जहां 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिलों की माफी की जा सकती है। इस काम के लिए बहुत थोड़े से बजट में ही गरीब आदमियों का भला हो जाएगा। उनके पास भी रहने के लिए पर्याप्त जगह हो जाएगी। इसके साथ-साथ जो गरीबी रेखा से नीचे बसने वाले लोगों को सरकार द्वारा मकान बनाने के लिए अनुदान राशि 25 हजार रुपये दी जाती है उसमें कुछ पैसा केन्द्र सरकार का होता है और कुछ पैसा राज्य सरकार का होता है उस राशि को भी बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनके पास रोटी खाने का भी हिसाब नहीं है। मकान बनाने की बात तो बहुत दूर की है, यह 25 हजार की राशि 50 हजार कर देने से उनको लाभ हो सकता है। चेयरमैन साहब, हमारे माननीय सदस्य कर्ण सिंह दलाल ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा था। गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में सारी चीजों का उल्लेख किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत भारी तरक्की की है। बहुत बड़ी संख्या में स्कूल अपग्रेड हुए हैं। महिलाओं की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। खानपुर कलां में गुरुकुल एक ऐसी संस्था थी जिसने लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। जिसके अंदर बहुत सी लड़कियों को पढ़ाई करने का मौका मिला था। मैं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूं कि यह संस्था किसी समय में छप्पर के बरामदों में चला करती थी और आज उसने एक यूनीवर्सिटी की शक्ल ले रखी है। मैं बार-बार इसके लिए उनको बधाई देती हूं और प्रार्थना करना चाहती हूं कि उस यूनीवर्सिटी को बहुत बड़ी शक्ल मिले और लड़कियों को पढ़ाई का ज्यादा मौका मिले। हर जिले में एक कालेज लड़कियों के लिए गवर्नमैंट ने अपने स्तर पर खोला है जिससे बहन-बेटियों को बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि को-एजूकेशन ज्यादातर लड़कियां नहीं ले पाती और न ही उनके परिवार वाले उनको भेज पाते। अगर अलग से लड़कियों के स्कूल-कालेज खुल जायेंगे तो हमारी बहन-बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का मौका मिल

सकता है। इसी प्रकार से स्कूलों की तादाद भी सरकार बढ़ा ही रही है। इनसे भी लड़कियों को काफी फायदा होगा।

श्री सभापति : बहन जी, आप दो मिनट में कन्क्लूड करें।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : चेयरमैन सर, आप मुझे दो-तीन मिनट का समय और दीजिए। अब मैं स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। स्वास्थ्य विभाग जहां एक ब्लॉक में सी०एच०सी० खोलता है और एक पी०एच०सी० खोलता है तो पी०एच०सी० में दो या तीन डाक्टर्ज होते हैं। जहां पर सब सैंटर्ज होते हैं वे वहां के एरिया की जरूरत को पूरा नहीं कर पाते । मेरी आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदया से प्रार्थना है कि जहां पर पी०एच०सी० हैं वहां पर दो-तीन डाक्टर्ज जरूर होने चाहिए और 20 हजार की आबादी पर एक पी०एच०सी० जरूर खोल देनी चाहिए ताकि जो सरकार बड़े प्रोग्राम करना चाहती है वे उस लैवल पर निपट सकते हैं। क्योंकि छोटी सी बीमारी के लिए गांव वालों को शहर की तरफ भागना पड़ता है। इसी प्रकार चाहे कोई भी तरीका सरकार अपनाये लेकिन इन पी०एच०सी० में डाक्टर एक साल या दो साल अवश्य सेवा करें चाहे तो सरकार जब डाक्टर्ज की भर्ती करती है तो उस समय इस बात का प्रावधान करें और यह कंडीशन रख दी जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में जो डाक्टर भर्ती किए जाते हैं वे दो साल तक वहां पर सेवा करेंगे। इसी प्रकार से आंगनवाड़ी का फैलाव वैसे तो सभी जगह किया हुआ है। लेकिन अभी और आंगनवाड़ी खोलने की जरूरत है। इससे जो औरतें और बच्चे कहीं पर भी नहीं जा सकते उनको आंगनवाड़ी से काफी लाभ हो सकता है। सड़कों का भी काफी काम चल रहा है लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदय मेरे हल्के के गांव उलाना कलां में एक पुल बनाने के लिए घोषणा करके आये थे जिसका एस्टीमेट 80 लाख रुपये है उस पुल से 10-12 गांवों को रास्ता जाता है और वह पुल इतना कमजोर है कि कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए उस पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। इसके साथ ही जो स्कूल खोलने या अपग्रेड करने हैं उनकी लिस्ट मैंने शिक्षा मंत्री महोदय को दे दी है उनका दर्जा बढ़ाने का सरकार कष्ट करे। चेयरमैन सर, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं और उस अभिभाषण का जिसे श्री कर्ण सिंह दलाल ने पेश किया उसका मैं समर्थन करती हूं। जयहिन्द।

Maj. Nirpender Singh Sangwan (Dadri) : Chairman, thank you very much for giving me time to speak on discussion of Governor's address. I am thankful to the Hon'ble Governor of Haryana for delivering his Address on 9th March, 2007 in this august House. Our Government has done good works in all spheres. I am also thankful to the Hon'ble Chief Minister for the development works which are being done in all the areas of the State of Haryana. All residents of villages and towns in Haryana have recognized good work which are being done by the government. The Planning Commission has also recognized good works done by the Haryana government due to these development works the plan outlay has been tripled in agriculture and allied activities. I must say that the Mandi Board is making good roads but there are some roads which were earlier left unfinished because they were being done in a double manner and the reason was that the work on the ground was being done by the one department and the work relating to the top layer was being done by the Mandi Board and that is why they were lying unfinished. I would request that these roads should be finished by the

[Maj. Nirpender Singh Sangwan]

Mandi Board. Experimental and demo-farms should be setup in all districts so that young farmers can avail the opportunity to see the output. New seeds should be demonstrated in the demo-farms. The seed of these new crops demonstrated in the demo-farms should be given out as seed money to the farmers. There is a paucity of doctors in the veterinary dispensaries and the repair of veterinary dispensaries in the villages is worth mentioning. In spite of money being sanctioned for these works, the works are going on very slowly. Paucity of doctors is still there. If you want to improve the cattle in all our rural areas, we need good doctors and dispensaries and it is the requirement of the day. Every district should have a demonstrative fish farm which can supply fish seed to all the villages which is coming up for fish culture in a very big way. The forest cover in the State is increasing but I must say only Eucalyptus, Kikkar and Babul trees are taking the need of today. The old plantation of Syshim, Rahera and Neem trees are rapidly diminishing this should also be paid attention and in future proper plantation of Neem, Rehera and Syshim trees should be made as wood of these trees is very essential in day-to-day works for all our carpenters and ohter people who are making new houses and furniture. Maintenance of the canal system is one of the areas, in which our Government has paid a lot of attention and has also given a lot of money but unscrupulous contractors take contracts and they either do not finish the work or they finish them in a manner which need not to be deserved. They should be taken over by the department if the work is unsatisfactory. I am thankful to the Hon'ble Chief Minister for equitable distribution of the water in the State that has taken up on a war-footing. Distribution network of the electricity is very much wanting. The wire poles and wires need replacement as these are very old and for this the work force is required. Till such time, the new people are recruited; people should be taken up on a contract basis so that these works do not suffer. The Industrial sector should be developed by the HUDA or HSIDC, in all towns which have a Municipal Committee otherwise the industries will come up in a very haphazard manner and they will be detrimental to the development of the city. Dadri itself needs nodal point for recruitment of industries. In the Education Sector, there is a paucity of JBT teachers and College cadre teachers. The School Teachers should be appointed without any further delay. Till the time, they are appointed, teachers should be taken on contract like they have been taken now. This policy should be continued in the near future also. The work on stadiums of sports has been taken up by the Government and it should be finished as early as possible. In these stadiums, provision of sports kits should be made in cricket, football and volleyball so that the children in the rural areas can show their performance. Lot of money has been sanctioned for the rural development works but it is not being utilized in the manner that it ought to be. The quality of works are not being maintained. I would request that a team in every District should be nominated to look into the quality of these works in the rural development Sector. In the urban development sector, I must thank Smt. Savitri Jindal for taking a lead for the first time that the Government has paid the dues and salaries of all the employees in the Municipal

Committees in a regular manner. All the arrears too have been cleared in Dadri for which I am very thankful to the worthy Hon'ble Chief Minister and Smt. Savitri Jindal. In the PWD(B&R), lot of money has been sanctioned but the roads need to be looked into, as far as their quality is concerned. Even the time schedules are not being followed for a very long time. The roads are under repair, causing lot of inconvenience to the villagers and other people, who are using them. In PWD (Public Health), for water supply and sanitation, there was a paucity of pipes for a very long time and this is being overcomed. Fifty percent of the southern Haryana is facing the problem of drinking water, so, this problem should be looked into on priority basis. Primary Health Centres need to be maintained also. There is a paucity of doctors and para-medical staff for which, I would request the worthy Health Minister that the doctors should be posted on priority basis in the areas which are not accessible. In the social sector, there are lot of families of martyrs, who laid down their lives for the country on the frontiers of the nation. I would request that the there should be a provision of service to the wife of a martyr and if his wife is unable or unwilling to take up service, one child of the family should be given service. Thank you.

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल (अम्बाला कैंट) : सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने 9-3-07 को सदन में जो अभिभाषण दिया उस अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल ने इस बात को स्पष्ट किया कि इन दो सालों में हरियाणा ने हर क्षेत्र में तरक्की की है चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। इन दो सालों में असीमित तरक्की असीमित विकास हरियाणा प्रदेश ने किया है मैं इसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करता हूं और उनकेअभिभाषण का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उनके द्वारा किये गये प्रयासों और मेहनत के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हरियाणा को एक तरक्कीशील राज्य बनाने का प्रयत्न किया। माननीय हुड्डा साहब ने हर बुजुर्ग, हर नौजवान, हर बच्चे और हर महिला को अपना मानकर हर वर्ग के लिए कार्य किया। हर जाति, हर वर्ग, हर मजदूर के सहयोग के लिए उन्होंने काम किया है तथा उन्होंने हमेशा ही उनको अपना समझा है। दलित हो, हरिजन हो, बैकवर्ड क्लास हो, महिला हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हों सबके जीवन की विडम्बनाओं को उन्होंने दिल से, मन से महसूस करके उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने 3510 रुपये मिनिमम वेजिज देकर मजदूर समाज के लिए जो काम किया है यह अपने आप में बहुत ही मजबूत फैसला है। माननीय मुख्य मंत्री जी का यह फैसला किसी रिप्रैजैंटेशन या किसी मांग का रिजल्ट नहीं है। परन्तु यह फैसला माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपनी आत्मा की पवित्रता से किया ताकि हमारे जो मजदूर भाई हैं उन्हें अपने जीवन में प्रकाश प्राप्त हो और वे अपने जीवन में आसानी से गुजारा कर सकें। इसके साथ माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के तहत हमारे आठ लाख दलित भाईयों के लिए मुफ्त पानी के कनैक्शन्ज़ और पानी की टंकी देने का जो फैसला किया है उससे यह बात स्पष्ट होती है कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री के दिल में हरिजन भाई, बैकवर्ड भाई, किसान, विद्यार्थी, महिलाओं के लिए कितना बड़ा स्थान है। को-ऑपरेटिव सोसाईटीज़ के लोन की जो समस्या हमारे किसान भाइयों और छोटे दुकानदार भाईयों के सामने खड़ी थी,हमारे हरिजन भाई

[श्री देवेन्द्र कुमार बंसल]

और बैकवर्ड भाइयों के सामने खड़ी थी, लोन के अन्दर जो गिरफतारी का प्रोविजन था या उसके अन्दर जो इन्ट्रस्ट का रेट था ऐसे प्रावधान को खत्म करके, गिरफ्तारी को खत्म करके हमारे मुख्य मन्त्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वे किसान मजदूर और हमारे दलित भाइयों के बहुत बड़े मसीहा हैं। हमारे दीन बन्धु सर छोटू राम जी जैसे महान व्यक्तित्व ने अपना सारा जीवन हमारे मजदूर भाईयों, हमारे किसान भाईयों के उत्थान के लिए लगाया है। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दीन बन्धु सर छोटू राम के सपनों को साकार किया है। इसके साथ ही स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिन्होंने हमेशा ही इस बात को माना था कि हमारे देश का मजदूर और किसान खुशहाल होगा तब हमारा देश तरक्कीशील होगा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी उस समय उन दुर्गम स्थानों पर जाते थे जहां हमारे मजदूर भाई, किसान भाई रहते थे और उनके जीवन को बड़ी गहराई से देखते थे और उनके जीवन के उत्थान के लिएं भरसक कोशिश करते थे। चेयरमैन सर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपनों को भी ऐसे पुण्य कदम उठा कर पूरा किया है। मैं इस सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी का एक बार फिर से उनके अनथक कार्य के लिए धन्यवाद करता हूं और उन्होंने जो विभिन्न नीतियां बनाई हैं उससे हर जाति और स्तर के लोगों को फायदा हुआ है। एस०वाई०एल० कैनाल के माध्यम से रावी-ब्यास के पानी का पूरा हिस्सा हरियाणा की जनता को दिलवाने के लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी प्रयासरत हैं इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। बिजली की समस्या एक लम्बे समय से चली आ रही हैं, कई सरकारें आईं और चली गईं लेकिन यह समस्या ज्यों की त्यों पड़ी रही इस समस्या से निपटने के लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने शासनकाल में यमुना नगर में, हिसार में और झज्जर में बिजली के सन्यन्त्र लगाए हैं और इस बात का हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि यमुना नगर में जो हमारा बिजली का सन्यन्त्र है जिसने 600 मेगावाट बिजली पैदा करनी है वह 300 मेगावाट बिजली इसी साल देने लग जायेगा। इसके अलावा दूसरे जो संयन्त्र हैं वे हरियाणा के अन्दर हमें बिजली देंगे और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपनी मेहनत से हरियाणा राज्य में एक ऐसी सरकार का निर्माण किया है जो भयमुक्त है। आज आतंकवाद हरियाणा से खत्म हो चुका है। जो अत्याचार जनता पर होते थे, जो अत्याचार हमारे व्यापारी भाईयों पर होते थे, वे सारी बातें आज खत्म हो गई हैं। आज जन जन में एक आहवान है कि हरियाणा में किसी प्रकार की लूट या अत्याचार नहीं है। इसी बजह से बिजनैस के लिए जो इन्वैस्टमैंट है वह 22 हजार करोड़ रुपये हरियाणा में आ चुकी है और 53000 करोड़ रुपये की इन्वैस्टमैंट पाईपलाईन में है। इस सब का श्रेय माननीय मुख्य मन्त्री जी को जाता है इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एस०ई०जैड० के माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक लाख 75 हजार करोड़ की जो इन्वैस्टमैंट की नीति बनाई है और जिससे 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमन्त्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐजुकेशन सिस्टम के लिए अनगिनत कदम माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उठाए हैं। जिसके तहत मॉडल स्कूलों को ऐस्टेब्लिश करना है। कमजोर वर्ग के स्टूडैंटस को सहयोग देना है और जो समैस्टर सिस्टम शुरू किया गया है इससे हमारे स्टुडैटस का फ्यूचर ब्रिलियैंट हुआ है। हरियाणा के अन्दर वूमैन यूनिवर्सिटी को स्थापित करना राजीव गांधी ऐजुकेशन सिटी को स्थापित करना तथा इस शिक्षा के अलावा टैक्नीकल शिक्षा को जो प्रोत्साहन दिया गया है जिसके लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में रखा गया है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं। स्पोर्टस के लिए

139 गांवों के अन्दर स्टेडियम बनाना और इन्डोर गेम्ज़ को प्रोत्साहन देना पहली दफा है कि इतना बड़ा प्रोत्साहन सपोर्टस को दिया गया है जिससे हमारे स्कूल के विद्यार्थी और हरियाणा के आम निवासी को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और हम सपोर्टस में पूरे भारतवर्ष में अपना विशेष स्थान बना सकेंगे। सर, हरियाणा में रोड्ज का निर्माण हो रहा है वह बहुत ही बढ़िया हो रहा है इसके अलावा एन०एच० 8 और एन०एच० 22 का काम चल रहा है और यह सड़क बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हरियाणा में एक बहुत बड़ा सड़कों का जाल बनाया जा रहा है। इस बारे में मैं ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती है। पिछली सरकार के वक्त में हरियाणा में सड़कों की हालत बहुत ही खराब थी और उसकी वजह से एक्सीडैंट हुआ करते थे और लोग मरा करते थे। इस सरकार ने कुछ ही समय में बहुत ही बढ़िया सड़कों का निर्माण हरियाणा में करवाया है और अब इन सड़कों के मामले में विदेशों की सड़कों से टक्कर लेने लगेंगे। चेयरमैन सर, इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश को प्रगति के मामले में देश में नम्बर एक पर लाना चाहते हैं और हमारा विश्वास है कि यह जरूर होगा। चेयरमैन महोदय, इसके अलावा हरियाणा में लिंग अनुपात में बहुत फर्क आ गया था अब इस सरकार की कोशिशों की वजह से यह लिंग अनुपात में जो दूरी आ गई थी वह कम हो गई है। यह सब हमारे मुख्यमंत्री जी और इनकी सरकार के सहयोगियों की वजह से सम्भव हो पाया है। चेयरमैन सर, अब मैं अपनी कांस्टीचुएंसी अम्बाला छावनी की कुछ दिक्कतों के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे यहां पर मुख्यमंत्री जी के सहयोग से 80 प्रतिशत सड़कें बन चुकी हैं और जो बाकी रह गई हैं हमें उम्मीद है कि वे भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगी। अम्बाला छावनी में जो पानी की समस्या थी आज वह भी नहीं रही है। यह समस्या हमारे यहां पर बहुत बड़ी समस्या थी। इसको दूर करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं सदन में यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार के आफिसर अम्बाला छावनी में 6-2-2007 को म्युनिसिपल कमेटी में मीटिंग करके वहां पर प्रोपर्टीज की रजिस्ट्रियां बंद कर आए हैं। इसके लिए अम्बाला छावनी में बहुत ज्यादा रोष है। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस बारे में कुछ किया जाए। इसके अलावा पिछली सरकार के वक्त में बिजली विभाग द्वारा बिजली के बिल भरने सम्बन्धी जो एन०ओ०सी० लागू करी थी उसको हटाया जाए। इसके साथ ही अम्बाला छावनी में अनाज मण्डी, चारा मण्डी और घास मण्डी को वहां से बाहर ले जाया जाए। चेयरमैन सर, इसके अलावा अम्बाला छावनी में एक ट्रोमा सैन्टर बनाने की बात कही थी जो कि अभी तक नहीं बना है। चेयरमैन सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उस ट्रोमा सैन्टर को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री सुखबीर सिंह (रोहट) : चेयरमैन सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका दिया। इस अभिभाषण में इस सरकार के कामों के बारे में साफ साफ दिखाया गया है कि इन दो सालों में इस सरकार की क्या-क्या कारगुजारियां रही हैं। इस सरकार ने हर क्षेत्र में चाहे वह शिक्षा है, खेल है, व्यापार या इन्डस्ट्री है सब क्षेत्रों में तरक्की की है और अच्छा काम किया है और इस बारे में सभी साथियों ने यहां पर चर्चा भी करी है। इस सरकार ने दो साल में जो जो कार्य किए हैं वे पिछले 40 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं किए हैं। पिछली सरकारों ने तो अपना पेट भरने का काम किया था चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी और इनके सभी साथी जन सेवा के लिए इस सरकार में आए हैं। इन दो सालों में हुड्डा जी की सरकार ने जो काम किए हैं। यह पूरे देश में एक मिसाल है और देश की

[श्री सुखबीर सिंह]

हर राजनीतिक पार्टी इनसे मिसाल लेगी कि प्रदेश में कैसे तरक्की की जा सकती है। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री की सीबीआई ने इन्कवायरी करी है और उन्होंने पाया है कि उनके देश में बड़े-बड़े होटल हैं। इनका करोल बाग में भी एक बड़ा होटल हैं और इसमें प्रोफैसर सतबीर सिंह इनके पार्टनर हैं। चेयरमैन सर, हमारे यहां पर जय प्रकाश कश्यपों का लड़का था उसको इन्होंने मारकार सतबीर सिंह के ट्यूबवैल में डाल दिया था और फिर सतबीर सिंह के ऊपर 302 का केस लगा दिया। 6 महीने बाद उससे सात आठ करोड़ रुपये लेकर उसको कह दिया कि वह केस गलत है। बाद में उसको जेल से निकाल दिया और करोल बाग के होटल में उसको मैनेजर लगा दिया। जब उस होटल पर छापा पड़ा तो उसमें 100 के करीब लड़कियां नग्न अवस्था में पकड़ी गयी और आज वह होटल सील है तथा उस मैनेजर को सजा हो रखी है। **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, जो पैसा सड़कों पर, होस्पीटल्ज पर लगाना चाहिए था, गरीबों के ऊपर खर्च होना चाहिए था, किसानों की मदद के लिए खर्च होना चाहिए था वह पैसा इन्होंने होटल पर लगाया है जहां पर वेश्यावृत्ति होती है। इससे बुरी और क्या बात होगी ? लेकिन हुड्डा साहब की यह सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। सभी हल्कों की सड़कों पर रोड़ी डाली गयी है। आज विकास के कार्यों की झड़ी लगी हुई । हुड्डा साहब की पोलिसी यह है कि विकास कार्य करके आगे बढ़ो। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हरियाणा को नम्बर वन राज्य बनाने के लिए काम किए हैं हालांकि मैं तो यह मानता हूं कि अगर सर्वे करवाया जाए तो आज भी हरियाणा नम्बर वन राज्य है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं। जैसे कि डांगी साहब ने भी बोलते हुए कहा कि अभी जो ट्यूबवैल का कनैक्शन लेने के लिए प्रति पोल 7 हजार रुपये की फीस है वह बहुत ज्यादा है इसलिए इसको कम किया जाना चाहिए क्योंकि ज्यादा फीस होने के कारण बहुत से किसान ट्यूबवैल का कनैक्शन नहीं ले पाते हैं। इनकी यह बात सही है सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। अगर यह फीस आधी हो जाए तो अच्छा रहेगा। अगर सही मायनों में सरकार ने किसान की मदद करनी है तो इस बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए। कभी ओले पड़ने की वजह से, कभी बाढ़ आ जाने की वजह से या कभी सूखा पड़ जाने की वजह से किसान को तो अपनी मजदूरी भी नहीं मिल पाती है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस फीस को कम किया जाना चाहिए। अभी भी ज्यादा बारिश से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। सोनीपत जिले के गंगाना गांव में हजारों एकड़ फसल खत्म हो गयी है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसकी भी गिरदावरी होनी चाहिए। इसी तरह से बी०पी०एल० कार्ड बनाने की बात है। जब से यह सरकार बनी तब से लोग हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं कि हमारे ये कार्ड बनवाओ। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले उनके कार्ड बने ही नहीं हैं। जो साधन सम्पन्न लोग थे उनके ही ये कार्ड बने थे। काफी लोग हमारे पास इन कार्डों को बनवाने के लिए आते हैं। हालांकि अब सरकार ने इस बारे में आर्डर किए हैं सर्वे दोबारा से करवाया जाएगा लेकिन जो पहले सर्वे हुआ था वह गलत क्यों हुआ था। इस बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए और सबंधित लोगों को सजा होनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों का नुकसान होता है। जिनको बी०पी०एल० कार्ड मिलने चाहिएं उनको ये नहीं मिल पाएं हैं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं उनको भी बिना कोई पैसा लिए नियमित किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें गरीब लोग रहते हैं। मुझे पता लगा है कि इनको नियमित करने के लिए फीस लगायी जा रही है। मेरा कहना यह है कि ये गरीब लोग हैं और इनके कालोनीज़ को नियमित करने में कोई फीस नहीं लगायी जानी चाहिए। इन कालोनीज़ को

बिना फीस लिए ही रैगुलर करना चाहिए। जितनी भी अच्छी कालोनीज हैं उनमें आठ आठ फुट की गलियां है। उस समय तो कालोनाईजर्ज अपनी सुविधा के लिए वहां पर जगह बेच गए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए अगर कोई पैसा लिया जाना चाहिए तो इन कालोनाइजर्ज से ही लिया जाना चाहिएं। इन कालोनीज में चौड़ी गलियां होनी चाहिएं। दिल्ली में जिस तरह से जे०जे० कालोनी हैं, सुल्तानपुरी कालोनी हैं या मंगोलपुरी कालोनी है वहां पर आठ-आठ फुट की गलियां सरकार ने बनाकर दे रखी हैं इसलिए इस तरह से हरियाणा में भी जितनी भी अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं उनमें ऐसा किया जाना चाहिए बेशक आप आगे के लिए प्रतिबन्ध लगा दें लेकिन अब तक जो कालोनी बन चुकी हैं उनको बिना फीस लिए नियमित किया जाना चाहिए क्योंकि उनमें मजदूर गरीब लोग रह रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी यह कहते थे कि भई, जब तक मैं जिऊंगा मुख्यमंत्री रहूंगा। ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठु बनने वाली बात थी। हमारा यह कहना है कि जिस तरह से हुड्डा साहब की सरकार कार्य कर रही है उसको देखते हुए चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की भगवान लम्बी उम्र करें, लेकिन जब तक वह जिंयेंगे तब तक उनकी ही सरकार बनेगी। यह हमें पता है क्योंकि हम 24 घंटे जनता में घूमते हैं। मैं यह बात यकीनन कह सकता हूं कि ये हमेशा के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे क्योंकि यह जनता की सेवा करने वाली सरकार है। हर क्षेत्र में इस सरकार ने विकास कार्य करवाएं हैं। आप चाहे खेलों के बारे में ही देख लें। हर गांव में स्टेडियम बनवाया गया है। यह बात पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। चौटाला साहब ने खेलों की तरफ इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके परिवार में खेलने वाला कोई हुआ ही नहीं है। न पढ़ाई में उनके यहां कोई हुआ है। एल०एल०बी० या बी०ए० की सनद भी ऐसे ही ली गयी हैं और यह भी अब तो अधूरी ही रह गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के क्षेत्र में चरित्र बहुत ज्यादा गिर रहा है। टैलीविजन पर जो प्रचार किया जा रहा है इससे आज बच्चों का चरित्र ज्यादा गिर रहा है। जब हम पढ़ा करते थे तो आर्य समाज स्कूल में पढ़ते थे। वहां पर चरित्र का बहुत ध्यान रखा जाता था और योगा की शिक्षा भी दी जाती थी। आसन करवाये जाते थे ताकि पढ़ने वाले बच्चों को सहूलियत हो जाए और बच्चों का दिमाग ठीक काम करें। आजकल बच्चों का दिमाग ऐसा है कि जरा जरा सी बात पर धैर्य खो बैठते हैं और गोलियां खा लेते हैं, फांसी खा जाते हैं। यह इसलिए होता है कि आजकल बच्चे देर से उठते हैं और स्कूलों में उनको चरित्र की शिक्षा नहीं दी जाती है। स्कूलों में व्यायाम नहीं करवाए जाते इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि स्कूलों में योग की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो व्यवहार सदन में किया है वह ठीक नहीं था उसके बावजूद भी हमारे रघुबीर सिंह कादयान जी ने उनको बोलने का पूरा मौका दिया है। ऐसे फिराख दिल स्पीकर के साथ भी चौटाला जी ने बहस की। चौटाला जी यहां सारा गलत बोलते रहे। ये अपने समय में सारा का सारा पानी अपने जिले में ले गए और आज ये यहां आकर पानी की बात करते हैं। ये पानी के बारे में जानते क्या हैं। आज यहां आकर पानी के समान बंटबारे की बात करते हैं। ये यह कहते हैं कि मेरे को बोलने नहीं दिया गया। उनको पूरा बोलने का मौका दिया गया। वह भ्रष्टाचारियों, बदमाशों और गुंडों को जेलों में बैठाकर रखते थे। आए दिन जींद-हिसार में गोलियां चलती थी। पुलिस में जो भर्तियां होती थी उसके लिए रोहतक जेल से फोन होता था। किसी हवलदार का ट्रांसफर कर दिया था। खुद को हवलदार बता रहा था। मेरे पास आया और बोला कि मिठाई का डिब्बा लेकर रोहतक जेल में जाऊंगा। वहां मैंने कृष्ण बदमाश से बदली करवानी है। उस समय ट्रांसफर जेल में बैठे गुंडे बदमाशों की सिफारिश से होती थी, इससे ज्यादा घटिया और क्या बात होगी ? मैं तो एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जैसे हुड्डा साहब ने कोर्ट के बारे प्रस्ताव इस

[श्री सुखबीर सिंह]

सदन में पारित करके केन्द्र को भेजा था ऐसा ही कोई प्रस्ताव हम सब मिलकर इस सदन में पारित करें जिसके तहत चौटाला को इस हाउस में घुसने ही नहीं दिया जाए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, और भी कोई ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि Man is known by the company तथा एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। स्पीकर साहब, हुड्डा साहब की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी एक मिसाल हैं। इनको हर आदमी से लगाव है। वे हर किसी को कुछ न कुछ देना चाहते हैं। चौटाला को तो सिर्फ कुर्सी हथियाने से मतलब है। जो जातपात की राजनीति करता है, बदमाशी की राजनीति करता है उसके दिमाग में क्या होगा ? हरिजन और जाट में लड़ाई हो जाए तो दोनों के पास बैठने वाला नेता चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला और भजन लाल का लड़ाई कराने का काम है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा वह इंसान हैं जो बनिया, पंजाबी, ब्राह्मण, कर्मचारी, जाट, हरिजन सभी जातियों और सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखते हैं। हर आदमी इनसे खुश है। इन्होंने तीन यूनीवर्सिटीज सोनीपत में दे दी। हमारे सोनीपत को चालीस सालों में एक कालेज भी नहीं मिला था। आज सोनीपत ऐजुकेशन का सैंटर बन गया है। सोनीपत के दसवीं पढ़े हुए लड़के लड़कियां आई०ए०एस०, आई०पी०एस० बनते हैं और यहां हर क्षेत्र से दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। वहां आज तक कोई सरकार एक गवर्नमैंट कालेज तक नहीं दे सकी थी और आज वहां तीन तीन यूनिवर्सिटीज हैं। यह कितनी बड़ी बात है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने टिब्बों में (सिरसा के अन्दर) यूनिवर्सिटी बना दी जहां कोई पढ़ने वाला ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : फरमाणा साहब, आप वाईंड-अप कीजिए।

श्री सुखबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है और विकास के कार्य कर रही है। आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, गवर्नर एड्रैस पर जिन भी माननीय सदस्यों ने डिसकशन में भाग लिया उनमें 12 तारीख को कुल तकरीबन 230 मिनट तक सभी मैम्बर साहेबान बोले जिनमें 142 मिनट कांग्रेस पार्टी के मैम्बर साहेबान बोले, 88 मिनट आई०एन०एल०डी०पार्टी के मैम्बर साहेबान बोले, 13 तारीख को 114 मिनट कांग्रेस पार्टी के मैम्बर साहेबान बोले, 19 मिनट आई०एन०एल०डी०पार्टी के मैम्बर साहेबान बोले, 22 मिनट बी०जे०पी० के मैम्बर साहेबान बोले, 14 मिनट बी०एस० पी० के मैम्बर साहेबान बोले और 29 मिनट इडीपैंडेंट मैम्बर साहेबान बोले। इस प्रकार टोटल तकरीबन आठ घण्टे 20 मिनट गवर्नर एड्रैस पर डिसकशन चली है और सभी आनरेबल मैम्बर्ज ने अपने-अपने सुझाव दिए हैं और पूरी तफशील से चर्चा हुई है। Hon'ble Members, now the Chief Minister will give the reply.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : धन्यवाद अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय ने 09.03.2007 को जो अभिभाषण इस सदन में दिया था। मैं समूचे सदन की तरफ से राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीति आज के गरीब मजदूर, खेतीहर किसान और आम आदमी पर केन्द्रित है और पिछले दो साल में जितनी भी नीतियां बनाई गई हैं इसी बात को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। जब कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली

और पहली कैबिनेट मीटिंग हमने की तब मैंने सभी माननीय सदस्यों को एक ही बात कही थी कि हम यहां जो भी फैसला करें तो फैसला करते समय उस गरीब से गरीब आदमी को ध्यान में रखकर फैसला करें कि उस फैसले से गरीब से गरीब आदमी को क्या लाभ मिलेगा। यही हमारी नीति का आधार है। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और गांव के किसान और मजदूर की क्या समस्या होती है। उससे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। चाहे वह गांव का इलाका हो, चाहे प्रदेश का या देश का इस संदर्भ में अगर विकास करना है तो उसके लिए तीन चीजें जरूरी हैं उन तीन चीजों में से अगर एक चीज की भी कमी रहेगी या एक भी चीज उपलब्ध नहीं होगी तो फिर हमारा विकास नहीं हो सकता। ये तीन चीजें हैं बिजली, पानी और कानून व्यवस्था। अगर तीन चीजें हों तो इन्फ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बन सकता है और उस इन्फ्रास्ट्रक्चर से हम विकास भी कर सकते हैं। जो सरकार ने पिछले दो साल में कार्यवाही की है उनके बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा होता अगर हमारे सारे विपक्ष के साथी भी सदन में होते। इस दौरान जो चर्चा हुई है उसमें सभी पार्टियों के सदस्यों ने हिस्सा लिया है। जैसा कि आपने बताया उसमें बी०जे०पी० हो, चाहे एन०सी०पी० हो, चाहे इंडीपैंडेंट हो और चाहे बी०एस०पी० हो या कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे सभी पार्टियों के सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, अपने-अपने सुझाव और अपनी -अपनी बात रखी, बहुत अच्छे सुझाव भी आये, सरकार की नीतियों पर भी प्रकाश डाला गया जिस-जिस सदस्य ने अपने विचार रखे और जो-जो सुझाव रखे मैं सदन की तरफ से उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि उन विचारों पर जितना भी हो सकेगा पूरा अमल किया जायेगा। अच्छे सुझाव भी आये हैं, कई माननीय सदस्यों ने अपनी हल्के की समस्या की बात भी कही है, अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या भी उठाई हैं। हमने सभी बातों को नोट कर लिया है और उन पर अमल करने का पूरा प्रयास किया जायेगा। लेकिन बड़े खेद की बात है कि जो हमारे इनैलो के विपक्ष के साथियों को आपने 88 मिनट बोलने का समय पहले दिन दिया और 19 मिनट का समय दूसरे दिन दिया। लेकिन इस समय में उन माननीय सदस्यों ने कोई बात नहीं कही। मैं किसी की निन्दा करने का आदि नहीं हूं लेकिन जो लिस्ट आपने बताई वह सबके सामने है। इनैलो के सदस्यों ने जो भी चर्चा की, जो भी मुद्दे उठाये, जिस प्रकार की भी बातें कहीं, वे सब बातें सदन को और प्रदेश के लोगों को गुमराह करने वाली कही और मैं इस बात को सबूत के साथ साबित कर सकता हूं। कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि यदि कोई माननीय सदस्य हमें अच्छे सुझाव देगा तो हम उनको मानेंगे लेकिन विपक्ष के साथियों ने सदन को गुमराह करने के अलावा और कोई बात नहीं करी। जिस प्रकार से चौटाला ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की वह न उनके हित में है और न प्रदेश के हित में है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि दो-तीन चीजें किसी भी प्रदेश के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। हमारा प्रांत कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि के क्षेत्र में हमें समृद्ध होना है तो उसके लिए बिजली और पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि हम किसानों को पूरी बिजली और पानी मुहैया करवायें। अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में और हमारी सरकार के समय में फसलों की प्रोक्योरमैंट कितनी-कितनी हुई है। हमारी सरकार ने चाहे सरसों की फसल हो या कोई और जीन्स हो एक-एक दाना किसान की फसल का खरीदा है। मैं रिकार्ड के आधार पर कह सकता हूं कि हमारे समय में फसलों के उत्पादन में भी भारी बढ़ौतरी हुई है। अध्यक्ष महोदय, 2004-2005 में खरीफ की फसलों में 38.59 लाख टन का उत्पादन हुआ था और वही उत्पादन बढ़कर 2006-07

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

में 44.98 लाख टन हो गया यानि कि पिछले वर्षों के मुकाबले में 6.39 लाख टन अधिक उत्पादन हुआ है। इसी प्रकार से रबी की फसलों में वर्ष 2004-05 में कुल उत्पादन 91.98 लाख टन हुआ था वह अब वर्ष 2006-07 में 100.99 लाख टन होने का अनुमान है यानि कि 8.96 लाख टन ज्यादा उत्पादन होने की संभावना है। इसी प्रकार से सरसों की फसल जो हमारे दक्षिणी हरियाणा से लेकर सिरसा के एरियाज तक बोई जाती है, कहीं कम बोई जाती है, कहीं ज्यादा बोई जाती है। उसकी खरीद वर्ष 2003-04 में शून्य थी, वर्ष 2004-05 में भी शून्य थी। उस समय किसान मण्डियों में चक्कर काटते रहे लेकिन उनकी सरसों की फसल खरीदने वाला कोई नहीं था। उसके बाद हमारी सरकार के समय में वर्ष 2005-06 में 3.60 लाख क्विंटल सरसों खरीदी गई और वर्ष 2006-07 में 4.50 लाख क्विंटल खरीदी गई यानि कि जितनी भी सरसों किसान मण्डियों में लेकर आये वह हमने सारी की सारी खरीदी जबकि पिछली सरकार ने एक दाना किसानों का नहीं खरीदा। अध्यक्ष महोदय, यह सब मैं रिकार्ड की बातें बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सदन में गन्ने के बारे में भी काफी चर्चा हुई। ओम प्रकाश चौटाला जी ने गन्ने के रेट को लेकर भी सदन को गुमराह करने का प्रयास किया रिकार्ड के आधार पर मैं सदन को बताना चाहूंगा कि वर्ष 1999-2000 में गन्ने का भाव 110 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाता था और आज 138 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जा रहा है जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। चौटाला जी इस समय सदन में नहीं बैठे। अच्छा होता यदि आज वे सदन में होते और मेरी बातें सुनते जो कि मैं रिकार्ड के आधार पर बता रहा हूं। चौटाला जी ने सदन को गुमराह करते हुए कहा कि उनकी सरकार के समय में चीनी का भाव 7 रुपये प्रति किलो था और गन्ने का भाव उस समय 110 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, मैं रिकार्ड के आधार पर पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि 1999-2000 में चीनी का भाव 14.20 रुपये प्रति किलों का था और आज चीनी का भाव 15.50 रुपये प्रति किलो है। चीनी का भाव आज उस समय से 1.30 रुपये ज्यादा है लेकिन गन्ने का भाव 138 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कपास की खेती के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में कपास वर्ष 2005-06 में 10 हजार एकड़ जमीन में बोई जाती थी। जबकि वर्ष 2006-07 में दो लाख एकड़ भूमि में बोई जा रही है। कपास की फसल किसान की आर्थिक स्थिति को बदलने वाली फसल है। इसी प्रकार से यहां खाद की भी चर्चा आई और यह कहा गया कि खाद की कमी है तो मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि 2 साल से जब से यह सरकार आई है खाद की बहुत जरूरत थी और हमने किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाया। जो आँकड़े मैं बताने जा रहा हूँ ये आँकड़े खुद अपने आप दर्शाते हैं कि हमने पूरा खाद पर्याप्त मात्रा में किसानों को दिया है। सन् 2004-05 में 12.15 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद उपलब्ध करवाया गया था और वर्ष 2006-07 में 28 फरवरी, 2007 तक 16.16 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद हमने उपलब्ध करवाया है। इसी प्रकार डी०ए०पी०2004-05 में 4.85 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध करवाया गया था और 28 फरवरी, 2007 तक हमने 4.88 लाख मीट्रिक टन डी०ए०पी०खाद उपलब्ध करवाया है। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में हमने बढ़ोतरी की है। अध्यक्ष महोदय, आपको और मेरे सभी साथियों को ध्यान होगा कि जब पिछली सरकार का समय था खाद की पर्ची पुलिस थाने में मिलती थी और अबकी बार हमारा खाद का वितरण सही तरीके से हुआ है। जहाँ तक बीज का सम्बन्ध है तो आँकड़े अपने आप दर्शाते हैं कि हम कितने प्रयत्नशील हैं और कितना हम चाहते हैं कि किसानों को अच्छे बीज मिलें ताकि उसकी फसल की पैदावार अच्छी हो

और उसकी आमदनी बढ़े। गेहूँ का बीज जो हमने किसानों को दिया उसके आँकड़े आप देखिए 2004-05 में 4.70 लाख टन गेहूं का बीज किसानों को उपलब्ध करवाया गया और 2006-07 में 5.49 लाख टन गेहूँ का बीज किसानों को उपलब्ध करवाया गया है। वर्ष 2004-05 में 29 हजार क्विंटल और वर्ष 2006-07 में 35 हजार क्विंटल धान का बीज हमने किसानों को दिया है। ढैंचे के बीज के बारे में कृषि मंत्री जी ने बताया है कि वह 3 हजार क्विंटल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, बिजली के बिलों की एक बड़ी गम्भीर समस्या थी जिससे केवल हमारे किसान ही नहीं बल्कि पूरी ग्रामीण जनता चाहे वे किसान भाई हों चाहे वे पिछड़े वर्ग से हैं चाहे अनुसूचित जाति से हैं जो भी गाँवों में रहते हैं, सभी झुलस रहे थे। आपने देखा यह सरकार बनने से पहले हमारे विपक्ष के साथियों ने लोगों को गुमराह करने का काम किया कि हमें सत्ता में लाओ फिर हम बिजली और पानी मुफ्त देंगे और जब बिजली के ट्रांसफार्मर को बदलने की बात आई तो जीन्द में जिस प्रकार बेकसूर किसान मारे गये उस बात का आप सबको मालूम है। उसके विरोध में जब हमने जीन्द से लेकर दिल्ली तक पद यात्रा निकाली तो रास्ते में हाँसी में मुझे 4-5 बुजुर्ग मिले। उन्होंने मेरे को कहा और कहते हुए उनकी आँखों में आंसू आए हुए थे उन्होंने कहा कि ये बिजली के बिल जो एक एक आदमी के खिलाफ इतने खड़े हैं कि किसी के खिलाफ 3 लाख रुपये किसी के खिलाफ 2 लाख रुपये बकाया है। उनको भरने के लिए अगर हम अपने सारे घर और जमीन भी बेच दें तो भी ये बिजली के बाकी बिल नहीं भर सकते। यह इतनी गम्भीर समस्या थी और इन बिलों के लिए किसी प्रकार की रियायत घोषणा उस समय नहीं की गई थी। उसके बाद चुनावों के समय हमने घोषणा पत्र में तो इन बिलों की रियायत की बात नहीं डाली लेकिन जब यह सरकार बनी तो वो उस बुजुर्ग वाली बात मेरे दिमाग में घूम रही थी तो मैंने फैसला किया कि इन बिजली के बिलों की समस्या से लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि बड़े से बड़े प्रदेशों के आप बजट मंगवा लें। हर साल प्रदेशों के बजट पेश होते हैं। प्रदेश किसानों को, मजदूरों को, ग्रामीणों को, रियायतें भी देते हैं। कहीं किसी प्रदेश ने 80 करोड़ रुपये की रियायत दी होगी, किसी प्रदेश ने 100 करोड़ रुपये की रियायत दे दी होगी, बड़े प्रदेश जहाँ पर हैं वहाँ 150 करोड़ रुपये की रियायत दे दी गई होगी लेकिन मेरा दावा है कि जब से देश आजाद हुआ है किसी प्रदेश ने एक साथ एक कलम से 1600 करोड़ रुपये की सहायता नहीं दी होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा दावा है कि 1600 करोड़ रुपये एक कलम से मुआफ तो इसी सरकार ने पूरे देश में पहली बार ही किये हैं जो कि प्रदेश की उस समस्या का समाधान करने के लिए छोटी बात नहीं थी। जहां तक इसका लाभ देने का सवाल है तो इसका लाभ सब को पहुंचा है। लगभग 12 लाख से ज्यादा डिफाल्टरज हमारे प्रदेश में थे जो बिजली के इन बकाया भारी बिलों को नहीं भर सकते थे और इस स्कीम का लाभ 12 लाख लोगों में से 9 लाख लोग उठा चुके हैं और वे अब बिलों की पेमैंट रैगुलर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी नरेश मलिक साहब जो बात कह रहे थे मैं इनको बताना चाहता हूं कि 9 लाख लोग इस स्कीम का लाभ उठा चुके हैं और जो लोग रह गए हैं उनको भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : वे कर्जे की बात कह रहे थे कर्जे में और ब्याज में तो फर्क है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, वे बिजली के बिलों की मुआफी के बारे में भी कह रहे थे। अखबार में कोई आंकड़े आ जाते हैं तो वे उनको ही सही मान लेते हैं वे उनको वैरीफाई नहीं करते। लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं है इसलिए मैं इस बात की चर्चा नहीं करता।

श्री नरेश मलिक : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दरिया दिली दिखाई मैं मानता हूं कि बिजली के बकाया बिलों का लगभग 9 लाख लोगों ने लाभ उठाया लेकिन मुख्य मन्त्री जी, मैं किसी बुरी मन्शा से यह बात नहीं कह रहा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि यह आंकड़े कोई झूठे नहीं है। मैंने जो बात कहीं उसमें ऐसी कोई बात नहीं हैं। मैं मानता हूं कि आपके दिल में जमींदारों के प्रति दर्द है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं तथा जिन गांवों के किसानों के बिजली के बिल बकाया हैं उनमें माननीय मुख्य मन्त्री जी का गांव भी शामिल है। इसके अलावा 5-6 और भी गांव हैं (विघ्न) इसमें किलोई गांव के किसानों की तरफ लगभग 24 करोड़ रुपये का बकाया है जो कि 89% है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बकाया बिलों की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप यह बताएं कि यह मुआफ हुआ या कि अभी बकाया खड़ा है।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, आज भी यह बकाया किसानों पर खड़ा है। धामड़ गांव का 12 करोड़ रुपये 85% व्यक्तियों पर, खड़वाली गांव का 8 करोड़ 73% व्यक्तियों पर(विघ्न) मैं प्वायंट आफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं और माननीय मुख्य मन्त्री जी से इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि किसान के ऊपर 8-8, 10-10 लाख रुपये आज भी बिजली के बिलों का बकाया है जो कि वे बेचारे नहीं दे सकते। जिन्होंने इस तरह का लाभ उठाया है उनके साथ ही मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सब को भी मुआफ किया जाए। जो किसान बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते मेरा केवल इतना ही अनुरोध था कि उनके बिजली के बकाया बिलों को भी मुआफ किया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मलिक साहब, ऐसा है कि जो आखिरी किश्त भरवा जाएगा उसके बाद बकाया मुआफ होगा। आपने सांघी गांव का जो नाम लिया है मैं आपकी इन्फर्मेशन के लिए यह बता देता हूं कि 806 लोगों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है और 57% रिकवरी हुई है। 12 करोड़ 10 लाख रुपये का वहां के लोगों को लाभ हुआ है। इसी प्रकार से गांव धामड़ में 606 कन्जयूमर्ज हैं जिनमें से 446 लोगों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है और 74% लोगों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है और 9 करोड़ 38 लाख रुपये का लाभ धामड़ गांव के किसानों और मजदूरों को हुआ है। (विघ्न) जब पूरी किश्त आ जाएगी उसके बाद ही तो मुआफ होंगे, हमारा यह प्रयास है कि लोग बिल जमा करवाएं आप उनको इस बात के लिए कहें। अगर लोगों को बिल जमा करवाने के लिए कह रहे हैं तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है क्योंकि बिजली की चोरी की छुट्टी तो नहीं दी जा सकती। स्पीकर सर, जो यह अनूठी स्कीम हमने लागू की है तो इसके लिए हमें हौंसला चाहिए, अगर ऐसे फैसलों में भी हाउस के साथी साथ नहीं देंगे तो फिर जनहित के फैसले कैसे लिये जाएंगे। यह बहुत बड़ा फैसला था।

आवाजें : सरकार ने जो यह फैसला लिया है इसको हम अप्रूव करते हैं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ठीक है, आपका धन्यवाद। इसके अलावा जो किसान हैं, ग्रामीण दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, छोटे दुकानदार हैं जिन्होंने को-आपरेटिव बैंकों से कर्जा लिया हुआ है और जो अपना कर्जा उतारने में असमर्थ हैं क्योंकि मूल के साथ ब्याज भी काफी ज्यादा हो गया है, आप सब को मालूम है कि उसके लिए भी हमने सिरसा रैली में ऐलान किया था कि 30 जून,

2007 तक जो भी मूल की राशि चुका देगा उसका पूरा ब्याज हम मुआफ करेंगे। इस ब्याज माफी से आठ लाख परिवारों को 513 करोड़ रुपये का लाभ होगा जो केवल को-आपरेटिव बैंकों के ही हैं। इसके अलावा जो लोग लैंड डिवैल्पमैंट बैंकों का कर्जा देने में असमर्थ हैं वे अगर दिनांक 30.06.2007 तक असल कर्ज वापिस कर देंगे तो उनको पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इससे करीब 1 लाख 40 हजार परिवारों को लाभ होगा और उनको 217 करोड़ रुपए की छूट मिली है। जिन्होंने समय पर कर्जा दिया है हमने उनको बैनिफिट दिया है और समय पर कर्जा देने वाले को हमने 2 प्रतिशत की ब्याज की छूट से लोनिज़ को 50 करोड़ रुपए का लाभ होगा और कुल मिलाकर इससे 9 लाख 40 हजार परिवारों को 820 करोड़ का फायदा होगा। हमारे से पहले तो कर्जा माफी के नाम पर सरकारें बन गई थी और आज वे स्वर्ग में हैं। (विघ्न) मैं किसी की निन्दा करने का आदी नहीं हूं। उन्होंने लोगों को कहा कि आप मेरी सरकार बनवा दो तो मैं आपके कर्जे माफ कर दूंगा, ऊपर लिखा होगा कि कर्जा माफ और नीचे चौधरी देवी लाल लिखा होगा। लेकिन उस वक्त लोगों ने उनका विश्वास करके उनकी सरकार बनवा दी थी लेकिन कितने लोगों को फायदा हुआ था। अध्यक्ष महोदय, यह तो आपको भी पता होगा क्योंकि उस वक्त आप कोआप्रेटिव मिनिस्टर थे। उस समय 12 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए थे। अध्यक्ष महोदय, कहां 12 करोड़ रुपए की माफी और आज कहां 1600 करोड़ रुपए की माफी। क्या 1600 करोड़ रुपए से वे 12 करोड़ रुपए की तुलना कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं जो कृषि पर 10 प्रतिशत और शार्ट टर्म लोन पर 14 प्रतिशत का इन्ट्रस्ट था उसको हमने कम करके 7 प्रतिशत किया है। इससे काफी लोगों को लाभ पहुंचा है। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, सदन में ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान से सम्बन्धित बात आई है। इस बारे में मैं सदन में बताना चाहूंगा कि 11-5-2000 में जो मुआवजा दिया गया था वह 26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक गेहूं की फसल के नुकसान पर 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिए गए थे और आज हम 10.1.2007 को 1000 रुपए प्रति एकड़ के मुकाबले में 3000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं और अन्य फसलों के लिए 50 प्रतिशत तक नुकसान पर 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं। उस वक्त गेहूं अगर 51 से 75 प्रतिशत बर्बाद हो गई थी तो उसके लिए उस समय 1500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था और हम इसके मुकाबले में 4000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं। अन्य फसलों पर 51 से 75 प्रतिशत नुकसान पर उस वक्त 1500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता था हम इसके मुकाबले में 3000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। उस वक्त जिस फसल का 75 प्रतिशत नुकसान हुआ उसको 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था जबकि हम फसल के 75 प्रतिशत नुकसान पर 5000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं और अन्य फसलों के लिए हम 75 प्रतिशत नुकसान पर 4000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नैचुरल कलैमिटी के लिए हमारा एस्टीमेट 70 करोड़ रुपए अनुमानित था और अब कल की ओलावृष्टि की वजह से यह 100 करोड़ रुपए हो जाएगा।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मुख्यमंत्री जी ने किसानों की फसलों के हुए नुक्सान के लिए प्रति प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं एक किसान के बेटे हैं जो घोषणा की गयी है क्या वह किसान की लागत है ? कम से कम दस हजार रुपये प्रति एकड़ तक यह मुआवजा होना चाहिए और सरकार को इसकी घोषणा करनी चाहिए। मैंने एक और अनुरोध किया था।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप चेयर को ऐड्रैस करें।

श्री नरेश मलिक : सर, मैं चेयर को ही ऐड्रैस कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आपकी बात ठीक नहीं है, सदन का नेता अपनी बात कन्टीन्यू कर रहा है आप इस तरह क्यों बीच में खड़े हो रहे हैं ? आप बैठ जाएं।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, हमारा पूछने का हक है। क्या आप हर एक के साथ ही ऐसा व्यवहार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप किस रूल के तहत खड़े हो ? किस बात के लिए आप प्वायंट ऑफ आर्डर ले रहे हो ? आपको सीरियसली लेना चाहिए। क्या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं ? किसानों की बात चल रही है, किसान बर्बाद हुआ पड़ा है और मुख्यमंत्री महोदय किसानों को मुआवजा देने की बात कर रहे हैं और आप इस तरह से बीच में खड़े हो रहे हैं। आप बैठिए।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं भी उसी किसान की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, मलिक साहब, आप बैठिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनकी बात सुन ली है। हम इससे भी ज्यादा मुआवजा दे सकते हैं लेकिन ये बताएं कि क्या पूरे देश में इससे ज्यादा कहीं मुआवजा दिया जा रहा है ? इनकी भी कई प्रदेशों में सरकारें हैं ये बताए। अध्यक्ष महोदय, यदि कोई अच्छी बात हो तो उसकी ऐप्रीशिएशन जरूर करनी चाहिए। मलिक साहब, आप तो बिजनैसमैन हैं। आमदनी और खर्चा देखते हैं। खर्चे का भी हिसाब देखना होता है। कहना बहुत आसान है लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। कह तो देवीलाल जी ने भी दिया था कि कर्जा माफ कर देंगे लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई अच्छा काम हो तो उसका स्वागत भी करना चाहिए।

श्री रामकुमार गौतम : ऑन ए प्वायंट आफ आर्डर सर, स्पीकर साहब, शायद मुख्यमंत्री जी सुन नहीं सके इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि जब 1995 में बाढ़ आयी थी तो ऐसे हमारे हल्कों में अनेक केसिज थे जिनमें मुआवजा ही नहीं मिला था। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जोकि बहुत अच्छे आदमी थे, उस समय चार बार मंत्री रह लिए थे लेकिन इसी कारण वे भी दोबारा से एम०एल०ए० नहीं बन सके थे कि उस समय ऐसे लोग भी मुआवजा ले गये जिनका उस मुआवजे पर कोई हक ही नहीं बनता था। इसलिए इस बारे में खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है कि किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए और जिसका इस मुआवजे पर हक न बने वे इसे ले न जाएं।

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, यह बात छत्रपाल जी ने भी उठायी थी। यह सारा मामला पटवारी के साथ बैठकर ही सैटल होगा। आप बैठें।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, माफ करना, मुझे पता नहीं था कि उन्होंने भी यह मामला उठाया था। मैंने सुना नहीं था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारा भी इस बारे में पूरा प्रयास रहेगा क्योंकि हम लोगों के नुमाइन्दे हैं। मेरा गौतम साहब से भी निवेदन है कि उनकी भी यह जिम्मेवारी हैं कि

विधायक होने के नाते अगर कहीं पर कुछ गडबड़ उन्हें या दूसरे विधायकों को अपने अपने हल्के में नजर आए तो वे यह बात कह सकते हैं फौरन उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कोई बिजनैस करता है, इन्वैस्टमैंट करता है और यदि उसका हजार का ब्यौत होता है तो ही वह लखपति बनता है और लखपति से करोड़पति बनता है। लेकिन इस सरकार के भूमि अधिग्रहण के एक फैसले से ही रातोंरात लोग करोड़पति बन गये। भूमि अधिग्रहण के मामले में हमने पूरे प्रदेश का फ्लोर रेट फिक्स किया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे कितना लाभ हुआ है। 135 किलोमीटर लम्बा एक्सप्रैस हाई वे बन रहा है इसको के०एम०पी० यानि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रैस हाई वे कहते हैं। इसकी भूमि अधिग्रहण का मामला पिछली सरकार के समय में से चला हुआ था। उस समय की कैबिनेट ने इस बारे में जो फैसला लिया था मेरे पास उसकी कॉपी है। जो उस समय प्रपोजल बनी और जो उसमें कोस्ट ऑफ इक्विजिशन 135 किलोमीटर की थी इसके लिए 3 हजार एकड़ से ज्यादा 3450 एकड़ भूमि ऐक्वायर होनी थी। कॉस्ट ऑफ ऐक्वीजिशन 170 करोड़ रुपये आंका गया है। वहां पर जाकर 167 करोड़ रुपये असैस हुआ है। उसके बेसिज पर फैसला हो गया कि मुआवजे की कॉस्ट 167 करोड़ रुपये हम यहां के किसान को जिसकी भूमि अधिग्रहण होगी, उस किसान को देंगे। हमारे इस फैसले से रातों रात लोग करोड़पति बने हैं। यह फैसला लेने के बाद अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक प्रौजैक्ट जो ऐक्सप्रैस वे है उसमें 167 करोड़ रुपये मुआवजा मिलना था लेकिन किसान को 167 करोड़ रुपये की बजाय 650 करोड़ रुपये का मुआवजा मिल रहा है। सिर्फ एक ही प्रौजेक्ट में 500 करोड़ रुपये का लाभ मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, फिर यहां सिंचाई की चर्चा आई। किसान के लिए पानी बहुत जरूरी है। उसके बगैर कृषि का कोई उत्पादन नहीं हो सकता लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार के आने से पहले पानी के नाम पर लोगों को गुमराह करके यहां राजनीति हो रही थी। आज उस सारी राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। कभी एस०वाई०एल० के नाम से यह कह दिया कि चलो एस०वाई०एल० खुदवाएंगे। कल एस०वाई०एल० मुद्दे पर पूरी चर्चा हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, आपको पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि एक क्यूसिक पानी नहीं बढ़ा। लेकिन आंकड़े अपने आप बता देते हैं कि कितना क्यूसिक पानी बढ़ा है। खरीफ 2004 में नहर के पानी की 14000 क्यूसिक्स प्रतिदिन की आपूर्ति की गई। खरीफ 2006 में 14 हजार क्यूसिक्स से बढ़ाकर 17445 क्यूसिक्स पानी की उपलब्धता किसानों को प्रदान की गई। इसी प्रकार से रबी 2004-05 में कुल 8939 क्यूसिक पानी उपलब्ध कराया गया और रबी 2005-06 में 12189 क्यूसिक्स पानी उपलब्ध कराया गया। श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला जी कह रहे थे कि एक क्यूसिक पानी नहीं बढ़ाया। जिन गांवों की टेलों पर आज तक पानी नहीं पहुंचा था उन गांवों के लोग आज स्वयं मुझे बताकर गए हैं कि उन टेलों पर पानी पहुंचा है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पिछले साढे पांच साल में एक बूंद भी पानी टेलों तक नहीं गया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आज सारी टेलों तक पानी पहुंचाने का काम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पानी का न्यायोचित बंटवारा हो, जिनका हक है उनको पानी मिले और रिचार्जिंग पूरी हो और हर इलाके को फायदा हो इसलिए हमने दो नई नहरों के निर्माण का कार्य शुरू किया है। जिनमें से एक तो हांसी बुटाना लिंक नहर जिसका 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसकी कैपेसिटी 2000 क्यूसिक पानी की होगी और इस पर 350 करोड़ रुपये की लागत

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

आएगी। अक्टूबर-नवंबर तक यह बनकर तैयार हो जाएगी। चौटाला जी ऊपर प्रैस में कुछ कहते हैं और यहां कुछ कहते हैं। प्रैस के एक साथी ने मुझे बताया कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने यहां कहा कि हमने कभी उस नहर का विरोध नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो मैं रिकार्ड दे सकता हूं। इनके पुत्र की स्टेटमैंट है नई नहर खुदने से आंतरिक जल युद्ध छिड़ जाएगा। न्यायोचित कहने की बजाय इन्होंने इसका विरोध किया है और गृह युद्ध तक की बात कही है तब मुझे मजबूरन कहना पड़ा कि यह गृह युद्ध की बात आप क्यों कर रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, अगर इस बात को गृह युद्ध करना कहते हैं तो हरियाणा के लोग मक्षा युद्ध करने के लिए तैयार हैं। यह बड़े दुख की बात है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी शाहबाद-दादूपुर-नलवी नहर बनाने की योजना की बात है। आप पहले भी विधान सभा के सदस्य रहे हैं, बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार यहां सदस्य बनकर आये हैं और कुछ माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जो तीन-तीन बार या चार-चार बार विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। आप रिकार्ड उठाकर देख लें कोई भी सैशन ऐसा नहीं होगा जिसमें दादूपुर नलवी नहर के बनाने की चर्चा न हुई हो लेकिन इस नहर को बनाने का काम कभी भी शुरू नहीं हुआ। पिछले 20 वर्षों से इस नहर को बनाने के लिए यहां पर चर्चा होती रही है। इस नहर के बनने से अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और पंचकूला इन चार जिलों को बहुत लाभ मिलेगा। इस नहर को बनाने का कार्य हमने शुरू कर दिया है और इस काम के लिए समय भी निर्धारित कर दिया है और इस नहर का 15 प्रतिशत कार्य पूरा भी हो चुका है। इस नहर के काम को करने के लिए कुल 260 करोड़ रुपये की योजना है। अध्यक्ष महोदय, पानी के बारे में चर्चा हो रही थी। सिरसा जिले में एक ओटू वीयर नहर है। इस नहर से वहां के क्षेत्र को काफी लाभ होता है और इस नहर से पांच हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इस नहर की गाद को निकलवाने के लिए और खुदाई करवाने के लिए 55 करोड़ रुपये की स्कीम सरकार ने मन्जूर की है। जिससे वहां के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। जैसा कि मैंने सिरसा रैली में एलान किया था दो साल के अन्दर-अन्दर जितने भी हरियाणा में खालें और नहरें है उनकी मरम्मत की जायेगी और नये खालें जिनका निर्माण होना है उनका निर्माण किया जायेगा। इसके लिए 454 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 100 करोड़ रुपये इस साल खर्च किए जायेंगे। वर्ष 2004-2005 के बजट में पिछली सरकार के समय में इसके लिए 151.65 करोड़ रुपये खर्च किए गये जबकि हमारी सरकार ने वर्ष 2006-07 में 357 करोड़ रुपये इरीगेशन विभाग के लिए खर्च किए हैं जबकि पिछली सरकार के समय में 27 करोड़ रुपये नॉन प्लान के थे जबकि हमारे नॉन प्लान के 48 करोड़ रूपये हैं। पिछली सरकार ने इरीगेशन विभाग के लिए 179.19 करोड़ रुपये खर्च किए जबकि हमारी सरकार ने प्लान और नॉन प्लान के मिलाकर 405.9 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कम से कम दोगुणा से ज्यादा अन्तर है। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० के बारे में बार-बार चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० के बारे में सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि वह हरियाणा की जीवन रेखा है और उसके लिए सदैव प्रयास किए गये। एस०वाई०एल० की जब भी खुदाई हुई है वह केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुई है। पहले श्रीमती इन्दिरा गान्धी जी के समय में, बाद में श्री राजीव गान्धी जी के समय में खुदाई हुई और आज भी मैं कह रहा हूं कि आज अगर एस०वाई०एल० की खुदाई होगी तो अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में ही एस०वाई०एल० की खुदाई को पूरा किया जाएगा और किसी सरकार के समय में नहीं । यह सब आपने देख लिया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि वे लोग एस०वाई०एल० की

चर्चा करते हैं जो पंजाब के पिछले चुनावों में अकाली दल की स्पोर्ट करने के लिए गये थे। श्री ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी पंजाब में अकाली दल पार्टी की स्पोर्ट करने के लिए गये थे। मैं भी कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट में गया था वहां पर मेरे से भी पानी के बारे में प्रश्न पूछे गये कि पानी का मुद्दा है फिर भी आप कांग्रेस पार्टी के लिए स्पोर्ट करने के लिए आये हैं। उस के जवाब में मैंने कहा कि यह पार्टी का मामला है लेकिन हम अपने हिस्से का पानी ले कर रहेंगे। मैं तो अपनी पार्टी की स्पोर्ट के लिए आया हूं। कोई श्री ओमप्रकाश चौटाला जी से पूछे कि क्या उनकी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही थी या उनकी पार्टी का अकाली दल पार्टी के साथ कोई एलायन्स था। अब गौतम साहब की पार्टी वहां पर चुनाव लड रही थी अगर इनको वहां जाना पड़ता तो ये चले जाते। अब उनसे कोई पूछे कि ये कौन सी पार्टी के लिए पंजाब में वोट मांगने गये थे किस पार्टी के समर्थन में गये थे। वे जिस पार्टी के समर्थन में गये थे, प्रकाश सिंह बादल जी की अकाली दल पार्टी उसका मैनीफैस्टो मेरे पास है। मैं उस मैनीफैस्टों के पेज नम्बर-2 पर जो लिखा हुआ है वह पढ़कर सुनाता हूं-

"शिरोमणी अकाली दल दा हमेशा इही स्टैंड रिहा है कि पंजाब दे पाणीयां ऊपर किसे होर सुबे दा हक नहीं। असे पार्टी इक वी बूंद पंजाब तों बाहर नहीं जाण देवेगी। पर मौजूदा मुख्यमंत्री ने पंजाब दे पाणियां संबंधी पंजाब विधान सभा विच समझौते रद्द करण संबंधी जो बिल पास कीता है। उस विच धारा-5 नू शामिल करके पंजाब तों पहिलां ही गलत तरीके नाल हरियाणा नूं जा रहे पाणी नूं कानूनी मानता दे दिती है। शिरोमणी अकाली दल ने धारा-5 नूं रद्द करन लई दो वार पंजाब विधान सभा विच शोध बिल वी लियांदा जो कि स्पीकर पंजाब विधान सभा ने पेश नहीं होण दित्ता। इस धारा दे शामिल होण नाल कांग्रेस पार्टी ने पंजाब दा केस हमेशा लई कमजोर कर दित्ता है। शिरोमणी अकाली दल इस मुद्दे दा हल होण तक अपना संघर्ष जारी रखेगा।"

इसी प्रकार से उस मैनीफैस्टो में चण्डीगढ़ के बारे में भी लिखा है कि-

"The Shiromani Akali Dal has waged long battles for the inclusion of Chandigarh and other Punjabi speaking areas in Punjab. But, unfortunately, successive Congress Governments at the Centre have always conspired to scuttle this demand. The Congress Party and the Punjab Government led by Captain Amarinder Singh have not raised this issue even once during the past five years. The Shiromani Akali Dal will continue its peaceful and democratic struggle for the fulfillment of Punjab's legitimate demand for the transfer of Chandigarh and other Punjabi speaking areas to Punjab."

अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी उस पार्टी की स्पोर्ट करने पंजाब में गये थे जिस पार्टी के मैनीफैस्टों में इस तरह की पंक्तियां लिखी हुई हैं और यहां सदन में वे आकर एस०वाई०एल० की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस सैक्शन-5 के तहत हरियाणा प्रांत को पानी मिल रहा है उस सैक्शन को डिलीट करने के लिए जिस पार्टी के मुखिया कह रहे हों, क्या उस पार्टी के लिए उन्हें वोट मांगने जाना चाहिए था। यदि उन्हें प्रदेश के हितों की जरा भी सोच होती तो वे वहां वोट मांगने नहीं जाते। लेकिन वे प्रदेश को और सदन को केवल गुमराह करना जानते हैं इससे ज्यादा वे कुछ नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, मैं भी पंजाब के पटियाला शहर में कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की उपस्थिति में गया था। उस समय मैंने जो कहा वे बातें बहुत से अखबारों ने प्रकाशित की

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
हुई हैं वे मैं सदन में पढ़कर सुनाता हूं:-

> "No surrendering of water rights, says Hooda. No compromise on water, says Hooda. हरियाणा के नहरी पानी का हक हम हरगिज लेकर रहेंगे, हुड्डा। तलवार से वार नहीं करूंगा लेकिन पानी की हिस्सेदारी पर अपना हक नहीं छोड़ेंगे, हुड्डा।"

कैप्टन साहब ने मुझे वहां एक तलवार भेंट स्वरूप दी थी उस पर मैंने कहा था कि तलवार से वार नहीं करूंगा लेकिन पानी की हिस्सेदारी पर अपना हक नहीं छोड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये शब्द मैं वहां पूरी जन सभा के सामने कहकर आया था । लेकिन चौटाला साहब ने एक बार भी प्रकाश सिंह बादल को पानी के बारे में नहीं कहा सिर्फ यह कहकर आये कि बादल की पार्टी को वोट दो जो हमें पानी नहीं देना चाहते । अध्यक्ष महोदय, सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में एस०वाई०एल० का जो फैसला दिया है वह इंदिरा गांधी अवार्ड और राजीव-लौंगोवाल के समझौते के आधार पर ही दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी ही एस०वाई०एल० खोदकर पंजाब से अपने हिस्से का पानी लेकर आयेगी इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में भी बहुत से सदस्यों ने जिक्र किया। चौटाला साहब ने कहा कि हमारी सरकार ने एक यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की इस बारे में मैं कहना चाहूंगा इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजली की कमी है और हमारे प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कई लोग 10-10 साल तक मुख्यमंत्री रह गये और 40 साल हरियाणा प्रदेश को बने हुए हो गये कोई बताये कि हमारे प्रदेश का अपना बिजली का उत्पादन आज तक कितना रहा है। हमारी अपनी जनरेशन साढ़े 18 सौ मैगावाट और 2000 मैगावाट बिजली उत्पादन में कुछ बाहरी परियोजनाओं के साथ हमारा हिस्सा है। कुल उपलब्ध बिजली हमारे पास करीब 4000 मैगावाट है और जब पीक समय होता है हमारे पास कुल 2800-2900 मैगावाट बिजली उपलब्ध होती है तथा पूरे प्रदेश में बिजली के लिए हाहाकार मची रहती है और जब जो ये 2 साल गये हैं अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा और पूरे उत्तर भारत पर नजर डाली जाये तो हम देखेंगे कि बिल्कुल अकाल जैसी स्थिति है। आप राजस्थान में जाकर देखिये, चाहे आप उत्तर प्रदेश में जाकर देखिये पिछले दो साल का इतिहास निकाल कर देखिये वहाँ लोगों की फसलें बिजली न होने की वजह से सूख गई लेकिन मेरा दावा है कि हमने हरियाणा में बिजली चाहे किसी भाव खरीदी हो, जहाँ भी फसलें ट्यूबवैल के पानी से होती हैं, हमने एक एकड़ भी हरियाणा के किसान की फसल सूखने नहीं दी। आज इस बाद का नतीजा यह है कि मैं पहली बार कह सकता हूँ कि आज तक गेहूँ के उत्पादन में पंजाब पूरे देश में सबसे ज्यादा रहा है लेकिन अबकी बार पहली बार ऐसा साल आने जा रहा है कि हरियाणा में गेहूँ का उत्पादन पंजाब से भी ज्यादा होगा। इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आंकड़े बोलते हैं 2004-05 में प्रतिदिन की जो ऐवरेज बिजली उपलब्ध थी वो 578 लाख यूनिट प्रतिदिन थी और 2006-07 में 672 लाख यूनिट प्रतिदिन हमने बिजली उपलब्ध करवाई है क्यों, कैसे, कहाँ से करवाई कोई उत्पादन नहीं बढ़ा उत्पादन कोई दो साल में नहीं हो सकता जैसे मैंने कहा। वे लोग गुमराह करते हैं लेकिन हमने शार्ट टर्म पर जो बिजली खरीदी वह बड़े महंगे रेट पर भी खरीदी। 2003-04 में उन्होंने 607 करोड़ रुपये की शार्ट टर्म पर बिजली खरीदी जबकि हमने 2006-07 में 1240.71 करोड़ रुपये की बिजली बाहर से खरीदकर

अपने किसानों को , गाँवों को और शहरों को बिजली दी है। वे लोग कहते हैं कि बिजली की एक यूनिट भी नहीं बढ़ी। बिजली की यूनिट तो बढ़ी हैं। रिकार्ड की बात है जब हमने सत्ता सम्भाली पानीपत के थर्मल प्लांट का लोड फैक्टर कुल 67 परसैंट था वह 67 परसैंट से बढ़कर 80 परसैंट हो गया है। लोड फैक्टर में 13 प्रतिशत की वृद्धि इस सरकार के समय में हुई है। दो वर्षों में हमने पानीपत थर्मल प्लांट से 374 करोड़ यूनिट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया है। ऐफीशिएंसी बढ़ी है जिसका नतीजा यह है कि 374 करोड़ यूनिट अतिरिक्त बिजली पैदा हुई है। बिजली के खर्चे में भी हमारी बढ़ोतरी आप देखो। पिछली सरकार का 5 साल का अगर बिजली का हिसाब लें तो कुल 4095 करोड़ रुपये उनका खर्च आया लेकिन हमारा इन पिछले दो सालों का 3748 करोड़ रुपये बिजली का खर्चा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बिजली कम्पनियों द्वारा 21538 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे ताकि बिजली की पूरी पूर्ती की जाये और इसी प्रकार से जो नये उत्पादन के लिए वे कह रहे थे कि बिजली का नया उत्पादन कितना है। यमुनानगर थर्मल प्लांट की बात की जाये तो यमुनानगर थर्मल प्लांट का इतिहास बहुत पुराना है। यह काम पिछले 20 सालों से अधर में लटका हुआ था और इसका कई बार शिलान्यास पत्थर रखा गया। यहां तक कि फरीदाबाद से भी इसके शिलायान्स के लिए बटन दबाए गये लेकिन इस पर काम कुछ भी नहीं हुआ। इस सरकार के आने के बाद ही जो पत्थर मैं रखकर आया मुझे सदन में यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि नवम्बर में 300 मैगावाट बिजली का उत्पादन यह थर्मल प्लांट शुरू कर देगा। यहां अर्जन सिंह जी बैठे हैं इनको पता है कि वहां पर कितने इंजीनियर लगे हुए हैं।

चौ० अर्जन सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि चौटाला साहब तो पत्थर उठाकर ले जाते थे, पत्थर रखते नहीं थे आपने ही पत्थर रखा है और आप ही इसको पूरा करेंगे और उसी दिन से इतने इंजीनियर लगे हुए हैं कि गिनना मुश्किल है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस थर्मल प्लांट से 300 मेगावाट बिजली फरवरी, 2008 में आ जाएगी। इस प्रोजैक्ट पर 2400 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह प्रोजैक्ट कोई छोटा प्रोजैक्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि बिजली, पानी और कानून-व्यवस्था तीन चीजें अगर नहीं होंगी तो हम प्रदेश का विकास कैसे कर सकते हैं। हमने जो लक्ष्य तय कर रखा है कि हरियाणा प्रदेश को देश का नम्बर वन प्रदेश बनाना है तो उसके लिए हमको ये कार्य करने हैं और तेजी से करने हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि यमुना नगर प्लांट की शुरूआत जुलाई, 1998 में श्री बंसी लाल जी की सरकार ने की और 1999 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आ गई। उन्होंने पांच साल तक इस प्रोजैक्ट पर कुछ काम नहीं किया और पांच साल तक वे सोते रहे। उन्होंने और चाहे जो कुछ भी किया लेकिन इस यमुना नगर के प्लांट के बारे में कुछ नहीं किया। वे यमुना नगर में तो जाते थे लेकिन इस प्लांट से बिजली उत्पादन के लिए उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। छः साल के बाद 30 सितम्बर, 2004 जब अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी हो रही थी तो चुनाव से थोड़े दिन पहले रिलायंस ऐनर्जी को इन्होंने बिजली उत्पादन करने के लिए चिट्ठी दी लेकिन उसके बाद भी छः महीने तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो उसके बाद इसका कार्य शुरू किया गया। चौटाला साहब एक चर्चा कर रहे थे कि सब काण्ट्रैक्टर

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

बदल दिया और वे किसी डोंग फेंग का नाम ले रहे थे। अध्यक्ष महोदय, वे कह रहे थे कि डोंग फेंग जो सब-कण्ट्रैक्टर है उसको बदलने के लिए पहले हमने मना कर दिया तो मैं बताना चाहूंगा कि रिलायंस वाले अपना सब-काण्ट्रैक्टर बदलना चाहते थे और काम रुका हुआ था तो हमने पहले उनका आवेदन रिजैक्ट कर दिया था यह बात ठीक है लेकिन हमने क्यों रिजैक्ट किया ? इसका कारण यह था कि पहले इसके लिए कुछ कण्डीशन्ज़ तय थीं और हमने उनसे यह कहा कि हमारी ये शर्तें वे मानें तो हम सब-काण्ट्रैक्टर बदलने की इजाज़त देंगे। वे कण्डीशन्ज़ क्या थीं वे मैं यहां पर बता देता हूं एक तो indemnification of any litigation की शर्त थी कि कहीं कल को कोई कोर्ट में चला जाए तो हमें कोर्ट में खड़ा करे तो उसके लिए जितना भी खर्चा होगा वह कम्पनी देगी यह हमारी कण्डीशन थी और guarantee for improved Performa parameters and equipments यह हमने कण्डीशन्ज़ रखी थी और समय की भी बात रखी थी। अध्यक्ष महोदय, पहली बार उन्होंने हमारी कण्डीशन्ज़ नहीं मानी तो हमने कहा कि हम सब-कण्टैक्टर को नहीं बदलते। उसके थोड़े दिन बाद हमने जो कण्डीशन्ज़ रखी थीं वे उन पर सहमत हो गये क्योंकि बिजली का प्रोडक्शन जरूरी थी इसलिए हमने उनको कहा कि वे काम करें और उसमें भी जो काण्ट्रैक्ट पीरियड था वह 30 से 33 महीनों का था उसको घटा कर हमने 27 से 30 महीने का किया। तीन महीने का पीरियड ऑफ कन्स्ट्रक्शन हमने घटाया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की चिट्ठी मेरे पास है उसमें लिखा हुआ है कि जो डोंग फेंग कम्पनी है उसने हिसार के लिए भी अपना क्लेम दिया था जो काण्ट्रैक्ट रिलायन्स को दिया गया है कण्डीशन्ज़ उसमें भी लगाई गई थीं। पता नहीं इस डोंग फेंग कम्पनी से इन्हें क्या प्रेम है पता नहीं क्या कारण हैं, ये यहां पर भी डोंग फेंग कम्पनी की सिफारिश कर रहे हैं। यह कम्पनी चाईना की कोई कम्पनी है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा बना है और मैं समझता हूं कि उत्तर भारत की भी शायद हो लेकिन हरियाणा की मैं जरूर कह सकता हूं हरियाणा, पंजाब में सबसे बड़ा प्रोजैक्ट हिसार थर्मल पावर प्लांट का है यह प्लांट 1200 मेगावाट बिजली पैदा करेगा उसका काम भी हमने एलॉट कर दिया है जिस पर कम्पनी की लागत 3775 करोड़ रुपये आएगी। इसका कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है और यह प्रोजैक्ट दिसम्बर, 2009 में पूरा हो जाएगा और इससे बिजली आनी शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक 1500 मेगावाट का थर्मल प्लांट झज्जर में एन०टी०पी०सी० लगा रही है। इस प्रोजैक्ट में दिल्ली और हमारा हरियाणा राज्य बराबर के भागीदार हैं। यह प्रोजैक्ट कम्पलीट होने पर इससे 750 मेगावाट बिजली हमें मिलेगी और 750 मेगावाट बिजली दिल्ली को मिलेगी। इसकी कुल लागत में हमारी इक्विटी आफ पार्टनरशिप है जिसमें 300 करोड़ रुपये की हमारी लागत है और इस प्रोजैक्ट से भी बिजली का उत्पादन कॉमन वैल्थ गेम्ज से पहले-पहले 2010 तक शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह परियोजना कहीं और जा रही थी दिल्ली के साथ छत्तीसगढ़ या कहीं और जा रही थी। हम प्रयास करके इस परियोजना को यहां लेकर आए ताकि हमारी बिजली की समस्या खत्म हो सके। इसके साथ ही झज्जर में एक और 1200 मैगावाट का थर्मल प्लांट हम निजी क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास दरख्वास्तें आ गई हैं और इसमें भी 2010 तक उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके साथ जो गरीब परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके घरों में बिजली के कनैक्शन उपलब्ध करवाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की है। इस पर 82.19 करोड़ रुपए की लागत

आएगी। इस योजना के तहत हम गरीब आदमी के घर तक बिजली पहुंचा सकेंगे। नॉन कन्वैंशनल एनर्जी के लिए हमने प्रयास किए हैं। 705 मैगावाट बिजली उत्पादन के लिए हमने एम०ओ०यू० साईन किए हैं और यहां से भी दो साल में बिजली उत्पादन शुरू होने की सम्भावना है। इस प्रोजैक्ट की कुल लागत 2300 करोड़ रुपए होगी।

अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले बिजली पानी के बारे में कहा है और अब कानून व्यवस्था की बात करता हूं। अगर राज्य में रूल्ज आफ लॉ अच्छे नहीं हैं, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है तो दो साल पहले हरियाणा में जो हालात थे वे दोबारा से आ जाएंगे। उस समय राज्य में कानून व्यवस्था के हालात ठीक नहीं थे और लोग यहां से पलायन करने लग गए थे। स्टेट की कोई अचीवमैंट नहीं थी, किसी भी तरह से इन्वैस्टमैंट नहीं हो रहे थी। लोगों का आत्मविश्वास खोता जा रहा था। उनको यह नहीं पता था कि वे सुबह घर से काम के लिए निकलेंगे और शाम को घर भी वापिस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। उस वक्त किसी की जायदाद सुरक्षित नहीं थी। यहां तक उस वक्त सत्ता पार्टी के विधायक भी सुरक्षित नहीं थे, इस बारे में बड़ी बड़ी कहानियां सुनने को मिलती थी। मैं किसी की निन्दा नहीं करना चाहता हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय, उस समय मैं भी सदन में विपक्षी पार्टी का नेता था। जब मैं गांवों में जाता था लोग मुझे कहते थे कि साहब हमारे विधायक की पिटाई कर दी है। तो मैंने कहा कि भई ऐसे कैसे हो गया, यह तो तुम्हारी कमजोरी है और वह विधायक तुम्हारे दो लाख आदमियों का नुमायंदा है। तुम्हें अपने विधायक की रक्षा करनी चाहिए थी। इस बारे में लोग कहते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं वे तो विधायक को हैलीकाप्टर में ले जाकर पीटते हैं, उनको वहां पर कैसे पकड़ें। (हंसी) अब जैसे सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी ने कहा था कि उस वक्त अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार में अपराधियों को संरक्षण प्राप्त नहीं है। अब जैसा आप सभी को भी पता है कि हरियाणा में नरेन्द्र अरोड़ा हत्याकांड कैथल में हुआ था और हमने उसके हत्यारे को बाहर से पकड़ा है। हमने उस अपराधी को साऊथ अफ्रीका से पकड़ा है। हम आज अपराधियों को दूसरे देशों में भी नहीं छोड़ रहे हैं। जब यह सरकार बनी थी तो मैंने कहा था कि अब हरियाणा अपराधियों की शरणास्थली नहीं है। इसलिए या तो वे अपराधी मुख्यधारा में आ जाएं या वे हरियाणा प्रदेश छोड़ कर चले जाएं। अध्यक्ष महोदय, इस काम में मुझे तो अपने साथियों का सहयोग चाहिए। हमारे विपक्ष के साथी चले गए हैं वे पता नहीं सहयोग देंगे या नहीं देंगे लेकिन जो सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं, वे हमें सहयोग दें तो हम हरियाणा में अपराधियों को रहने नहीं देंगे। इसके साथ ही हमारी दूसरी मुख्य समस्या बे-रोजगारी की है। अब बे-रोजगारी कैसे दूर हो हमें इस बारे में सोचना है। आज खेती पर हमारे बहुत से परिवार निर्भर हैं। आज जोत छोटी-होती जा रही है। अगर दादा के पास 10 एकड़ जमीन थी तो आज पोते के पास आधा एकड़ जमीन ही है। इसलिए खेती पर आज गुजारा नहीं हो सकता है। हमने मैक्सीमम बेरोजगारी को सरकारी नौकरियां देने की कोशिश करी है। सभी को तो सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं। अब हमारे पास बेरोजगारी दूर करने का एक ही रास्ता रह गया है कि हरियाणा प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा और अच्छे-अच्छे उद्योग लगें लेकिन उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। जहां तक उद्योगों का सवाल है या खेती का सवाल है मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपनी परियोजनाओं का जिस हिसाब से हमने नक्शा बनाया हुआ है उसके बाद आने वाले दस सालों में

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

उद्योगों में हम एक प्रतिशत से ज्यादा भूमि नहीं आने देंगे। लेकिन एक प्रतिशत भूमि कितने प्रतिशतों को रोजगार देगी यह हमारा सोचने का विषय है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा को बने हुए चालीस साल हो गये हैं और इन चालीस सालों में कुछ निवेश हरियाणा में कितना हुआ है। वह मैं बताना चाहता हूं। हमारी सरकार आने से पहले का अगर हम हिसाब लगाएं तो इन चालीस सालों में चालीस हजार करोड़ रुपयों का इन्वैस्टमैंट हुआ है जबकि हमारी सरकार के इन दो सालों में अब तक 22 हजार करोड़ रुपये तो विभिन्न परियोजनाओं के तहत लग चुके हैं और 55 हजार करोड़ रुपये पाईप लाईन में हैं। ये भी एक या डेढ़ साल में लग जाएंगे। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले पांच सालों में केवल दस हजार करोड़ रुपये की ही इन्वैस्टमैंट आयी थी। एस०ई०जैड० के 72 प्रस्ताव हमारे पास आये हैं जिसमें से 49 को इन-प्रिंसीपल सैंट्रल गवर्नमैंट की कामर्स मिनिस्ट्री से मंजूरी मिल चुकी है। इनमें 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपयों से ज्यादा का निवेश होगा और अगर एक एस०ई०जैड० कामयाब होता है तो वह अकेला ही बीस लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार से खरखौदा, फरीदाबाद, रोहतक और यमुनानगर में हम आई०एम०टी० मानेसर जैसे चार इंडस्ट्रियल टाउंज बनाना चाहते हैं। इसके अलावा के०एम०पी० एक्सप्रैस हाई वे के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि यह दो हजार करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट होगा। इस पर काम शुरू हो गया है। इसी तरह से इंडियन आयल कौरपोरेशन के द्वारा पानीपत में विकसित पैट्रो हब में 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है। इससे 50 हजार आदमियों को रोजगार मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जो अपनी श्रम नीति लेकर आया है। इस बारे में आप सबको मालूम ही है। श्रम मंत्री यहां बैठे हैं मैं इसके लिए इनको हार्दिक बधाई देता हूं कि ये श्रम नीति लेकर आए हैं जबकि कोई दूसरा प्रदेश आज तक ऐसी श्रम नीति लेकर नहीं आया है। हमने मिनीमम वेजिज 3510 रुपये किए हैं जोकि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हैं। यह गरीब आदमी के लिए हैं इससे तीन हजार करोड़ रुपये का लाभ हरियाणा के मजदूरों को होगा। पहले ये मिनीमम वेजिज 2485 रुपये थे जबकि हमने नान स्किल्ज लेबर के लिए 3510 रुपये किए हैं। 27 लाख मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद शिक्षा की बात आती है। शिक्षा भी हमारे विकास के लिए जरूरी है। इसके लिए भी हमारी सरकार ने खास ध्यान दिया है। इसके बजट में काफी बढ़ौत्तरी की गयी है। आंकड़े दर्शाते हैं कि 2004-05 में शिक्षा पर 1622.89 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जबकि 2007-08 में 2761.42 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए प्रस्तावित हैं। इसी तरह से महिलाओं की शिक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। उत्तर भारत में सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय की खानपुर में स्थापना की गयी है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े और हमारे बच्चे ऊपर जाएं, अच्छी तरह से पढ़ें। विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी दीन बन्धू सर छोटू राम के नाम से मुरथल में विश्वविद्यालय बनाया गया है और जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी चाहे जितनी भी डिमांडज़ थी, उतना पैसा उनको दिया गया है। इसी प्रकार से राजीव गांधी एजूकेशन सिटी की स्थापना की गई है। उसके लिए जमीन ऐक्वायर हो गई है। वहां पर इंटरनैशनल स्टैंडर्ड की पढाई होगी ताकि हरियाणा प्रदेश के बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकें। वहां पर जितने दाखिले होंगे उनमें से 25 प्रतिशत दाखिले हरियाणा के बच्चों के होंगे और उनमें से भी पहले पांच फीसदी बच्चों को फुल फी कंसैशन दिया जाएगा और अगले दस फीसदी बच्चों को 50 प्रतिशत फी कंसैशन दिया जाएगा व लास्ट दस फीसदी बच्चों को

25 फीसदी की कंसैशन दिया जाएगा ताकि जो गरीब परिवारों के होशियार बच्चे हैं वे पढ़ाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकें। हमने एजुसैट नैटवर्क शुरू किया है। यह एशिया में सबसे बड़ा नैटवर्क होगा। यह हम शिक्षा के क्षेत्र में लगाने जा रहे हैं। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने में हरियाणा पहला प्रदेश है। हमने स्कूलों में सेमैस्टर सिस्टम शुरू किया है और उससे बच्चों की हाजिरी बढ़ गई है। इस प्रकार से 14 हजार नये अध्यापक हम भर्ती करने जा रहे हैं और उनमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है और उनमें ग्रामीण युवाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। समाज कल्याण के क्षेत्र में हमने कार्य किया है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के बजट में हमने वृद्धि की है। 2004-05 में इसके लिए कुल 40.94 लाख का बजट था उसे बढ़ाकर 63.86 लाख किया गया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भी बजट में हमने भारी वृद्धि की है। 2003-04 में इनका बजट कुल 47.40 करोड़ था जिसे 2006-07 में बढ़ाकर 137.93 करोड़ किया है। इन वर्गों के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। अपंगों के लिए पैंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमास की है। लाडली स्कीम के तहत लड़कियों के माता पिता को 500 रुपये प्रति मास के हिसाब से पैंशन योजना लागू की है। बौनों और किन्नरों को 300 रुपये प्रति मास की दर से पैंशन दी है। विधवाओं की पैंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये प्रति मास की है। शतप्रतिशत विकलांग एवं अंगहीनों की पैंशन 200 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति मास की है। अनुसूचित जातियों के लिए मकान की गारंटी की राशि दस हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की है। बेरोजगार नवयुवकों के भत्तों में वृद्धि की है। इंदिरा गांधी विवाह सामूहिक योजना में 15 हजार रुपये के कन्यादान का हमने आबंटन किया है। 85 वें संविधान संशोधन को हमने लागू किया है। तकनीकी संस्थाओं में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के नाम से संपत्ति पंजीकरण में स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत छूट महिलाओं के लिए की है। महिलाओं के लिए बिजली के बिल में 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट की है यदि मकान और बिल उनके नाम हो। 8 लाख से अधिक अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए स्कीम लेकर आए हैं जिसको कि पूरा भारत देख रहा है। ऐसे 8 लाख से अधिक परिवार हैं जिनको पीने के पानी की सुविधा देने के लिए हमने फैसला किया है उसमें सबको पानी का कनैक्शन पहुंचाएंगे। स्वजल योजना में 200 लीटर की एक पानी की टंकी और एक टूटी भी देंगे। इस परियोजना पर 350 करोड़ रुपया खर्च लगेगा। आप सबको मालूम है कि रक्षा बंधन के त्यौहार के अवसर पर सभी महिलाओं को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है यह एक साल के लिए नहीं थी बल्कि हर साल के लिए है। गांव में खेलों के लिए खेल के मैदान की सुविधा दी है। पहले जिस गांव में जाते थे तो युवाओं की इच्छा होती थी कि हमारे पास खेलने का स्थान हो। हमारे गांवों में इसके लिए बहुत पोटेंशियल है इसलिए 40 करोड़ रुपये की लागत से 135 गांवों में ग्रामीण खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और स्पोर्टस के जो आउटस्टैण्डिंग स्पोर्टसमैन हैं जो मैडल लेकर आये हैं उनके गांवों को आदर्श गांव बनाया जायेगा और इस प्रकार कुल 53 गांवों को आदर्श गांव बनाने का फैसला सरकार ने किया है। नगर पालिका, पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषदों के सभी नुमायन्दों को पहली बार 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का मानदेय इस सरकार ने दिया है। जो नम्बरदार और चौकीदार हैं उनको 500 रुपये से 1000 रुपये का मानदेय दिया गया है। चौकीदार को लाठी और बैटरी भी दी गई है। बी०पी०एल० के कार्डों के

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
बारे में बहुत आम शिकायतें आई हैं और बहुत सारे सदस्यों ने सुबह बोलते हुए इस बारे में अपनी बात रखी है। अब सरकार ने फैसला किया है कि बी०पी०एल० के कार्डों को बनाने के लिए रि-सर्वे किया जायेगा और यह प्रोसैस तीन महीने के अन्दर कम्पलीट हो जायेगा ताकि सभी जरूरतमंदों को इसका लाभ पहुंच सके। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से राज्य पाल महोदय के अभिभाषण में अनेकों कामों का उल्लेख किया गया है। बहुत सारे विभाग हैं जिनकी सभी की चर्चा यहां पर नहीं की जा सकती। ऐसा अछूता कोई विभाग नहीं रहा है जिसके लिए हम कोई नई नीति लेकर नहीं आये हों और हरियाणा को विकास की ओर नहीं चलाया हो क्योंकि पहले हरियाणा प्रदेश का विकास रुका हुआ था लेकिन अब तेजी से विकास शुरू हो गया है। गांवों में विकास हो रहा है, शहरों में भी विकास हो रहा है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से एक निवेदन है कि आप सभी का सहयोग रहना चाहिए आप सभी के सहयोग की आज सरकार को जरुरत है। किसी भी बात के लिए आप सहयोग करेंगे उसी से हरियाणा का विकास और ज्यादा होगा। आज जो सदस्य चुनकर आये हैं पता नहीं कल आयें या नहीं अगर आप सभी का सहयोग रहेगा तो इसी टर्म के दौरान हरियाणा को देश का नम्बर एक प्रदेश बना दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker : Question is—

"That an address be presented to the Governor in the following terms :—

That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 9th March, 2007 at 2.00 P.M.

The motion was carried, unanimously.

वर्ष 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 2006-07.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2006-07.

एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, I.G. Sher Singh, Chairperson Committee on Estimates will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2006-07.

I.G. Sher Singh (Chairperson, Committee on Estimates) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2006-07.

वर्ष 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members now discussion and voting on the Demands for Supplementary Estimates (Second Instalment) 2006-07 will take place. As per the past practice and in order to save the time of the House, the demands on the order paper No. 1 to 3, 5, 7 to 17 and 20 to 25) will be deemed to have been read and moved. The Hon'ble Members can discuss any demand and they are requested to indicate the demand number on which thay wish to raise discussion.

That a Supplementary sum not exceedig **Rs. 27,38,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 1-Vidhan Sabha.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 10,53,15,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No.2- General Administration.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 9,11,04,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 3- Home.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2,38,87,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No.5- Excise & Taxation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 3,72,28,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No.7- Other Administrative Services.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 48,47,43,000/-** for revenue expenditure and **Rs.21,87,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 8- Building & Roads.**

[Shri Birender Singh]

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 22,95,31,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 9- Education.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 34,66,65,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 10- Medical & Public Health.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 31,08,27,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 11- Urban Development.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs.1,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 12- Labour & Employment.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 188,67,02,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 13- Social Welfare and Rehabilitation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 8,38,98,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 14- Food & Supplies.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2161,14,82,000/-** for revenue expenditure and **Rs.367,40,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 15- Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 6,25,39,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 4,11,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 16-Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 17,32,27,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 17- Agriculture.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,28,30,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 20- Forests.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 44,68,25,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No.21- Community Development.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 5,42,82,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 3,49,98,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 22-Co-operation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 11,03,68,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 1,91,15,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 23-Transport.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 3,00,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 24- Tourism.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 6,33,90,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 25- Loans & Advances by State Government.**

प्रो० छत्रपाल सिंह (घिराय) : स्पीकर सर, मैं डिमांड संख्या-15 पर बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2006 के अंदर प्लान और नोन प्लान में सिंचाई विभाग का कितना बजट था और अब जो हमने 19-9-2006 में सदन के अंदर इनके सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स पास करवाये थे उनके फीगर्ज क्या हैं तथा अब कितने सप्लीमैंटरी एस्टीमेंट्स इसमें इनक्लूड किये गए हैं। (विघ्न)

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के बारे में तो माननीय साथी को बता सकता हूं लेकिन माननीय साथी जो जानकारी चाहते हैं उसके लिए वे अलग से लिखकर दे दें उनको जवाब भिजवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर साहब, क्या आपको बजट एस्टीमेट्स की कापी नहीं मिली है। बजट एस्टीमेट्स की कोपी में ये सारी इन्फार्मेशन दी हुई है।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस कोपी को देखकर ही बता रहा हूं मेरे पास जानकारी है मैं सदन के अंदर इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि हमारा 2006-07 का जो टोटल बजट है वह 19154.24 करोड़ रुपये का बनता है। 103.18 करोड़ रुपये के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स हमने विधान सभा के अंदर 19-9-2006 को पास किए हैं और अब तकरीबन 3020.11 करोड़ रुपये के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स पास होने के लिए आये हैं इसमें जो मेजर एक्सैस सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स हैं वे सिंचाई विभाग के 2022 करोड़ रुपये के हैं। इसमें मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस समय विभाग प्लानिंग करते हैं जिसमें उनका पूरे साल का बजट या दूसरे एस्टीमेट्स होते हैं उनके अंदर इतनी भारी फल्कच्यूेशन कैसे आ जाता है। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि इतना अधिक एक्सैस सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स आने के बाद भी वे इनको वहन करते हैं और विधान सभा इसको पास करके देती है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यदि विभाग दुरुस्त तरीके से अपनी प्लानिंग करके अपने एस्टीमेट्स बनायें और विधान सभा के बजट के अंदर टोटल एस्टीमेटस पहले से कोरपोरेट हो जाये तो एक्सैस सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स बहुत कम मात्रा में आयेंगे। यह जो 2022 करोड़ रुपये के एक्सैस एस्टीमेट्स आये हैं ये पिछली सरकार के निकम्मेपन के कारण आये हैं। इस पर वित्त मंत्री जी पूरी तरह से रोशनी डाल पायेंगे। ये टोटल एक्सैस एस्टीमेट्स पास होने के बाद टोटल बजट 22277.53 करोड़ रुपये का बन जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस ईशू के ऊपर विभाग सीरियसली गौर करें। अब जो ये अनुपूरक मांगे आई हैं इनको हर मैंबर पढ़ नहीं पाते हैं। क्या इनको कम करने के लिए विभागों के पास अपनी कार्य प्रणाली के अंदर कोई बदलाव लाने की योजना है, क्या विभाग इस बात पर विचार करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स की यह सैकिण्ड इंस्टालमैंट है जिसमें हमने 3020.11 करोड़ रुपये की विधान सभा से अनुमति लेनी है और इससे पहले इसकी पहली इनस्टालमैंट थी जिसमें हमने 103 करोड़ रुपये की अनुमति ली थी। 3020 करोड़ में से इसमें 2022 करोड़ रुपये सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस में इनक्लूड किया गया है। ये 2022 करोड़ रुपये पॉवर यूटीलिटीज के 2003-2004 के अन्दर ऋण के तौर पर दिये गये थे हमारे से पहले जो उस समय की सरकार थी उन्होंने पॉवर यूटीलिटीज को पैसा बॉन्ड की शक्ल में दिया था वह 2004-05 के बजट में रिफ्लैक्ट होना चाहिए था लेकिन वह नहीं हुआ। उसके बाद ये अब सी०ए०जी० की रिपोर्ट आई उसमें यह प्वाईंट आऊट किया गया और हमने अपने बजट में अब उसको रिफ्लैक्ट किया है। हालांकि हमारी इसमें कोई भी देनदारी नहीं थी यह पिछली सरकार के समय में हुआ था लेकिन पिछले साल में क्योंकि यह विधिवत तरीके से रिफलैक्ट नहीं किया गया इसलिए हमने इसको सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स के माध्यम से सदन के सामने रखा है और उक्त राशि की सब्सिडी उक्त ऋण के विरुद्ध बुक ट्रांसफर द्वारा समायोजित की जाएगी। इस प्रकार वित्तीय आदान-प्रदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी की जो दूसरी मांगें हैं उसमें जैसे हमने पॉवर सैक्टर में जो नये हमारे पॉवर प्रोजैक्ट शुरू हुए हैं उनमें 367 करोड़ रुपये इक्विटी के तौर पर लगाया है। इसी प्रकार से ग्रांट-इन-एड के तौर पर भी हमने हुडको को 30 करोड़ रुपये दिये हैं और हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट प्रोग्राम के लिए 33 करोड़ रुपये और जो एन०सी०आर० में मैट्रो बन रही है उसमें हमारी स्टेट का जो शेयर है 30 करोड़ रुपये हमने उसके लिए दिया है जो बाद में हुडा देगा। इस प्रकार से यह 800 करोड़ रुपये के करीब राशि ऐसी है

जो हमें इस वार्षिक बजट से अलग से जुटानी पड़ी और जिसको पास करने के लिए हम इस सदन के सामने आए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस सप्लीमेंटरी एस्टीमेट को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker : Now the demands will be put to the vote of the house.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceedig **Rs. 27,38,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 1-Vidhan Sabha.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 10,53, 15,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No.2- General Administration.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 9,11,04,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 3- Home.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is:—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2,38,87,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No.5- Excise & Taxation.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is:—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 3,72,28,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No.7- Other Administrative Services.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 48,47,43,000/-** for revenue expenditure and **Rs.21,87,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 8- Buildings & Roads.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 22,95,31,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 9- Education.**

[Mr. Speaker]

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 34,66,65,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 10- Medical & Public Health.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 31,08,27,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 11- Urban Development.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 12- Labour & Employment.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 188,67,02,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 13- Social Welfare and Rehabilitation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 8,38,98,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 14- Food & Suplies.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2161,14,82,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 367,40,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 15- Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 6,25,39,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 4,11,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 16-Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 17,32,27,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 17- Agriculture.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is:—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,28,30,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 20- Forests.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 44,68,25,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 21- Community Development.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 5,42,82,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 3,49,98,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 22-Co-operation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 11,03,68,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 1,91,15,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 23-Transport.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 3,00,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 24- Tourism.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 6,33,90,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 25- Loans & Advances by State Government.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. tommorrow, the 15th March, 2007.

*13.25 Hours (The Sabha *then adjourned till 9.30 A.M. tommorrow, the 15th March, 2007.)